{ विश्वास वही रफ्तार नई }

बालाघाट
मंगलवार 14 जुलाई 2026
आषाढ कृष्ण 13 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 16, अंक 290
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

सेंसेक्स -
निफ्टी -
सोना -
चांदी -
डॉलर -

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

खास खबर

खान सर को मिली जमानत

पटना। पटना की एक सिविल कोर्ट ने सोमवार को फैसल खान उर्फ खान सर और उनके 2 बॉडी गार्ड्स को अग्रिम जमानत दे दी। यह केस शहर के मुसल्लहपुर इलाके में 2 कोचिंग संस्थानों के बीच हुई झड़प से जुड़ा है। इससे पहले, जज की अनुपस्थिति की वजह से सुनवाई 10 जुलाई से 13 जुलाई तक के लिए टाल दी गई थी। यह केस 2 जून की एक घटना से जुड़ा है, जब 15 से 20 लोगों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के परिसर में तोडफ़ोड़ कर दिया और खान सर द्वारा चलाए जा रहे कोचिंग संस्थान पर पत्थर भी फेंके। हालांकि अगले ही दिन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें संस्थान से जुड़े 2 बॉडी गार्ड कथित तौर पर गोली चलाते हुए दिख रहे थे। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को भी हिरासत में ले लिया।

पीएम के दौरे वाले दिन ब्लास्ट की धमकी

मोहाली। पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले मोहाली के 6 स्कूलों को सुबह-सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद स्कूलों को बंद करा दिया गया। ईमेल में लिखा- आज स्कूल निशाने पर हैं, इसके बाद 17 जुलाई को बम धमाके होंगे। ईमेल में मोहाली के स्कूलों, मेयर कार्यालय और जालंधर-चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को निशाना बनाने का दावा किया गया है। साथ ही पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का समर्थन करते हुए उन्हें अपना भाई बताया गया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि भास्कर इस ईमेल की पुष्टी नहीं करता है। फेज-6 स्थित शिवालिक पब्लिक स्कूल को सुबह करीब 9 बजे ऑफिशियल ईमेल पर यह धमकी भरा मैसेज आया। शिवालिक के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि उस वक्त दूसरा पीरियड चल रहा था, जब यह मेल आई। अब टीमें जांच कर रही हैं। बच्चों को ले जाने के लिए हमने परिनजों को मैसेज भेज दिया है।

दो बसों की टक्कर; 5 की मौत, 42 घायल

मदुरै। तमिलनाडु के मदुरै जिले में सोमवार सुबह दो बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 42 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, चेन्नई से मार्थांडम जा रही प्राइवेट बस कोट्टामपट्टी के वंदिनगर के पास फोरलेन हाईवे पर अचानक बेकाबू हो गई। बस डिवाइडर पार कर सामने वाली लेन में पहुंच गई और मदुरै से तिरुचिरापल्ली जा रही सरकारी बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्राइवेट बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि सरकारी बस पलट गई।

कुछ ना कहना

मप्र में प्रमोशन रिजर्वेशन केस में बड़ा फैसला, हाई कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से किया इनकार, जस्टिस विवेक रूसिया सुनवाई से अलग

प्रमोशन में आरक्षण बैन जारी, अब स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई

भोपाल/जबलपुर। मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर वर्षों से चल रहे बहुचर्चित कानूनी विवाद में सोमवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। जबलपुर हाईकोर्ट ने फिलहाल प्रमोशन प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने या किसी भी पक्ष को अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एक्टिंग चीफ जस्टिस) विवेक रूसिया ने संभावित हितों के टकराव का हवाला देते हुए स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग (रिक्यूज) कर लिया। अब इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के लिए विशेष (स्पेशल) बेंच गठित की जाएगी, जो इसी सप्ताह अंतिम बहस शुरू कर सकती है। यह मामला प्रदेश के लाखों सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है। लंबे समय से पदोन्नतियां अटकी हुई हैं और सभी की निगाहें हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रमोशन प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने और अंतरिम राहत देने की मांग की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने तत्काल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई स्पेशल बेंच करेगी और वही अंतिम निर्णय देगी। अदालत के इस रुख का अर्थ यह है कि फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण विवाद का कोई तत्काल समाधान नहीं निकलेगा और कर्मचारियों को अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा।

एक-दो दिन में बनेगी स्पेशल बेंच

हाईकोर्ट ने संकेत दिया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जल्द ही इस मामले के लिए स्पेशल बेंच का गठन करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि एक-दो दिन में नई बेंच का गठन हो जाएगा और इसी सप्ताह अंतिम बहस शुरू हो सकती है। नई बेंच प्रमोशन में आरक्षण की संवैधानिक वैधता, राज्य सरकार की नीति, लंबित पदोन्नतियों और सभी संबंधित कानूनी पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई करेगी।

सपाक्स ने उठाया प्रमोशन रोकने का मुद्दा

सपाक्स (सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग कर्मचारी संस्था) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने अदालत से कहा कि पिछली सुनवाई में सरकार ने मौखिक आश्वासन दिया था कि अंतिम निर्णय आने तक नई प्रमोशन नीति के तहत पदोन्नति नहीं की जाएगी। उन्होंने अदालत से कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो पिछली सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की जा सकती है, जिससे सरकार के मौखिक आश्वासन की पुष्टि हो सके। सपाक्स ने विधानसभा सचिवालय में हाल ही में जारी 23 प्रमोशन आदेशों पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब किसी भी विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए।

एक्टिंग चीफ जस्टिस ने खुद को किया अलग

सुनवाई के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम तब हुआ जब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया ने स्वयं को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। उन्होंने अदालत को बताया कि पहले वे आर.बी. राय प्रकरण में अधिवक्ता के रूप में पक्ष रख चुके हैं। वर्तमान मामला भी उसी फैसले के आधार पर आगे बढ़ रहा है। निष्पक्षता बनाए रखने और किसी भी संभावित हितों के टकराव से बचने के लिए उन्होंने सुनवाई से अलग होने का निर्णय लिया। इसके बाद अब नए सिरे से स्पेशल बेंच गठित होगी।

पिछली सुनवाई में सरकार ने मांगा था समय

पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जाह्नवी पंडित ने अदालत को बताया था कि महाधिवक्ता प्रशांत सिंह स्वयं सरकार का पक्ष रखना चाहते हैं। उनकी अनुपलब्धता के कारण समय देने का अनुरोध किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया था। सोमवार को सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह तथा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन उपस्थित रहे।

अजाक्स की दलील

दूसरी ओर अजाक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने अदालत में तर्क दिया कि रिकॉर्ड में प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने का कोई लिखित आदेश मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर सरकार प्रमोशन प्रक्रिया नहीं रोक सकती। इसलिए पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने तत्काल अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।

अदालत पहले भी जता चुकी है चिंता

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और इसका जल्द अंतिम निराकरण होना चाहिए। अदालत ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा था कि नई प्रमोशन नीति लागू नहीं करने संबंधी मौखिक आश्वासन का क्या आधार है। सरकार का जवाब आने के बाद भी सोमवार को अदालत ने रोक हटाने से इनकार कर दिया।

हिंदू राष्ट्र पर बाबा रामदेव के बयान से सियासी घमासान, विपक्ष ने उठाए सवाल

नई दिल्ली । योग गुरु बाबा रामदेव के हिंदू राष्ट्र संबंधी बयान को लेकर देश में नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बाबा रामदेव ने कहा कि हिंदू राष्ट्र से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज एक ही थे और मुसलमानों तथा ईसाइयों को भी किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी के पूर्वज सनातनी आर्यवैदिक परंपरा से जुड़े थे।

बाबा रामदेव के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सभी को

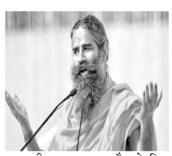

सनातनी माना जा रहा है, तो फिर समाज में इतने विभाजन क्यों पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सभी एक ही परंपरा से जुड़े हैं, तो सभी को समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि भारत का शासन संविधान से चलता है और देश एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की बहस संविधान की मर्यादा के भीतर होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने भी इस बयान की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि देश के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विषय उठाए जा रहे हैं। बाबा रामदेव के बयान ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर राजनीतिक विमर्श को तेज कर दिया है। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर बयानबाजी जारी है, जबकि यह विषय एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है।

काशी, मथुरा, संभल में सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता मंजूर नहीं

हिंदू-मुस्लिम पक्ष ने कहा- बातचीत से समाधान नहीं, केस लडक़र फैसला चाहते हैं

वाराणसी/मथुरा/संभल। यूपी के तीन मंदिर-मस्जिद विवादों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ये तीनों विवाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समाधान समारोह 2026 पहल के तहत लेटर भेजकर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था और दोनों पक्षों से सहमति मांगी थी। हालांकि, किसी भी पक्ष ने इसके लिए सहमति नहीं दी। कोर्ट ने यह लेटर कब भेजा था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों पक्षों ने कहा है कि वे अदालत में ही केस लडक़र फैसला चाहते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21 से 23 अगस्त तक समाधान समारोह के तहत विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत के जरिए हल निकालना है।

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां मौजूद प्राचीन विश्वेश्वर (काशी विश्वनाथ) मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई थी। इस मामले में वाराणसी जिला अदालत, इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पूजा के अधिकार, एएसआई सर्वे, वजूखाना क्षेत्र और धार्मिक स्थल अधिनियम से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोडक़र बनाई गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमीन के स्वामित्व, सर्वे और 1968 के समझौते की वैधता से जुड़े कई मुकदमे लंबित हैं।

शाही जामा मस्जिद विवाद

संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह प्राचीन हरिहर (हरि) मंदिर को तोडक़र बनाई गई थी। चंदौसी सिविल कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सर्वे, उसकी वैधता और संबंधित कानूनी याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई होगी और दोनों पक्ष अपने-अपने सबूत व दलीलें पेश करेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों ने इनकार किया है।

यात्री की मौत पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, रेलवे को दिया कार्रवाई का आदेश, कहा

सब्जियों की तरह टीटीई बेचते हैं बर्थ

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (टीटीई) ट्रेनों में खाली बर्थ को बाजार में सब्जियों की तरह बेचते हैं। कोर्ट ने देश के सभी रेलवे जोन के जनरल मैनेजरों को निर्देश दिया कि ऐसे दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अदालत ने यह टिप्पणी एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें नशीला पदार्थ देकर लूट का शिकार बने एक यात्री की मौत हो गई थी। दरअसल, फरवरी 2009 में न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह जा रहे दो यात्रियों ने बिना रिजर्वेशन टिकट के साथ तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस में सफर शुरू किया था। दोनों ने एक टीटीई को पैसे देकर खाली बर्थ हासिल की। बाद में दो अपराधियों ने उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर उनके कीमती सामान लूट लिए। उनमें से एक यात्री पहले से ही कई बीमारियों से पीड़ित था। नशीले पदार्थ के असर से उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा यात्री बच गया था।

मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज

शाह-यादव से जुड़ी घटनाओं से हलचल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कैबिनेट विस्तार या बड़े राजनीतिक फैसलों का अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि उनकी रणनीतिक योजनाएं अत्यंत गोपनीय रहती हैं। हालांकि, हाल की दो घटनाओं ने मानसून सत्र से पहले संभावित कैबिनेट फेरबदल की अटकलों को हवा दी है।

पहली घटना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के निवर्तमान डायरेक्टर तपन डेका के सम्मान में आयोजित डिनर है। एक दुर्लभ सार्वजनिक कदम उठाकर केंद्रीय मंत्री शाह ने एक्स पर डेका की प्रशंसा करते हुए कार्यक्रम की तस्वीरें साझा कीं। इससे अटकलें हैं कि डेका को सेवानिवृत्ति के बाद जम्मू-कश्मीर से जुड़ी कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना बढ़ती है।

दूसरी अहम घटना केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अचानक हुए प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी है, जिसमें उनके चार अहम निजी सहयोगियों को हटाया गया। केंद्रीय मंत्री यादव को बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार और संगठन से जुड़े अहम व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिनका प्रभाव उनकी मंत्री पद की जिम्मेदारियों से कहीं अधिक है। इस अप्रत्याशित कदम ने राजनीतिक और नौकरशाही हलकों में हलचल मचा दी है। विपक्षी कांग्रेस ने, पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के नेतृत्व में, सरकार पर कुशासन और यादव के मंत्रालय में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। यह घटना किसी बड़े बदलाव का संकेत है या मात्र एक प्रशासनिक कदम, यह देखना बाकी है, लेकिन इससे यादव को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं।

हालांकि, सूत्रों का कहना है कि संसद के मॉनसून सत्र (20 जुलाई से पहले) में कैबिनेट में फेरबदल की संभावना कम है। सरकार का मुख्य ध्यान विधायी कार्यों पर है और प्रधानमंत्री का शेड्यूल भी बहुत व्यस्त है। 20 जुलाई से पहले विस्तार होने पर नए मंत्रियों के पास सत्र की तैयारी के लिए कम समय होगा।

गुजरात में फैला चांदीपुरा वायरस

गोधरा। गुजरात में संक्रमण से एक महीने में अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से तीन बच्चे चांदीपुरा वायरस से संक्रमित थे। अन्य 9 बच्चों की मौत भी इसी वायरस से होने की आशंका है। हालांकि, इनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। संक्रमण के मामले गांधीनगर, साबरकांठा, खेड़ा, अरावली और पंचमहल जिलों में सामने आए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने इस स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि इस घातक वायरस के संक्रमण के कारण अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 2 बच्चों की मौत गोधरा और राजस्थान के एक बच्चे की मौत हिम्मतनगर में हुई। प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में चांदीपुरा के संदिग्ध लक्षणों वाले बच्चों की कुल 6 मौतें दर्ज की गई हैं। जबकि तीन बच्चों की मौत गोधरा के सिविल अस्पताल में हुई। इनमें दो बच्चों की मौत दो दिन पहने यानी कि 11 जुलाई को हुई।

पीएम-सीएम को हटाने पर विधेयक में बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद पद से हटाने वाले बिल में बदलाव किया जा सकता है। संयुक्त संसदीय समिति ने विधेयक में कई महत्वपूर्ण संशोधन सुझाए हैं। जेपीसी ने 130वें संशोधन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। जेपीसी ने सनसेट क्लॉज (एक निश्चित समय सीमा के बाद कानून का खत्म होना) की सिफारिश की है। जेपीसी ने अपने सुझाव में कहा है कि जेल से सरकार नहीं चलनी चाहिए। गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक हिरासत में पीएम, सीएम और मंत्री रहते हैं तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए कुर्सी जाने के बजाए अस्थायी तौर पर पद से हटाए जाने की सिफारिश की गई है। इसका मकसद है कि जो लोग बाद में निर्दोष पाए जाएं,उन्हें हमेशा के लिए पद से न हटाया जाए।

संसदीय समिति ने अपने संशोधन में कहा कि अगर तय समय के भीतर मंत्री बरी हो जाते हैं या छूट जाते हैं। इसके बाद फिर अभियोजन पक्ष कार्रवाई नहीं करता है तो वे फिर से अपने पद पर बहाल हो सकते हैं। साथ ही, समिति ने गंभीर आपराधिक अपराधों को परिभाषित करके बिल के दायरे को भी सीमित करने का सुझाव दिए हैं। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की। जेपीसी ने कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई अहम संशोधन सुझाए गए। स्थायी रूप से पद से हटाने के बजाय अस्थायी तौर पर पद से हटाने का प्रावधान करने की सिफारिश की गई। समिति ने माना है कि यदि तय समय के भीतर मंत्री बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं या अभियोजन पक्ष कार्रवाई नहीं करता है, तो वे फिर से अपने पद पर बहाल हो सकते हैं।

पुलिस हिरासत में होने के 31 वें दिन चली जाएगी कुर्सी

समिति ने कहा है कि जिन अपराधों में पांच साल या उससे अधिक की सजा संभव है, केवल उन्हीं के आरोपों में हिरासत में जाने पर कुर्सी जाएगी। मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक या विशेष अदालतें भी बनाई जा सकती हैं। विधेयक के वर्तमान प्रावधान के अनुसार तीस दिन की हिरासत के अगले ही दिन यानी 31वें दिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल या उपराज्यपाल को कहेंगे कि संबंधित मंत्री को हटा दिया जाए। जेपीसी ने कहा कि हिरासत में होने के 31 वें दिन पीएम, सीपीएम मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें मंत्रिपरिषद से हटा मान लिया जाएगा। हालांकि, सदस्यता बनी रहेगी, इस संशोधन से उनकी सांसद/विधायक सदस्यता नहीं जाएगी। इस तरह वे केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का कार्यकारी पद छोड़ेंगे। जब तक जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं होते, वे चुने हुए जनप्रतिनिधि बने रहेंगे,

पुलिस हिरासत से छुटने के बाद घर वापसी का प्लान

समिति ने जनप्रतिनिधियों को स्थायी रूप से पद से हटाने के बजाय अस्थायी तौर पर पद से हटाने का प्रावधान करने की सिफारिश की गई। इस तरह पद पर वापसी का प्रावधान हिरासत से छूटने के बाद रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट की गो हत्या बैन के आदेश पर रोक, कहा- इसमें सुधार की जरूरत, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था- ये इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को बकरीद या किसी भी दिन राज्य में गाय-बछड़ों के वध पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में सुधार की जरूरत है।

राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के 27 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि जब कानून तय श्रेणी की गायों के वध की अनुमति देता है, और उसके लिए निर्धारित स्थान भी तय हैं, तब अदालत का ऐसा

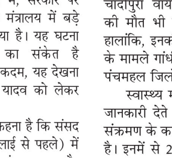

निर्देश कानून के प्रावधानों के विपरीत है। इसे कायम नहीं रखा जा सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने आज इस मामले में नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

मद्रास हाईकोर्ट ने कुर्बानी रोकने को कहा था

मद्रास हाईकोर्ट ने 27 मई को (बकरीद से एक दिन पहले) तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य में बकरीद या किसी अन्य दिन गाय और बछड़ों की कुर्बानी न हो। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की बेंच ने कहा कि संविधान सभा की बहस में कहा गया था कि गाय भारत में पूजनीय मानी जाती है। भगवान कृष्ण के समय से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। कई मुस्लिम शासकों ने भी गोहत्या पर रोक लगाई थी। महात्मा गांधी भी गो संरक्षण को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे।

जनहित में रूपझर पुलिस की सराहनीय पहल

वर्षा ऋतु में पहाड़ी मार्ग से झाड़ियां और गिरे पेड़ हटाकर आवागमन किया सुरक्षित

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। वर्षा ऋतु के दौरान सड़क सुरक्षा एवं आमजन की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए थाना रूपझर पुलिस ने एक सराहनीय जनहितकारी अभियान चलाया। निरीक्षक कामेश धूमकेती द्वारा थाना रूपझर का प्रभार ग्रहण करने के बाद जनसेवा, यातायात सुरक्षा एवं दुर्घटना रोकथाम को लेकर विशेष पहल की जा रही है। इसी क्रम में 12 जुलाई को थाना रूपझर पुलिस के अधिकारियों एवं जवानों ने चिखलाझोड़ी से सोनेवानी बंजारी के घने जंगल एवं पहाड़ी मार्ग पर श्रमदान कर सड़क किनारे उगी घनी झाड़ियों की सफाई की तथा वर्षा के कारण सड़क पर गिरे बड़े-बड़े पेड़ों एवं उनकी शाखाओं को हटाकर मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित एवं सुगम बनाया।

उल्लेखनीय है कि बैहर बालाघाट मार्ग जिले के सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यस्त मार्गों में से एक है। यह मार्ग घने जंगलों, पहाड़ियों तथा अनेक तीव्र एवं अंधे मोड़ों से होकर गुजरता है। वर्षा ऋतु में तेज बारिश और आंधी के कारण कई स्थानों पर विशाल वृक्ष सड़क किनारे गिर गए थे तथा झाडियां तेजी से फैल जाने से वाहन चालकों की दृश्यता काफी कम हो गई थी। विशेष रूप से रात्रि के समय सामने से आने वाले वाहनों का समय रहते दिखाई न देना दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन रहा था। इससे दोपहिया, चारपहिया एवं मालवाहक वाहनों के चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

इस मार्ग पर पूर्व में कई गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।जिनमें लोगों की जान गई तथा अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसे संवेदनशील मार्ग पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसी जोखिम को देखते हुए रूपझर पुलिस ने स्वयं श्रमदान कर सड़क के दोनों ओर फैली झाड़ियों को काटकर हटाया, गिरे हुए पेड़ों एवं लकड़ियों को सड़क से बाहर किया तथा ऐसे स्थानों की सफाई की जहां दृश्यता बाधित हो रही थी। इस कार्य के बाद सड़क की विजिबिलिटी पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई है और अब दूर से आने वाले वाहन आसानी से दिखाई देने लगे हैं।जिससे दुर्घटनाओं की संभावना में कमी आने की उम्मीद है।

पुलिस का यह प्रयास केवल सड़क की सफाई तक सीमित नहीं है। बल्कि इसका उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यातायात को सुगम बनाना तथा संभावित दुर्घटनाओं को रोकना है। स्थानीय नागरिकों एवं वाहन चालकों ने रूपझर पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्य प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करते हैं तथा समाज में पुलिस की सकारात्मक भूमिका को प्रदर्शित करते हैं।

रूपझर पुलिस की आमजन से अपील

थाना रूपझर पुलिस ने सभी वाहन चालकों एवं यात्रियों से अपील की है कि वर्षा ऋतु के दौरान विशेष सावधानी बरतें। वाहन हमेशा नियंत्रित गति से चलाएं, अंधे मोड़ों पर अनिवार्य रूप से हॉर्न बजाएं, ओवरटेक करने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित करें कि सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा है तथा बारिश के दौरान फिसलन वाली सड़क पर अचानक ब्रेक लगाने से बचें।पुलिस ने यह भी कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों, गहरी खाइयों तथा सड़क किनारे खतरनाक स्थानों पर फोटो या सेल्फी लेने का प्रयास न करें। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते समय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सभी यातायात नियमों का पालन करें।

रूपझर पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षित यातायात केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। पुलिस भविष्य में भी जनहित, सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना रोकथाम के लिए ऐसे अभियान लगातार संचालित करती रहेगी।ताकि बैहर बालाघाट मार्ग पर यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा सुरक्षित एवं सुगम बन सके।

टीएल बैठक में हुई समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। 13 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा (टीएल) बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर मृणाल मीना ने समय सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा कर उनके निराकरण के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर राहुल नायक एवं मायाराम कोल, डिप्टी कलेक्टर प्रदीप कौरव, एसडीएम गोपाल

सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

जर्जर भवनों की पहचान एवं डिस्मेंटल करने के निर्देश

कलेक्टर श्री मीना ने बैठक में जिले के नगरीय क्षेत्रों में स्थित जर्जर भवनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि जिन भवनों के गिरने और जनहानि होने की संभावना हो, उन भवनों को डिस्मेंटल करने की कार्यवाही की जाए। जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऐसे शासकीय एवं अशासकीय भवनों को चिन्हित करने एवं उन्हें डिस्मेंटल करने कहा गया। इस दौरान बताया गया कि नगरीय क्षेत्र बालाघाट में 11 शासकीय एवं 20 प्राइवेट भवनों को चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार वारासिवनी में 05 शासकीय एवं 03 प्रायवेट भवनों को चिन्हित किया गया है। नगरीय क्षेत्र मलाजखंड में 10 जर्जर भवनों को डिस्मेंटल कर दिया गया है।

जर्जर भवनों में संचालित संस्थानों पर रोक एवं यात्री वाहनों की सघन जांच के निर्देश

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण को निर्देशित किया गया कि जिले में कहीं पर भी जर्जर भवन में आंगनवाड़ी केंद्र, शालाओं की कक्षाएं एवं छात्रावास संचालित न हों। यदि कहीं ऐसी स्थिति हो तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और अन्य भवनों में इनका संचालन किया जाए। कलेक्टर श्री मीना ने जिला परिवहन अधिकारी को सख्त निर्देश दिये कि जिले में संचालित यात्री वाहनों की सघन जांच करें और नियम विरुद्ध एवं बिना फिटनेस के संचालित बसों पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र के एसडीओपी के साथ बैठक कर टेम्पो, ऑटो, पिकअप एवं अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी ढोने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें

बैठक में सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर श्री मीना ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 50 दिनों से अधिक की लंबित शिकायतों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाए। जिन विभागों में 500 दिनों से अधिक की शिकायत लंबित पाई जाएगी, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने तथा यह राशि उनके वेतन से काटने के निर्देश दिए गए।

दतिया की जनता मध्य प्रदेश में परिवर्तन का शंखनाद करेगी-कांग्रेस

भाजपा के अहंकार और जनविरोधी राजनीति का लोकतांत्रिक जवाब देगी

भोपाल /दतिया। मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के उपरांत दतिया में एक विशाल जनसभा आयोजित हुई, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश प्रभारी श्री हरीश चौधरी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता, विधायक गण,जनप्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनसभा में उमड़े जनसैलाब ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि दतिया की जनता विकास, न्याय, किसान हित, युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी है तथा प्रदेश में परिवर्तन का मजबूत संकल्प ले चुकी है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि देश की जनता ने एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वादे पर विश्वास किया था कि वे देश को कभी झुकने नहीं देंगे, लेकिन आज देश का हर वर्ग आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक दबाव का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज किसानों, युवाओं, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों को लगातार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ा है और जनता के अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता स्वयं तय करेगी कि लोकतंत्र को मजबूत करना है या अहंकार की राजनीति को आगे बढ़ाना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि दतिया विधानसभा उपचुनाव केवल एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं है, बल्कि यह पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव है। उन्होंने कहा कि दतिया की जनता के पास प्रदेश की तस्वीर बदलने का ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल पूछा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे आज तक पूरे क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा कि किसानों से रू2,700 प्रति क्विंटल गेहूं, रू 3,100 प्रति क्विंटल धान, रू ?6,000 प्रति क्विंटल सोयाबीन का मूल्य देने तथा महिलाओं को ?3,000 प्रतिमाह देने के वादे किए गए थे, लेकिन वर्षों बाद भी जनता इन घोषणाओं के पूरा होने का इंतजार कर रही है। पटवारी ने कहा कि जनता ने सरकार को सेवा के लिए जनादेश दिया था, प्रतिशोध और बदले की राजनीति के लिए नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने राजेंद्र भारती के विधायक पद समाप्त होने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दतिया की जनता के जनादेश का अपमान है और जनता इसका लोकतांत्रिक जवाब देगी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को सर्वसम्मति से चुना गया उम्मीदवार बताते हुए कहा कि वे सरल, ईमानदार, जनसेवी और सभी कार्यकर्ताओं की सामूहिक पसंद हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ने तथा कांग्रेस की ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने घोषणा की कि चुनाव अभियान के दौरान वे स्वयं दतिया में रहकर गांव-गांव जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सत्ता पक्ष धनबल, प्रशासनिक दबाव या अन्य साधनों का उपयोग करता है, तब भी कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच रहकर उसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दतिया की जनता कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को विजयी बनाकर पूरे प्रदेश में परिवर्तन का संदेश देगी।झ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता की ताकत से चलता है, सत्ता के दुरुपयोग से नहीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दतिया की न्यायप्रिय और जागरूक जनता भाजपा द्वारा किए गए प्रत्येक राजनीतिक षड़यंत्र का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी तथा कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से दतिया की जनता से अपील की कि वे लोकतंत्र, संविधान, किसान, युवा, महिला और आम नागरिक के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें तथा कांग्रेस प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह को ऐतिहासिक विजय दिलाएं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि प्रदेश में जनहित, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का चुनाव है।

आम सूचना

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मौजा पांढरवानी तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट में स्थित भूमि ख.नं. 331/13 रकबा 0.8090 हे0 श्रीमती कैलासी नामदेव पति श्री खुरसीराम नामदेव जाति दर्जी निवासी ग्राम पांढरवानी तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट म.प्र. के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज है। जो लालबर्रा शहर के वैदिक इंग्लिश स्कूल से लगी हुई अत्यंत मूल्यवान भूमि है और उक्त भूमि हम अपीलकर्तागण के दादा स्व. चट्टीलाल नामदेव से प्राप्त पैतृक भूमि है। स्व. चट्टीलाल नामदेव की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र खुरसीराम नामदेव व पुत्रवधु कैलासीबाई द्वारा स्व. चट्टीलाल नामदेव के वृद्धावस्था में फर्जी वसीयतनामा तैयार करवाकर उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया है और राजस्व प्रलेखों मे अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुये लोगों के बहकावें में आकर उपरोक्त वर्णित भूमि को अपीलकर्तागण की मां कैलासीबाई नामदेव व पिता खुरसीराम नामदेव किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय कर भूमि अफरा तफरी करना चाह रहे है। हमारी मां और पिता दोनों की आयु करीब 80 वर्ष से अधिक की हो चुकी है और वर्तमान में उनके सोचने समझने की शक्ति भी कमजोर हो चुकी है और लालबर्रा क्षेत्र में फैले भू माफिया हमारे माता पिता को बहला फुसलाकर उक्त भूमि खरीदने की फिराक में है और हमें विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि किसी भू माफिया ने हमारे माता पिता से एकांत में भूमि का सौदा कर भूमि का बिक्री इकरारनामा अवैध रूप से स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करा लिया है और भूमि खरीदी बिक्री के संबंध में हम विधिक वारसानों से क्रेता और विक्रेता द्वारा किसी प्रकार से सलाह मशवरा नहीं किया गया है। उक्त भूमि हमारी पैतृक भूमि है, जिस पर हम अपीलकर्तागण का बराबर बराबर का हक हिस्सा है और उक्त भूमि को हमारी मां कैलासी बाई को हमारी सहमति के बिना विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं है और हमारी सहमति के बिना उक्त भूमि को विक्रय करने का सौदा कोई भी व्यक्ति करता है तो वह अवैध व शून्य माना व समझा जावेगा। फलस्वरूप इस नोटिस के माध्यम से आमजनता को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि की खरीदी बिक्री करने का सौदा ना करे और ना ही करावें अन्यथा इस आमसूचना के पश्चात किया गया किसी भी प्रकार का विक्रय पंजीयन अवैध व शून्य माना व समझा जावें।

अतः आमजनता सुचना प्राप्त करें।

प्रकाशक
पवन पिता खुरसीराम नामदेव
शरद पिता खुरसीराम नामदेव
संजय पिता खुरसीराम नामदेव
सभी निवासी वार्ड नंबर 15 ग्राम पंचायत
पांढरवानी तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट म.प्र.

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी जिला बालाघाट (म.प्र)

क्रमांक/0024/ अति.कले./वि.अधि./2028 बालाघाट तारीख 10/04/2026

आम-सूचना

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अन्तर्गत विशेष/अन्तजातीय विवाह हेतु आवेदकगण राकेश कुमार पाटिल उम्र-29 वर्ष पिता श्री सोहनलाल पाटिल जाति महार निवासी वार्ड नं. 02 ग्राम आमगांव तह. व जिला बालाघाट (म.प्र) एवं आवेदिका राखी नगपुरे उम्र-26 वर्ष पिता श्री ज्ञानेश्वर नगपुरे जाति लोधी निवासी वार्ड नं. 19 ग्राम सुरजटोला मोहगांव तह. लालबर्रा जिला बालाघाट (म.प्र.) ने उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे विशेष विवाह हेतु सुनवाई दिनांक 24/07/2026 को नियत की गई है।

अतः उक्त विवाह के सबंध मे जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह सुनवाई दिनांक 24/07/2026 तक न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी बालाघाट के समक्ष न्यायालयीन समय प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति लिखित रूप मे प्रस्तुत करें। नियत समयवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा ।

अपर कलेक्टर
विवाह अधिकारी
जिला-बालाघाट(म.प्र)

फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे पुलिसकर्मी

भोपाल में आईजी के निर्देश हर संडे थाने में दिखाना होगा दम

भोपाल। मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस को और फिट और सुपर हिट बनाने की मुहिम शुरू हुई है। पुलिस महानिरीक्षक रुचिवर्धन मिश्रा की पहल पर हर रविवार-थाना परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत हर रविवार पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य, फिटनेस और थाना कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी। जिले के सभी थानों में अधिकारियों और कर्मचारियों को एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान और हार्टफुलनेस मेडिटेशन कराया जाएगा। पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और बेहतर पुलिसिंग के लिए रविवार से इसकी शुरुआत की गई है। हर रविवार फिट रहेगा थाना परिवार, स्वस्थ पुलिसिंग की नई पहल स्लोगन के साथ आईजी देहात रुचिवर्धन मिश्रा और देहात एसपी पंकज कुमार पांडे ने ईटखेड़ी और सूखी सेवानिया थाने मे इस अभियान का शुभारम्भ किया। भोपाल जिले के सभी थानों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान और हार्टफुलनेस मेडिटेशन किया। अधिकारियों ने नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर पुलिसिंग की बुनियाद बताया। फिटनेस गतिविधियों के बाद सभी थानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की गई और लंबित विवेचनाओं और मर्ग प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, अपराध नियंत्रण, वारंट तामीली, शिकायतों की निष्पक्ष जांच और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की प्रगति पर चर्चा हुई। इस पहल के साथ ही थाना परिसर की साफ-सफाई, मालखाना, हवालात सुरक्षा, जब्त संपत्ति के निराकरण और कार्यालयीन व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। 40 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों और कर्मचारियों की हेल्थ प्रोफाइल तैयार कर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, तनाव प्रबंधन और चिकित्सकीय परामर्श पर भी जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक (देहात) पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि हर रविवार-थाना परिवार केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों के कल्याण, बेहतर थाना प्रबंधन, प्रभावी अपराध नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण विवेचना और जनोन्मुखी पुलिसिंग को मजबूत करने की सतत पहल है। भोपाल (देहात) पुलिस अब प्रत्येक रविवार इस अभियान के तहत स्वास्थ्य, संवाद और कार्य समीक्षा का कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करेगी।

नाम सुधार सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं विकाश पिता ओम प्रकाश पंचभावे ग्राम गड़दा पोष्ट केशलेवाड़ा थाना हट्टा तह. जिला बालाघाट म.प्र. का निवासी हुं।

मेरी कक्षा दसवीं की अंकसूची में मेरा नाम विकाश पिता ओमप्रकाश दर्ज है।

अतः मेरे ड्राईविंग लाइसेंस क्रमांक MP50R-2022-0008483 में मेरा नाम **VIKASH S/o OMPRAKASH** किया जावे तथा मुझे इसी नाम से जावा व पहचाना जावें।

आवेदक
विकाश पिता ओमप्रकाश
ग्राम-गड़दा पोष्ट-हट्टा

बारबेड वायर (कांटेदार तार) एवं चेन लिंक जाली उचित दाम पर उपलब्ध

लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध

निर्माता
तिरूपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोनः- 07632-243531
मोः- 8989976858, 9425139998

न्यूज गैलरी

कोसमी के एक मकान में लगी आग, पैरा, अनाज और घरेलू सामग्री जलकर हुई खाक

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। नगर मुख्यालय से लगे ग्राम कोसमी के वार्ड क्रमांक 13 में सोमवार तड़के एक घर में लगी आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में घर में रखा पैरा, अनाज और अन्य घरेलू सामग्री उसकी चपेट में आकर जलकर राख हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने इसे महज हादसा मानने से इनकार करते हुए अपने ही मोहल्ले के एक व्यक्ति पर जानबूझकर आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज करने में लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार ग्राम कोसमी निवासी तेजलाल नगपुरे के घर में 13 जुलाई की सुबह लगभग 3:30 बजे अचानक आग लग गई। गहरी नींद में सो रहे परिवार की आंख उस समय

खुली, जब घर के बाहर से धुआं और आग की लपटें दिखाई देने लगीं। देखते ही देखते आग ने घर के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। परिवार के सदस्यों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया, जिसके बाद ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए। घटना की सूचना तत्काल डायल-112 और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। काफी देर तक चली मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक घर में रखा पैरा, अनाज और अन्य जरूरी घरेलू सामग्री पूरी तरह जल चुकी थी। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि समय रहते ग्रामीण और दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंचती, तो आग आसपास के अन्य मकानों तक भी फैल सकती थी। पीड़ित तेजलाल नगपुरे ने दावा किया है कि यह आग दुर्घटनावश नहीं लगी, बल्कि सुनियोजित तरीके से लगाई गई है। उनका कहना है कि उन्होंने और उनकी बेटी ने मोहल्ले के एक व्यक्ति को आग लगाते हुए अपनी आंखों से देखा है। घर में रखा पैरा, खाद्यान्न और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह नष्ट हो गया, जिससे परिवार के सामने आजीविका और दैनिक जीवन का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद जब वे शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे तो उनकी शिकायत तत्काल दर्ज नहीं की गई। जबकि उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुना गया। इस कारण उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई को लेकर चिंता है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और आग से हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।

परमिट नहीं, फिर चालान क्यों ? स्कूली वैन-ऑटो चालकों ने यातायात थाने का किया घेराव

परिवहन विभाग पर परमिट जारी नहीं करने का आरोप, यातायात पुलिस से कार्रवाई रोकने की मांग

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

जिले में स्कूल वाहनों की जांच के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के बीच सोमवार को स्कूली वैन और ऑटो चालकों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार हो रही चालानी कार्रवाई से नाराज दर्जनों वाहन चालक अपने वाहनों के साथ सुबह करीब 11 बजे सीधे यातायात थाना पहुंच गए और थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। चालकों ने आरोप लगाया कि एक ओर यातायात पुलिस दस्तावेज पूरे नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग वर्षों से उनके वाहनों के परमिट जारी नहीं कर रहा है। ऐसे में वे नियमों का पालन करना चाहते हुए भी असमर्थ हैं और दोनों विभागों के बीच पिस रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान चालकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। उनका कहना था कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के नाम पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन जिन कारणों से दस्तावेज अधूरे हैं, उन्हें दूर करने की दिशा में संबंधित विभाग कोई पहल नहीं कर रहा। इससे उनकी रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है।

वैन चालक अमित अग्रवाल ने बताया कि पिछले कई दिनों से यातायात पुलिस द्वारा स्कूल वाहनों की विशेष जांच की जा रही है। इस दौरान परमिट, फिटनेस, बीमा, टैक्स, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की जांच कर कमी मिलने पर तत्काल चालान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाहन चालक नियमों का पालन करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि परिवहन विभाग ही उनके वाहनों के परमिट जारी नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि कई वाहन संचालक दो-तीन वर्षों से लगातार परिवहन विभाग के चक्कर काट रहे हैं। बार-बार आवेदन और दस्तावेज जमा करने के बावजूद परमिट नहीं मिल रहे। ऐसे में मजबूरीवश उन्हें बिना परमिट के ही वाहन चलाकर बच्चों को स्कूल पहुंचाना पड़ रहा है। अब यातायात पुलिस द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई किए जाने से उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है। चालकों ने कहा कि यदि परिवहन विभाग समय पर परमिट जारी कर दे तो वे सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब एक विभाग अपना काम नहीं कर रहा, तो दूसरे विभाग द्वारा कार्रवाई करना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर विभागीय लापरवाही की सजा वाहन चालकों को क्यों भुगतनी पड़ रही है? प्रदर्शन के दौरान कई चालकों ने बताया कि वे केवल स्कूल परिवहन का कार्य कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। लगातार चालान बनने से उनकी आमदनी पर सीधा असर पड़ रहा है। कई चालकों ने कहा कि हजारों रुपये के चालान भरना उनके लिए संभव नहीं है। यदि यही स्थिति बनी रही तो उन्हें वाहन खड़े करने पड़ेंगे, जिसका सीधा असर स्कूल जाने वाले बच्चों की परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ेगा। चालकों ने यह भी आरोप लगाया कि परिवहन विभाग में परमिट की प्रक्रिया अत्यधिक लंबी और जटिल है। आवेदन करने के बाद महीनों तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। कई बार नए दस्तावेजों की मांग कर दी जाती है, जिससे प्रक्रिया और लंबी हो जाती है। उनका कहना था कि यदि प्रशासन वास्तव में स्कूल वाहनों को नियमों के दायरे में लाना चाहता है तो सबसे पहले लंबित परमिट प्रकरणों का निराकरण किया जाना चाहिए।

वाहन चालकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जायेगा - यीना

इस पूरे मामले को लेकर यातायात थाना प्रभारी यीना राहांगडाले ने अनौपचारिक चर्चा में बताया कि स्कूल वैन चालकों द्वारा परमिट संबंधी समस्याएं उनके संज्ञान में लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस का उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना और स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत जिन वाहनों में दस्तावेजों की कमी पाई जा रही है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि वाहन चालकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों और परिवहन विभाग से चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि परमिट संबंधी लंबित मामलों के समाधान के लिए जल्द ही विशेष शिविर लगाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वाहन संचालकों को एक ही स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों और परमिट संबंधी समस्याओं का समाधान मिल सके।

तीन महीने से टीपी का इंतजार, खेत में सड़ रहा हजारों बांस; वन विभाग पर किसान का फूटा गुस्सा

जिले के बिरसा क्षेत्र का मामला, परिवहन अनुमति नहीं मिलने से लाखों के नुकसान की आशंका, कई बार सत्यापन के बाद भी नहीं जारी हुई टीपी, डीएफओ बोले- जल्द होगी कार्रवाई

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। बांस उत्पादन के लिए प्रदेशभर में पहचान रखने वाले बालाघाट जिले में एक बार फिर किसानों को वन विभाग से परिवहन अनुमति (टीपी) नहीं मिलने का मामला सामने आया है। बिरसा विकासखंड के ग्राम एक्को निवासी एक किसान ने आरोप लगाया है कि वह पिछले तीन महीने से अपने खेत में तैयार बांस के परिवहन की अनुमति (ट्रांजिट पास-टीपी) के लिए वन विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक अनुमति जारी नहीं की गई। इसके कारण खेत में पड़ा हजारों की संख्या में बांस बारिश के कारण खराब होने लगा है और उन्हें लाखों रुपये के नुकसान की आशंका सताने लगी है।

किसान मदन सिंह ने बताया कि उनकी निजी भूमि पर तैयार बांस की फसल पूरी तरह कटाई के बाद परिवहन के लिए तैयार है। उन्होंने वन परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण उकवा सामान्य को आवेदन देकर राज्य एवं राज्य के बाहर परिवहन के लिए ट्रांजिट पास जारी करने का अनुरोध किया था। उनके खेत में कुल 5,329 नग बांस कटकर तैयार पड़े हैं, जिनमें अलग-अलग लंबाई के बांस शामिल हैं। उन्होंने बताया कि समय पर परिवहन नहीं होने के कारण लगातार हो रही बारिश से बांस की गुणवत्ता प्रभावित होने लगी है, जिससे बाजार में मिलने वाला मूल्य भी कम हो जाएगा। यदि शीघ्र अनुमति नहीं मिली तो पूरी फसल खराब होने का खतरा है। मदन सिंह का कहना है कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कई बार उनके खेत का निरीक्षण किया, सत्यापन भी किया, लेकिन इसके बावजूद फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार नए निरीक्षण और नई

प्रक्रिया का हवाला देकर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। इससे उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान के समर्थन में पहुंचे ग्रामीण डमरू सिंह धुर्वे और कैलाश नकपुरे ने भी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर किसानों को बांस उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खेती बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन जब किसान तैयार फसल बेचने की स्थिति में आता है तो उसे परिवहन अनुमति के लिए महीनों तक विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनका कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में किसान बांस की खेती करने से ही पीछे हट जाएंगे। ग्रामीणों ने बताया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा तीन-तीन और चार-चार बार मौके पर जाकर सत्यापन किया जा चुका है। इसके बावजूद अनुमति जारी नहीं होना समझ से परे है। उनका कहना है कि विभागीय प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं होनी चाहिए कि किसान अपनी उपज बेचने के लिए महीनों तक इंतजार करता रहे। गौरतलब है कि बालाघाट जिला प्रदेश के प्रमुख बांस उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में किसान निजी भूमि पर व्यावसायिक रूप से बांस की खेती करते हैं। शासन भी किसानों को बांस उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन यदि तैयार उपज के परिवहन में ही अनावश्यक देरी होगी तो इसका सीधा असर किसानों की आय और बांस उत्पादन को बढ़ावा देने की योजनाओं पर पड़ेगा।

आवेदन कुछ दिन पहले ही मेरे संज्ञान में आया है - रेशम सिंह

इस पूरे मामले में जब वन मंडलाधिकारी (डीएफओ) रेशम सिंह धुर्वे से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि संबंधित किसान का आवेदन कुछ दिन पहले ही उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने मामले की जांच और निरीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। डीएफओ ने कहा कि कई बार किसान केवल निचले स्तर के कार्यालयों में ही आवेदन देकर प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि यदि वे सीधे डिवीजन कार्यालय में आकर अपनी समस्या रखते हैं तो अनुमति प्रक्रिया तेजी से पूरी कराई जा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों को अनावश्यक रूप से बार-बार सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण हैं तो नियमानुसार परिवहन अनुमति जारी की जाएगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित मामले में शीघ्र कार्रवाई कर किसान को राहत देने का प्रयास किया जाएगा।

सीटें बढ़ाओ, छात्रों का भविष्य बचाओ, एनएसयूआई ने कॉलेज प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी

बीए, बीएससी, बीकॉम सहित स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीटें कम होने से प्रवेश का संकट, ग्रामीण और गरीब विद्यार्थियों के हित में सीट वृद्धि की मांग

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के प्रवेश के दौरान सीटों की कमी का मुद्दा अब गरमाने लगा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने महाविद्यालय में विभिन्न संकायों की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार 13 जुलाई को कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि वर्तमान में बीए, बीएससी और बीकॉम सहित अन्य पाठ्यक्रमों में सीटें काफी कम हैं, जिससे बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं प्रवेश से वंचित हो सकते हैं। यदि समय रहते सीटों में वृद्धि नहीं की गई तो संगठन आंदोलन का रास्ता अपनाएगा।

एनएसयूआई के पदाधिकारी ऋषभ सहारे और सुमेध बंसोड़ ने बताया कि हर वर्ष प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सीटों की कमी के कारण अनेक मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता। इस वर्ष भी वही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शासकीय महाविद्यालय पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सीमित सीटों के कारण उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। उन्होंने कहा कि बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे प्रमुख पाठ्यक्रमों में प्रवेश की मांग सबसे अधिक रहती है, जबकि सीटें अपेक्षाकृत कम हैं। इसके कारण कई विद्यार्थियों को मजबूर होकर निजी महाविद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है, जहां उन्हें भारी-भरकम फीस का भुगतान करना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह संभव नहीं होता, जिससे कई छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। एनएसयूआई पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी का अधिकार है और केवल सीटों की कमी के कारण किसी भी छात्र को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि शासन और महाविद्यालय प्रशासन समय रहते सीटों में वृद्धि कर दें तो जिले के हजारों विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। संगठन द्वारा महाविद्यालय प्रबंधन को सौंपे गए ज्ञापन में केवल स्नातक कक्षाओं ही नहीं, बल्कि स्नातकोत्तर स्तर के एमए, एमएससी और एमकॉम पाठ्यक्रमों में भी सीटें बढ़ाने की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पिछले कई वर्षों से प्रवेश के समय सीटों की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए सभी संकायों में सीट वृद्धि कर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर उपलब्ध कराया जाए। एनएसयूआई ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में छात्र हित में आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर महाविद्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। वर्तमान में प्रवेश प्रक्रिया जारी है और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें महाविद्यालय प्रबंधन और उच्च शिक्षा विभाग पर टिकी हैं कि वे विद्यार्थियों की मांग को स्वीकार करते हुए सीटों में वृद्धि का निर्णय लेते हैं या फिर छात्रों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

तेज आंधी बनी काल-बालाघाट गोंदिया नागपुर में चला इलाज लेकिन जिंदगी की जंग हार गई

छत से गिरी निर्मला ने डेढ़ माह बाद तोड़ा दम, दो मासूम बेटियों के सिर से उठा मां का साया

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। तेज आंधी-तूफान के बीच घर की छत से गिरी एक महिला आखिरकार जिंदगी की लंबी जंग हार गई। लगभग डेढ़ माह तक बालाघाट, गोंदिया और नागपुर के अस्पतालों में चले लगातार उपचार के बावजूद चिकित्सक उसे बचा नहीं सके। सोमवार सुबह जिला अस्पताल बालाघाट में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया है। सबसे अधिक मार उन दो मासूम बेटियों पर पड़ी है।जिनके सिर से हमेशा के लिए मां का साया उठ गया।मृतिका निर्मला पति दुर्गा प्रसाद नेताम 35 वर्ष ग्राम सिरपुर थाना कटंगी निवासी है। जिला अस्पताल पुलिस ने इस महिला का शव पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजन को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्मला नेताम अपने पति के साथ खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करती थी। परिवार में पति के अलावा उसकी दो छोटी बेटियां हैं। जानकारी के अनुसार 30 मई की शाम लगभग 5 बजे क्षेत्र में तेज आंधी तूफान चल रहा था। इसी दौरान निर्मला घर की छत पर सुख रहे कपड़ों को निकालने के लिए छत के ऊपर गई थी। अचानक तेज हवा के झोंके से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे गिर गई। सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गई थी। परिजन तत्काल उसे जिला

अस्पताल बालाघाट लेकर पहुंचे। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिये थे।परिजनों ने हार नहीं मानी। बेहतर इलाज की उम्मीद में पहले उसे बालाघाट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराये लेकिन वहां से भी रेफर कर दिया गया। इसके बाद निर्मला को गोंदिया ले जाया गया वहां भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए इसके बाद निर्मला को नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।जहां लगभग एक माह तक उसका उपचार चलता रहा। परिवार ने हर संभव प्रयास किया और उसकी जान बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन उसकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका।इसके बाद 6 जुलाई को परिजन निर्मला को पुनः जिला अस्पताल बालाघाट लेकर आए।जहां उसका इलाज जारी रहा। चिकित्सकों के अथक प्रयासों केतेज आंधी बनी काल- छत से गिरी निर्मला ने डेढ़ माह बाद तोड़ा दम, दो मासूम बेटियों के सिर से उठा मां का साया बावजूद 13 जुलाई की सुबह लगभग 8:40 बजे निर्मला ने अंतिम सांस ली।जिला अस्पताल पुलिस ने आवश्यक पंचनामा कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत मर्ग कायम कर मामले की जांच एवं आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण संबंधित थाना कटंगी को भेज दिया है।

पेपर लीक और रूकी छात्रवृत्ति सहित अन्य मांगों को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने सौंपा ज्ञापन

कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में (एसटी) आरक्षण का घोर उल्लंघन का आरोप, मांगे पूरी नही होने पर आंदोलन करने की दी चेतावनी

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा।

छात्र अधिकारों और आदिवासी व पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले प्रमुख संगठन गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन लालबर्रा ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और छात्र नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोंडवाना स्टूडेंटस यूनियन ने सोमवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को महामहिम रा'यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर समूह-2, उपसमूह-1 अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण रोस्टर के अनुरूप पदों का निर्धारण किये जाने, प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्यवाही, रूकी छात्रवृति जल्द दिये जाने सहित अन्य मांगों को पूरा किये जाने की मांग की है। वहीं मांगे पूरी नही होने पर आगामी समय में आंदोलन करने की चेतावनी प्रशासन को दी है। सौंपे गये ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित समूह-2, उपसमूह-1 कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा-2026 में अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के आरक्षण नियमों का घोर उल्लंघन किया गया है। मध्यप्रदेश में आदिवासियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का वैधानिक प्रावधान प्रभावी है। इस आधार पर कुल घोषित 2784 पदों में से अनुसूचित वर्ग के लिए लगभग 557 पद अपेक्षित हैं, जबकि इसके विपरीत मात्र 122 पद ही घोषित किए गये हैं। विसंगतिपूर्ण तरीके से अनारक्षित वर्ग के लिए 1126, ईडब्ल्यूएस के लिए 444, अनुसूचित जाति के लिए 316 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 776 पद शामिल किये गये है। साथ ही न्यायालयीन प्रकरण के कारण 13 प्रतिशत पद होल्ड बताये गये है जो गलत है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण रोस्टर के अनुरूप पदों का निर्धारण होना चाहिए। वहीं गोंडवाना स्टूडेंटस यूनियन ने आरोप लगाया है कि आरक्षण रोस्टर का समुचित पालन नहीं करना अनुसूचित जनजाति वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन है और रोजगार के अवसरों को भेदभावपूर्ण तरीके से सीमित करने का एक गंभीर अपराध है। संगठन ने इस भर्ती के विभागवार एवं श्रेणीवार आरक्षण रोस्टर को तत्काल सार्वजनिक करने और पदों में नियमानुसार वृध्दि सुनिश्चित करने की मांग की है।

संगठन की प्रमुख मांगें

गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन लालबर्रा द्वारा तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं एसडीएम के नाम सौंपे गये ज्ञापन में उनकी प्रमुख मांगे है। जिसमें कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा-2026 में आदिवासियों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कर पदों की संख्या 122 से बढ़ाकर न्यायसंगत की जाने और रोस्टर सार्वजनिक करने, नीट, एमपीपीएससी व्यापम और पटवारी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों की उ%च स्तरीय न्यायिक या सीबीआई जांच करवाकर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही, प्रभावित विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क और यात्रा खर्च की भरपाई शासन से करने, जिले के शासकीय विश्ववद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत एसटी/एससी/ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं की लंबे समय से रूकी छात्रवृत्ति एवं आवास भत्ते का तत्काल भुगतान किये जाने की मांगे शामिल है। वहीं संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि लगातार पेपर लीक होने से छात्र-छात्राएं मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, कई युवा डिप्रेशन और आत्महत्या जैसी कदम उठा रहे है। वहीं दूसरी ओर, समय पर छात्रवृत्ति और आवास भत्ता न मिलने के कारण गरीब वर्ग के छात्र-छात्राएं परीक्षा फॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं। यदि इन न्यायोचित मांगों पर शासन-प्रशासन द्वारा ठोस और त्वरित कार्यवाही नहीं की गई, तो उग्र आंदोलन किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ हो रहा भेदभाव - सुनेश

गोंडवाना स्टूडेंटस यूनियन जिला अध्यक्ष सुनेशसिंह उइके ने बताया कि संपूर्ण प्रदेश में एससी/एसटी वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति समय पर उनके खातों में नही डाला जा रहा है जिससे उन्हे पढ़ाई करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे आर्थिक संकअ से गुजर रहे है। साथ ही कृषि विस्तार अधिकारी समूह 2, उपसमूह 1 में एसटी वर्ग आरक्षण में घोर उल्लंघन किया गया है। श्री उइके ने बताया कि आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर तहसीलदार महोदय को महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और हमारी जायज मांगों को पूरा करें।

मांगे पूरी नही होने पर करेगें आंदोलन - राकेश

गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन प्रदेश सदस्य राकेश वाडिवा ने बताया कि गोंडवाना स्टूडेंटस यूनियन हमेशा छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ता है वर्तमान में जो कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर भर्ती प्रदेश सरकार के द्वारा निकाली गई है। उसमें आरक्षण के अनुसार हमारे समुदाय के लोगों को 20 प्रतिशत ही पद स्वीकृत किये गये है उसे बढ़ाकर आरक्षण के अनुसार किया जाना चाहिए। श्री वाडिवा ने बताया कि नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षा के पेपर बार-बार लीक हो रहे है जिससे विद्यार्थी मानसिक रूप से परेशान है इसलिए सरकार से मांग है कि पेपर लीक की उ'च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्यवाही करें और एसटी के बच्चों को लंबे समय से छात्रवृत्ति नही मिली है उनके खातों में जल्द छात्रवृत्ति डाली जाये उक्त मांगों को लेकर तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और मांगे पूरी नही होने पर आंदोलन किया जायेगा।

नहर एवं केनालों की साफ-सफाई करवाये जल संसाधन विभाग - भाऊराम

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। जल उपभोक्ता संस्था पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव भाऊराम गाड़ेश्वर ने विज्ञप्ति जारी कर अपने वक्तव्य में बताया कि मानसून सत्र प्रारंभ हो चुका है और लालबर्रा क्षेत्र स्थित नहर एवं केनालों की लंबे समय से साफ-सफाई नही करवाई गई है एवं कुछ स्थानों से नहर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में नहरों में पानी छोड़ा जाता है तो किसानों के खेतों तक नही पहुंच पायेगा इसलिए नहर में पानी छोड़ने के पहले जल संसाधन विभाग को नहर एवं केनालों की साफ-सफाई व जहां-जहां से नहर व केनाल जीर्णशीर्ण एवं क्षतिग्रस्त हो चुके है उनका मरम्मत कार्य करवाना चाहिए। लेकिन जल संसाधन विभाग के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है जिससे क्षेत्रीय किसानों में आक्रोश व्याप्त है। श्री गाड़ेश्वर ने बताया कि वैनगंगा ढूटी वीयर वैनगंगा बड़ी नहर अंतर्गत आने वाले ग्राम बबरिया, आमाटोला, अमोली, चन्दपुरी, निलजी, लवादा, सर्राटी जलाशय से निकली माइनर नहर जिन ग्रामों से गुजरी है। उन ग्रामों की केनालों एवं नहरों की लंबे समय से साफ-सफाई नही करवाई गई है। साथ ही कुछ स्थानों से नहर व केनाल क्षतिग्रस्त भी हो चुके है ऐसी स्थिति में किसानों के खेतों तक पानी नही पहुंच पाने के कारण पानी के अभाव में हजारों हेक्टेयर में लगने वाली फसल प्रभावित हो सकती है। साथ ही यह भी बताया कि मानसून सत्र प्रारंभ हो चुका है और कुछ दिनों बाद लालबर्रा क्षेत्र स्थित सभी नहरों में पानी छोड़ा जायेगा इसलिए जल संसाधन विभाग से मांग है कि नहरों में पानी छोड़ने के पहले नहर व केनालों की साफ-सफाई व क्षतिग्रस्त स्थानों का मरम्मत कार्य जल्द करवाये।

जन अभियान परिषद की समीक्षा बैठक आज

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत के सभाकक्ष में 14 जुलाई को मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र. शासन) द्वारा परिषद के नेटवर्क से जुड़ी ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों और मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम से जुड़े परामर्शदाताओं की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आहूत की गई है। यह बैठक जिला समन्वयक (म.प्र. जन अभियान परिषद बालाघाट) महेश पटले एवं विकासखंड समन्वयक अनिल कुमार के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ होगी। आयोजित बैठक में सीएमसीएलडीपी के अंतर्गत बीएसडब्ल्यू एवं एमएसडब्ल्यू के नवीन प्रवेश, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जन अभियान परिषद का स्थापना दिवस पखवाड़ा सहित अन्य कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की जायेगी।

ओरिएंटल कॉलेज के पास कार और बाइक में भीषण भिड़ंत, युवक गंभीर रूप से घायल

प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को किया गया जिला चिकित्सालय रिफर, टक्कर इतनी जबरदस्त कि बाइक के उड़े परखच्चे

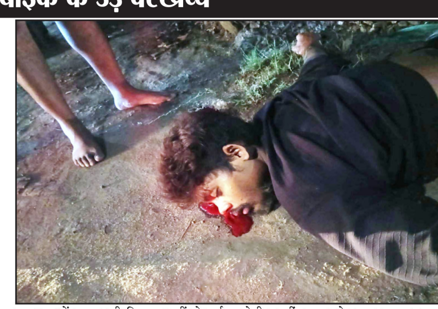

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। लालबर्रा-बालाघाट हाईवे रोड पर बकोड़ा के समीप स्थित ओरिएंटल कॉलेज के पास रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गये और कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिसका लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रिफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 1 बजे ओरिएंटल कॉलेज के समीप चौपहिया वाहन (कार) और मोटरसाइकिल में आमने-सामने से सीधी टक्कर हुई है। देर रात हुए इस हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं शुरूआत में घायल की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में उसकी पहचान वारासिवनी निवासी करीब 30 वर्षीय मयूर के रूप में हुई है। इस सड़क हादसे में मयूर को गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही कार सवार कौन थे, कहा से आ रहे थे इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नही आई है। लेकिन यह हादसा रविवार एवं सोमवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे घटित हुई है। वहीं बाइक व कार की क्षतिग्रस्त स्थिति को देखते हुए प्रतीत हो रहा है कि कार में सवार व्यक्तियों को भी मामूली चोटे आई होगी। वहीं घटना के बाद घायल बाइक सवार मयूर को राहगीरों व पुलिस की मदद से लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे जिला चिकित्सालय रिफर कर दिया है। वहीं सड़क हादसे की खबर मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

नहाने के लिए कुएं से पानी निकालते समय पैर फिसलने से मयाराम की मौत

पिपरिया छि. से अंत्येष्टि में शामिल होकर लौटा था मृतक, पुलिस मामले की जांच में जुटी

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जाम में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जहां नहाने के लिए कुएं से पानी निकालते समय अनियंत्रित होकर गिरने से एक 44 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, जिसका पोस्टमार्टम मंगलवार को किया जायेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जाम निवासी 44 वर्षीय मयाराम/युवराज दांदरे मजदूरी कार्य करता था। सोमवार को वह अपने किसी रिश्तेदार के निधन पर अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम पिपरिया छि गया हुआ था। वहां से शाम लगभग 4 बजे वह वापस अपने घर जाम लौटा था। घर पहुंचने के बाद मयाराम मकान के पीछे स्थित कुएं पर नहाने के लिए गया था। नहाने के दौरान जब वह कुएं से बाल्टी के जरिए पानी निकाल रहा था। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे गहरे पानी में जा गिरा। वहीं कुएं की ओर से अचानक कुछ गिरने की तेज आवाज सुनकर परिजन भागकर आये लेकिन कुएं के पास मयाराम के दिखाई न देने पर परिजनों को अनहोनी की शंका हुई। जिसके बाद परिजनों और पड़ोसियों ने स्थानीय स्तर पर लोहे के गल के माध्यम से उसे कुएं से बाहर निकालने का काफी प्रयास किये। लेकिन कुएं में पानी अत्यधिक होने के कारण जब तक उसे बाहर निकाला गया तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। जिसके बाद घटना की सूचना लालबर्रा पुलिस को दी गई। वहीं कुएं में गिरने से जाम में एक व्यक्ति की मौत हो जाने की जानकारी लगने पर थाना प्रभारी के निर्देश पर सहायक उपनिरीक्षक प्रशांत बंसोड़ पुलिसबल के साथ घटना स्थल पहुंचे एवं आवश्यक कार्यवाही कर शव को अपने कब्जे में लिया गया। जिसके बाद लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लाया गया किन्तु शाम हो जाने के कारण पोस्टमार्टम नही किया गया। शव को वि'छेदन गृह में सुरक्षित रखवा दिया गया है, मंगलवार सुबह शव का पोस्टमार्टम किया जायेगा। इस हृदयविदारक घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मृतक मयाराम मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। वह अपने पीछे पत्नि और दो छोटे बच्चों को छोड़ गया है। परिवार के मुखिया की असमय मौत से परिजनों के सामने अब जीविकोपार्जन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल लालबर्रा पुलिस मयाराम की मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है।

योजना का दिलवाया जायेगा लाभ - सुरेन्द्र

जाम के सरपंच सुरेंद्र बलोने ने बताया कि मयाराम दांदरे सोमवार को रिस्तेदारी में किसी की मृत्यु हो जाने पर पिपरिया छिं अंत्येष्टि कार्यक्रम में गया था, जहां से आने के बाद मकान के पीछे स्थित कुएं में नहाने के लिए गया था, तभी पानी निकालते समय पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गया और पानी में डुबने रहने से उसकी मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। श्री बलोने ने बताया कि मृतक परिवार का मुखिया था और यह दु:खद घटना है, जिससे पुरे ग्राम में शोक की लहर व्याप्त है, मृतक का पोस्टमार्टम मंगलवार को किया जायेगा। साथ ही यह भी बताया कि मृतक के परिजनों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाया जायेगा।

मामले की जांच की जा रही है - प्रशांत

दूरभाष पर चर्चा में सहायक उपनिरीक्षक प्रशांत बंसोड़ ने बताया कि जाम से सूचना मिली थी कि कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जिसके बाद घटना स्थल पहुंचकर शव बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की गई और शाम हो जाने के कारण दुसरे दिन मंगलवार को पोस्टमार्टम किया जायेगा। मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है।

थानेगांव में नहर माइनर खस्ताहाल

किसानों की सिंचाई की जीवन रेखा गर्त में

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम थानेगांव में सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ग्राम के सिरहाटोला से लेकर नाले तक जाने वाली नहर माइनर इस समय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आलम यह है कि किसानों को अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए दिन रात भारी मशक्कत और कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इसके बावजूद खेतों तक पानी कब पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। यह गंभीर समस्या पिछले कुछ वर्षों से लगातार बनी हुई है लेकिन जिम्मेदार सिंचाई विभाग मूकदर्शक बना बैठा है।

सैकड़ों एकड़ फसल पर संकट

प्राप्त जानकारी के अनुसार ढूटी घाट नहर की एक कैनाल मेंढकी के लिए निकलती है। इसी से ग्राम डोंगरगांव से एक माइनर थानेगांव के लिए आता है। पूरी तरह कच्ची होने के कारण इस नहर में जगह जगह छोटे बड़े गहरे गड्ढे हो गए हैं। कई स्थानों से नहर पूरी तरह टूट.फूट चुकी है जिसके चलते पानी सिरहाटोला से आगे थानेगांव तक पहुंच ही नहीं पाता है। इस माइनर पर क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि निर्भर है। पानी के अभाव में किसानों को फसल बचाना भारी पड़ रहा है। कई बार तो स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि फसल पकने के समय की सिंचाई नही मिलने के कारण खड़ी फसलें मार खा जाती हैं और किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती। विवश होकर किसानों को अन्य महंगे जल स्त्रोतों से पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है जिससे उन पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। नहर की सुध नही लिए जाने के कारण वर्तमान में पूरी माइनर झाड़ियों और मलबे से पट चुकी है। बेतहाशा उगी झाड़ियों और गंदगी ने पानी के बहाव को पूरी तरह रोक दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के द्वारा इसकी सामान्य साफ सफाई तक नहीं करवायी गई है। मरम्मत के अभाव में जीर्ण.शीर्ण हो चुकी यह माइनर अब अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। इस समस्या को लेकर बीते कुछ वर्षों में कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों को लिखित और मौखिक शिकायतें दी जा चुकी हैं। ग्रामीणों केद्वारा लगातार मांग की जा रही है कि व्यवस्था में सुधार करते हुए माइनर का जीर्णोद्धार किया जाए या इसकी लाइनिंग करवायी जायें। परंतु विभागीय अधिकारियों की लगातार अनदेखी के कारण आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विभाग की इस कार्यप्रणाली और उदासीनता को लेकर अब क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। किसानों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि तत्काल इस दिशा में तत्परता दिखाई जाए। नहर की व्यवस्थित रूप से मरम्मत कराई जाए जमी हुई गंदगी व झाडियों को साफकिया जाए और माइनर का लाइनिंग कार्य कराकर अंतिम छोर पर स्थित खेतों तक पानी सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को इस समस्या से स्थाई मुक्ति मिल सके।

शिकायत करने के बाद भी आज तक मरम्मत नहीं हुई-तपेश सुलकिया

किसान तपेश सुलकिया ने बताया कि नहर की बहुत भारी समस्या है। शिकायत कई बार की गई है परंतु आज तक मरम्मत नहीं हुई ना ही कोई अधिकारी के द्वारा इस समस्या पर ध्यान दिया गया है। जिसके चलते यह अति समस्या हो गई है इस नहर के आसपास करीब ८०० एकड़ कृषि भूमि स्थित है जो इस नहर पर आधारित है। जिसमें सिंचाई की दिक्कत बनी हुई है आज तक नहर का कचरा और झाड़ी की साफ सफाई नहीं हुई तो मरम्मत बहुत दूर का विषय हमें लग रहा है।

नहर की लाईनिंग कार्य नही होने से किसान को बहुत समस्या है-चमरू मात्रे

चमरू मात्रे ने बताया कि बड़ी नहर से यह माइनर नहर आती है और यह टेल का क्षेत्र पड़ता है। यहां पर पहले कुछ काम कराया गया था अंदर में तो उसमें नहर के अंदर की मिट्टी निकाली गई थी । परंतु नहर की पार या कोई भी व्यवस्थित काम नहीं हुआ है। आधे रास्ते पानी आता है यह समस्या को करीब ५ वर्ष हो गए हैं नहर वाले वसूली करने आते हैं पानी पहुंचाने नहीं। किसान को बहुत समस्या होती है हर बार वह विभाग के दरवाजे खटखटाता है परंतु उसे केवल निराशा ही प्राप्त हो रही है।

भविष्य में नहर का लाईनिंग कार्य नही हुआ तो नहर विलुप्त हो जायेगी-बद्दूलाल मानेश्वर

बद्दूलाल मानेश्वर ने बताया कि थानेगांव नाले तक यह नहर जाती है जो आधे रास्ते आती है। फिर जरूरत के आधार पर किसान कड़ी मशक्कत कर बांधकर अपनी अपने खेतों में लाता है परंतु वह भी आएगा नहीं आएगा वह पानी पर निर्भर है। पूरी नहर टूट फुट हो गई है जगह जगह गड्ढे है कई दिक्कतें हैं। जंगल में व्यर्थ में पानी बहता है सरलता से पानी आज तक कभी नहीं आया हम यही चाहते हैं कि किसान को समय पर पर्याप्त पानी मिले तो इस नहर को बनाना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा ही रहा तो किसान के लिए भविष्य में बहुत दिक्कत होगी और धीरे.धीरे यह नहर विलुप्त होने की कगार पर आ जाएगी जिसे किसानी और मुश्किल हो सकती है।

मां की डांट से नाराज होकर भिलाई से भागा १४ वर्षीय बालक वारासिवनी में मिला

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए परिजनों को सकुशल सौंपा

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। घरेलू मनमुटाव और माता पिता की सामान्य डांट फटकार के बाद आवेश में आकर घर छोड़ने वाले बच्चों से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से अपनी मां की डांट से आक्रोशित होकर बिना बताए घर से निकला एक १४ वर्षीय नाबालिग बालक ट्रेन के माध्यम से सफर करते हुए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वारासिवनी रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्थानीय नागरिकों की सजगता और वारासिवनी पुलिस की त्वरित व कार्यवाही के चलते बालक को सुरक्षित दस्तयाब कर उसकी मां को सौंप दिया गया है। प्राप्त

जानकारी के अनुसार बालक की पहचान आर्यन वाल्दे पिता महेन्द्र वाल्दे उम्र १४ वर्ष निवासी भिलाई पावर हाउस कैम्प २ भिलाई छत्तीसगढ़ के रूप में की गई है। आर्यन १२ जुलाई को अपनी मां की डांट से नाराज होकर अचानक घर से लापता हो गया था। परिजन छत्तीसगढ़ में उसकी हर जगह तलाश कर रहे थे लेकिन आवेश में आकर बालक ट्रेन में बैठ गया और वारासिवनी तक आ पहुंचा। १३ जुलाई को वारासिवनी रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात और अकेले बालक को संदिग्ध स्थिति में घूमता देख स्थानीय नागरिकों को संदेह हुआ। बालक काफी घबराया हुआ था नगर वासियों ने जिम्मेदारी का परिचय देते हुए तत्काल इसकी सूचना स्थानीय वारासिवनी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही वारासिवनी थाना प्रभारी के कुशल निर्देशन में पुलिस टीम तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंची और बालक को अपनी सुरक्षा में लेकर थाने आई। पुलिस कर्मियों ने जब बालक को पुचकारा और आत्मीयता से पूछताछ की तब उसने बताया कि वह मां की डांट के कारण आक्रोश में आकर घर से भाग आया था। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए बालक के बताए पते और परिजनों से संपर्क साधा और उसकी मां श्रीमती जया पति महेन्द्र वाल्दे को बालक के सुरक्षित होने की सूचना दी। बेटे के मिलने की खबर पाकर परिजन तुरंत वारासिवनी पहुंचे। जहां कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने बालक आर्यन को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। अपने जिगर के टुकड़े को सकुशल वापस पाकर मां की आंखें छलक आईं और उन्होंने वारासिवनी पुलिस व नगर वासियों का दिल से आभार व्यक्त किया। इस त्वरित और सफल दस्तयाबी में थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके ,प्रधान आरक्षक रामप्रसाद भराने ,जावेद खान एवं भानू बसेने का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि बच्चों के मनोविज्ञान को समझें और उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करें। साथ ही किसी भी स्टेशन या सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई बच्चा अकेला या भटकता हुआ दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि किसी अनहोनी को रोका जा सके।

बूथ को मजबूत करें कार्यकर्तागण चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित-सुमेरसिंह सोंलकी

भाजपा कार्यालय में कामकाजी बैठक आयोजित

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी भाजपा कार्यालय में प्रदेश महामंत्री डॉ. सुमेरसिंह सोंलकी की अध्यक्षता में कामकाजी बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संगठन के हिसाब से कार्य करने के लिये प्रेरित किया गया। नगर मंडल वारासिवनी की काम काजी बैठक में विशेष रूप से प्रदेश महामंत्री डॉ. सुमेरसिंह सोंलकी,जिला प्रभारी अभिलाष मिश्रा, जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे, सांसद श्रीमती भारती पारधी, पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, विधायक गौरव सिंह पारधी, उपाध्यक्ष किशोर अमूले,विधानसभा प्रभारी जितेन्द्र मोहारे, अभय कोचर, जिला महामंत्री नरेन्द्र भैरम, पूर्व नपा अध्यक्ष श्रीमती स्मिता जायसवाल, नपा अध्यक्ष सरिता मनोज दांदरे, नपा उपाध्यक्ष श्रीमती प्रीति संतोष शिव , नगर मंडल अध्यक्ष संदीप मिश्रा, मिलिंद नगपुरे, वेदप्रकाश पटेल की मौजूदगी में बैठक प्रांरभ की गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री डॉ. सुमेरसिंह सोंलकी ने भाजपा कार्यकर्ताओं की क्लास लेते हुये पार्टी की रीति निती से परिचय कराते हुये मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होने जानकारी में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व ग्रहमंत्री अमित शाह भी अपने अपने बूथ के अध्यक्ष है। और भाजपा में कार्यकर्ताओं का ही सबसे ज्यादा महत्व है और आज हमारी भाजपा का परिवार १२ करोड़ से ज्यादा सदस्यों का हो चुका है। श्री सोलंकी ने प्रत्येक बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री व पन्ना प्रभारीयों की कार्यशैली से वन टू वन में परिचीत होते हुये कहा की भाजपा के सत्ता में जितने भी प्रतिनिधी है वह कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही महत्तवपूर्ण पदो तक पहुंचे है। पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है तो उसका निर्वहन हमे लगन व ईमानदारी से करना है। यह भाजपा है जो पिछली पंक्ति के कार्यकर्ताओं को भी अचानक सबसे आगे करके अग्रिम पंक्ति में खडी कर देती है। पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा की आज प्राय सभी राज्यो में भाजपा की सरकार बन रही है। विशेषकर पश्चिम बंगाल में भी हमारी भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इसके पीछे पिछले दस साल की नेत्रत्व की मेहनत व सैकडो कार्यकर्ताओं का बलिदान है। श्री जायसवाल ने कहा की जब पूर्व में राज्यसभा सदस्य के लिये चुनाव हुये थे। तब तात्कालिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरी माताश्री के शांत होने के बाद विशेष विमान भोपाल से भेजकर मुझे वोट डालने भोपाल बुलवाया था। और नियमानुसार वह वोट उस समय के राज्यसभा के सदस्य डॉ. सुमेरसिंह सोंलकी को मेरे द्वारा दिया गया था। इस जानकारी के बाद डॉ. सुमेरसिंह सोंलकी ने भी गुडडा भैया की ओर इशारा करते हुये कहा की विशेष विमान भेजने की यह ताकत हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही थी। आज भी पार्टी की नजर में कार्यकर्तागणो की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। बैठक में जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने कहा की आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी कार्ययोजनाओं की समीक्षा करना और संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सशक्त बूथ संगठन है। बूथ पर कार्य करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव का वास्तविक योद्धा होता है। हमें अपनी विचारधारा, पार्टी की रीति नीति और केंद्र,राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर और हर मतदाता तक पहुँचाना है। जिला प्रभारी अभिलाष मिश्रा ने कहा की जिस दिन हम अपने बूथ को मजबूत कर लेंगे। उसी दिन हमे चुनाव के परिणाम के पहले ही कितने वोटो से विजयश्री होगी, इसका आंकलन भी सामने आ जायेगा। वारासिवनी का संगठन बेहद मजबूत है और आने वाले सभी चुनावो में भाजपा की जीत कार्यकर्ताओं के कारण होनी तय भी है। बैठक मे चिरौंजी पारधी, प्रवीण खरोले, सुनील बंटी पारधी,केशव सिंह बैस, प्रबल जायसवाल,शैलेन्द्र तिवारी, अमित येरपूडे, विनोद मिश्रा, प्रवीण रूसिया, मदन धार्मिक, पवन धूर्वे,मनोज लिल्हारे,आलोक खरे,मोनू लिमजे,संजय गुप्ता, शानू सिंघई, अरमान खान,मिथलेश बुरडे, शंशाक डोंगरे, मंयक मिश्रा, अनिश मिश्रा ,श्रीमती निर्मला पटले,रीना कासल, सीमा पारधी, तुलसी शर्मा, शीतल अरोरा,दीपा रूसिया,ललिता ठाकरे, कोमल व्यास,श्रीति पालेवार, मिनाक्षी ठाकरे उपस्थित रही।

डिवाइडर से टकराई एक्टिवा, राजू कटरे घायल अस्पताल में उपचार जारी

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। नगर के बालाघाट मार्ग स्थित हीरो शोरूम के पास सोमवार की दोपहर एक सड़क दुर्घटना में एक्टिवा सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल लाइन वार्ड नंबर १५ निवासी राजू कटरे पिता श्रीराम कटरे दोपहर के समय अपनी एक्टिवा क्रमांक एम पी ५० एम जी २१२५ से किसी निजी काम के लिए निकले थे। जैसे ही वह बालाघाट रोड स्थित बैगा मोहल्ले की गली से मुख्य सड़क की ओर आए तभी अचानक सामने कुछ स्कूली बच्चे आ गए। स्कूली विद्यार्थियों को टक्कर से बचाने के प्रयास में राजू कटरे ने अपने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया जिससे उनकी तेज रफ्तार एक्टिवा सीधे सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजू कटरे सड़क पर गिरकर चोटिल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल ११२ की टीम ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उनका उपचार अस्पताल में जारी है।

प्राध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन

कई वर्षों से लंबित जायज मांगों के लिए लगाई गुहार

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय वारासिवनी के प्राध्यापकों ने सोमवार को अपनी कई वर्षों से लंबित जायज मांगों के शीघ्र निराकरण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है। प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ वारासिवनी इकाई के तहसील अध्यक्ष डॉ हेमन्त कुमार मण्डाले ने बताया कि प्रांतीय प्राध्यापक संघ की प्रबंधकारिणी की भोपाल में ९ जुलाई को आपात बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि १० जुलाई से प्रदेश के शासकीय कालेजों के प्राध्यापकों के चरणबद्ध आंदोलन के द्वितीय चरण में कालीपट्टी बांधकर काम करने के स्थान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सामूहिक ज्ञापन सौंपकर वर्षों से लंबित जायज मांगों के निराकरण हेतु अवगत कराया जायेगा। ज्ञात हो कि प्रांतीय प्राध्यापक संघ के आव्हान पर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षको, क्रीड़ा अधिकारियों एवं ग्रंथपालों के द्वारा अपनी ६ सूत्रीय वैधानिक मांगों के लिए प्रदेश स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन के प्रथम चरण में १ जुलाई से कालीपट्टी बांधकर काम करके सांकेतिक विरोध दर्ज कराते हुए शासन का ध्यान आकर्षित किया था। प्रांतीय प्राध्यापक संघ के द्वारा बार बार ज्ञापन सौंपने एवं

चर्चा के बाद भी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कई वर्षों से लंबित मांगों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। कुछ मांगें तो पिछले २० वर्षों से लंबित हैं। प्राध्यापकों में विभाग की निष्क्रियता एवं लचर प्रणाली के कारण गहरा रोष एवं असंतोष व्याप्त है, वर्ष २००४ एवं २००५ में नियुक्त बैकलॉग असिस्टेंट प्रोफेसरों की परिवीक्षा अवधि नियुक्ति दिनांक से २ वर्ष में समाप्त कर उन्हें यूजीसी नियमानुसार कैरियर एडवांसमेंट का लाभ दिया जाये ,तथा जिन असिस्टेंट प्रोफेसरों ने अभी निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं की है उन्हें वर्ष २०२८ तक योग्यता अर्जित करने का अवसर प्रदान किया जायें,क्रीड़ा अधिकारियों एवं ग्रंथपालों को असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पदनाम दिया जाये तथा उनकी सेवानिवृति की आयु में वृद्धि कर ६५ वर्ष की जाये, साथ ही यूजीसी प्रावधानानुसार पे.मैट्रिक्स १४ का लाभ दिया जाये,वर्ष २००९, २०११ व २०१९ में नियुक्त, नियमितीकरण से वंचित असिस्टेंट प्रोफेसरों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की जाये एवं उन्हें यूजीसी नियमानुसार कैरियर एडवांसमेंट का लाभ शीघ्र दिया जाये। छानबीन समिति की बैठक प्रति सप्ताह एवं विषयवार आयोजित की जाये,असिस्टेंट प्रोफेसरों एवं एसोसिएट प्रोफेसरों को पात्रता अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर पदनाम दिया जाये, सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन, वेतन निर्धारण, अर्जित अवकाश एवं समूह बीमा भुगतान को प्राथमिकता दी जाये,सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार परामर्शदात्री समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जाये, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पिछले १० वर्षों से परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है। इस दौरान डॉ सुरेंद्र खंडायत, दोमदत्त सिंह, डॉ त्रिरत्नेश गजभिये, नरेंद्र डोंगरे ,हेमन्त गणवीर विकास साहू मौजूद रहे।

न भूतो,न भविष्यति-इस्सयोग आध्यात्मिक क्रांति

विज्ञान,तकनीक और भौतिक उपलब्धियों के इस युग में मनुष्य ने पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी विजय का परचम लहरा दिया है। जीवन पहले की अपेक्षा अधिक सुविधासंपन्न हुआ है।संचार के साधनों ने दूरियों को लगभग समाप्त कर दिया है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर मानव सभ्यता को नई दिशा दे रहा है।फिर भी यदि कोई सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है,तो वह है—मनुष्य के भीतर बढ़ती मानसिक अशांति, तनाव,अकेलापन और आत्मिक रिक्तता। बाहरी समृद्धि के बीच भी मन की शांति आज दुर्लभ होती जा रही है। ऐसे समय में भारतीय अध्यात्म की सनातन परम्परा पुन: प्रासंगिक हो उठती है,जिसने सदैव मनुष्य को बाहर नहीं,अपने भीतर झाँकना सिखाया है।भारत की गुरु-शिष्य परम्परा केवल धार्मिक आस्था की नहीं,बल्कि आत्मबोध, लोककल्याण और मानवीय मूल्यों की परम्परा रही है।जब-जब समाज दिशाहीन हुआ,तब-तब किसी संत- महापुरुष ने अपने जीवन से मानवता को नई दिशा दी।ब्रह्मलीन महात्मा सुशील कुमार जी ऐसे ही विरल संतों में गिने जाते हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक साधना को जन-जन तक पहुँचाने का सहज,सरल और अनुभवपरक मार्ग प्रदान किया, जिसे आज विश्व इस्सयोग के नाम से जानता है।13 जुलाई उनके अनुयायियों के लिए केवल जन्मदिवस नहीं,बल्कि आत्ममंथन, साधना और गुरु-चिंतन का पावन पर्व है।वर्ष 1938 में बिहार के भोजपुर जनपद में वैदिक विद्वान श्री श्रीशचंद्र शास्त्री तथा पूजनीया कर्पूर कमला जी के घर जन्मे महात्मा सुशील कुमार जी को अध्यात्म संस्कारों के रूप में विरासत में मिला।उनके पिता चारों वेदों के प्रकाण्ड ज्ञाता,संस्कृत के विद्वान और आर्य समाज के प्रतिष्ठित आचार्य थे।भारत सरकार उन्हें थाईलैंड,श्रीलंका सहित अनेक देशों में वेद और संस्कृत के प्रचार- प्रसार के लिए भेजती थी।माता कर्पूर कमला जी भी विदुषी और समाजसेवा के प्रति समर्पित थीं। ऐसे वातावरण में बालक सुशील के मन में बचपन से ही सत्य,ईश्वर और जीवन के रहस्यों को जानने की तीव्र जिज्ञासा जाग उठी।गायत्री मंत्र, वैदिक संस्कार और आत्मानुशासन ने उनके व्यक्तित्व की मजबूत आधारशिला रखी।महात्मा सुशील कुमार जी का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि आध्यात्मिकता और कर्मयोग एक-दूसरे के पूरक हैं।उन्होंने वर्ष 1961 में सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की तथा बाद में विधि की पढ़ाई भी पूरी की।बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग में अभियंता के रूप में उन्होंने महात्मा गांधी सेतु,बोकारो इस्पात परियोजना तथा अनेक राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया।नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी उन्होंने निर्भीक होकर विकास कार्य सम्पन्न कराए।उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 1997 में उन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी सम्मान से सम्मानित किया गया।किन्तु उनकी वास्तविक पहचान एक सफल अभियंता या प्रशासक भर नहीं थी। उनके भीतर का साधक निरंतर उस परम सत्य की खोज में लगा था, जिसे पद, प्रतिष्ठा या पुरस्कार से प्राप्त नहीं किया जा सकता।उन्होंने यह सिद्ध किया कि आध्यात्मिक उपलब्धि केवल हिमालय की गुफाओं में नहीं,बल्कि गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी प्राप्त की जा सकती है।वे कहा करते थे कि गृहस्थ आश्रम त्याग का नहीं,बल्कि साधना का श्रेष्ठतम आश्रम है।यदि जीवन में सच्चे सद्गुरु का सान्निध्य मिल जाए तो परिवार ही तपोवन बन जाता है और दैनिक कर्म साधना का माध्यम।यही भारतीय दर्शन की वह परम्परा है जिसमें राजा जनक जैसे गृहस्थ भी ब्रह्मज्ञानी कहलाए।18 मई 1963 को उनका विवाह पूज्य माँ विजया जी के साथ हुआ।यह केवल वैवाहिक संबंध नहीं,बल्कि दो आध्यात्मिक यात्राओं का दिव्य संगम था। दोनों ने साथ-साथ साधना का कठिन मार्ग अपनाया। प्रारम्भ में उन्हें एक लौकिक गुरु से दीक्षा मिली,किन्तु साधना की गहराइयों में उन्होंने अनुभव किया कि स्वयं सद्गुरु भगवान शिव उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं।

न्यायपालिका के खिलाफ फैल रहा असंतोष स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक

भारतीय लोकतंत्र की सफलता का आधार उसके चार प्रमुख स्तंभ—विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया—हैं। इनमें न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक माना जाता है। न्यायपालिका केवल विवादों का निपटारा करने वाली संस्था नहीं, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता, विधि के शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाली व्यवस्था है। जब नागरिकों को शासन, प्रशासन अथवा अन्य संस्थाओं से न्याय नहीं मिलता, तब उनकी अंतिम आशा न्यायपालिका ही होती है। किन्तु हाल के वर्षों में न्यायपालिका को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष, आलोचना और बहस का दायरा बढ़ा है। न्यायिक निर्णयों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ, लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, पारदर्शिता के प्रश्न तथा सोशल मीडिया पर फैलती अधूरी जानकारी ने इस असंतोष को और अधिक चर्चा का विषय बना दिया है। ऐसे में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या न्यायपालिका के प्रति बढ़ता असंतोष उसकी गरिमा और विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहा है, अथवा यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है? ऐसा असंतोष अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप ने जजों को न्यायिक सेवक कहा और फिर सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कोर्टरूम में कागज भी उछाले। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उस वकील को कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया, पर कोर्ट ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया है। इस पर कोर्ट के संबंधित न्यायधीश की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने अपना धैंय बना कर उच्चतम न्यायालय का सम्मान रखा उसे इस कृत्य के लिए माफ कर दिया है। इसे विस्तारपूर्वक समझना होगा।

असंतोष के प्रमुख कारण-

1. न्याय में अत्यधिक विलंब

भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती न्याय मिलने में होने वाली देरी है। देश की विभिन्न अदालतों में करोड़ों मामले वर्षों से लंबित हैं। अनेक दीवानी और फौजदारी मुकदमे दशकों तक चलते रहते हैं। प्रसिद्ध उक्ति है—विलंबित न्याय, न्याय से वंचित करना है। जब किसी व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिलता, तो उसका न्यायपालिका पर विश्वास कमजोर होने लगता है।

2. न्यायाधीशों के रिक्त पद और संसाधनों की कमी

देश की अनेक अदालतों में न्यायाधीशों के हजारों पद लंबे समय तक रिक्त रहते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में आधुनिक तकनीक, पर्याप्त न्यायिक कर्मचारी, आधारभूत ढाँचे और डिजिटल सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिलता है। बढ़ते मामलों और सीमित संसाधनों के कारण न्यायिक प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है।

3. न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर विवाद

कॉलेजियम प्रणाली लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। इसके समर्थकों का मानना है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, जबकि आलोचकों का तर्क है कि इसमें पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। नियुक्तियों में देरी तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समय-समय पर उत्पन्न मतभेद भी जनता के बीच भ्रम और असंतोष उत्पन्न करते हैं।

4. संवेदनशील मामलों में विवाद

कुछ राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक महत्व के मामलों में दिए गए न्यायिक निर्णयों को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलती हैं। कई बार न्यायालय के निर्णयों का मूल्यांकन कानूनी आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक अथवा वैचारिक दृष्टिकोण से किया जाता है। इससे न्यायपालिका पर अनावश्यक दबाव और अविश्वास का वातावरण बन सकता है।

5. सोशल मीडिया और सूचना का दुष्प्रचार

डिजिटल युग में सोशल मीडिया सूचना का सबसे तेज माध्यम बन चुका है। किंतु अधूरी जानकारी, झूठे दावे, भ्रामक वीडियो और न्यायिक निर्णयों की गलत व्याख्या जनता में भ्रम पैदा करती है। कई बार न्यायालय के पूरे निर्णय को पढ़े बिना केवल कुछ अंशों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। इससे न्यायपालिका की छवि प्रभावित होती है।

क्या असंतोष न्यायपालिका की गरिमा को प्रभावित करता है?

लोकतंत्र में किसी भी संस्था की आलोचना अस्वाभाविक नहीं है। न्यायपालिका भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, इसलिए उसके निर्णयों और कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाना नागरिकों का अधिकार है। किंतु यह आलोचना तथ्यों, संवैधानिक मूल्यों और कानूनी समझ पर आधारित होनी चाहिए।जब आलोचना रचनात्मक होती है, तब वह सुधार का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके विपरीत यदि आलोचना व्यक्तिगत आरोपों, राजनीतिक प्रचार, झूठी सूचनाओं या न्यायाधीशों की निष्ठा पर निराधार प्रश्नों के रूप में सामने आती है, तो यह न्यायपालिका की गरिमा और जनता के विश्वास दोनों को नुकसान पहुँचाती है।न्यायपालिका की शक्ति जनता के विश्वास पर आधारित होती है। यदि नागरिकों का भरोसा कमजोर होता है, तो विधि के शासन की अवधारणा भी प्रभावित होती है। इसलिए गरिमा की रक्षा केवल न्यायपालिका की ही नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की आवश्यकता है।

न्यायपालिका की उपलब्धियाँ-

भारतीय न्यायपालिका की आलोचनाओं के बीच उसके ऐतिहासिक योगदान को भूलना उचित नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर संविधान की मूल भावना की रक्षा की है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, महिलाओं के अधिकारों, बच्चों के अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना के अधिकार तथा सामाजिक न्याय से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है।जनहित याचिका की व्यवस्था ने गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम प्रदान किया। न्यायपालिका ने कई अवसरों पर कार्यपालिका और विधायिका की मनमानी पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित कर लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखा।

कोविड-19 महामारी के दौरान भी अनेक न्यायालयों ने स्वास्थ्य सुविधाओं, ऑक्सीजन उपलब्धता, प्रवासी मजदूरों तथा नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई। इससे स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों की संरक्षक भी है।

न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता

लोकतंत्र में न्यायपालिका की गरिमा केवल न्यायाधीशों के सम्मान का प्रश्न नहीं है, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता का प्रश्न है। यदि न्यायालयों के प्रति जनता का विश्वास समाप्त हो जाए, तो लोग कानून के बजाय अन्य माध्यमों से विवादों का समाधान खोजने लगेंगे, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।इसलिए न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल, मीडिया और राज्य की सामूहिक जिम्मेदारी है। न्यायालयों की आलोचना अवश्य होनी चाहिए, परंतु वह तथ्यों, संवैधानिक मर्यादा और कानूनी तर्कों पर आधारित होनी चाहिए।भारतीय न्यायपालिका के प्रति बढ़ता असंतोष एक गंभीर विषय है, किंतु इसे केवल न्यायपालिका की विफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की निरंतर समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया का भी संकेत है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही—दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। एक ओर न्यायालयों को अधिक पारदर्शी, त्वरित और सुलभ बनाना होगा, वहीं दूसरी ओर समाज, मीडिया और राजनीतिक नेतृत्व को भी न्यायपालिका के प्रति संयमित, तथ्याधारित और जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाना होगा।

लोकतंत्र की मजबूती केवल मजबूत कानूनों से नहीं, बल्कि उन संस्थाओं पर जनता के अटूट विश्वास से सुनिश्चित होती है जो उन कानूनों की रक्षा करती हैं। भारतीय न्यायपालिका की गरिमा, निष्पक्षता और स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है।

इसलिए आलोचना और सम्मान, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए न्यायपालिका में आवश्यक सुधारों को आगे बढ़ाना ही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

सुधार की दिशा

बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक हैं—

न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।

न्यायिक अवसंरचना का आधुनिकीकरण किया जाए।

ई-कोर्ट, डिजिटल फाइलिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाए।

नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।

लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाए जाएँ।

मध्यस्थता, लोक अदालत और वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए।

न्यायिक निर्णयों को सरल भाषा में उपलब्ध कराया जाए ताकि आम नागरिक भी उन्हें समझ सकें।

मीडिया और सोशल मीडिया पर न्यायिक मामलों की तथ्यपरक एवं जिम्मेदार रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया जाए।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक, विधि विचारक है।)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

-सौरभ वार्ष्णेय

सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और न्याय की संवेदना

-कांतिलाल मांडोत

देश की सर्वोच्च अदालत केवल एक न्यायिक संस्था नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की अंतिम आशा का केंद्र है। जब देश का कोई नागरिक हर स्तर पर न्याय की तलाश में असफल होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो उसके मन में यही विश्वास होता है कि यहां उसकी बात निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ सुनी जाएगी। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा पूरे न्यायिक तंत्र की आधारशिला मानी जाती है। अदालत की गरिमा बनाए रखना जितना न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मचारियों का दायित्व है, उतना ही वहां उपस्थित प्रत्येक अधिवक्ता, याचिकाकर्ता और नागरिक का भी कर्तव्य है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता वकील द्वारा न्यायाधीशों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कागजात उछालना और मुख्य न्यायाधीश के लिए अपशब्द कहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी भी परिस्थिति में न्यायालय के भीतर इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता। अदालत तर्क और कानून की भाषा समझती है, आक्रोश और अपमान की नहीं। यदि न्याय की लड़ाई लड़ने वाला स्वयं कानून और शिष्टाचार की सीमाएं लांघने लगे, तो न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर होने का खतरा पैदा हो सकता है। वकील केवल अपने मुवक्किल का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह न्यायालय का भी अधिकारी माना जाता है। उसकी वाणी, उसका आचरण और उसका व्यवहार न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा होता है। इसलिए अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संयम बनाए रखें। असहमति व्यक्त करने का अधिकार सभी को है, लेकिन असहमति और अभद्रता के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। उस रेखा का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक संस्कृति और न्यायिक परंपरा की पहचान है। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अदालत ने वकील की याचिका खारिज कर दी, लेकिन उसके खिलाफ अवमानना की कठोर कार्रवाई नहीं की। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि वह व्यक्ति संभवत: अत्यधिक तनाव और मानसिक दबाव में है तथा उसकी हताशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह दृष्टिकोण न्यायपालिका की मानवीय संवेदना को भी सामने लाता है। कानून केवल दंड देने का माध्यम नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को समझने और न्याय के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखने की व्यवस्था भी है। वास्तविकता यह है कि न्याय की तलाश में अदालत तक पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा, संघर्ष या अन्याय का बोझ लेकर आता है। वर्षों तक मुकदमे लड़ने, आर्थिक बोझ उठाने और बार-बार अदालतों के चक्कर लगाने के बाद जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, तब कई लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं। यह टूटन कभी-कभी हताशा और असंतुलित व्यवहार के रूप में सामने आती है। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे व्यवहार को उचित ठहराया जाए, बल्कि यह समझना आवश्यक है कि उसके पीछे पीड़ा और निराशा का एक लंबा इतिहास भी हो सकता है। न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता के साथ-साथ उसकी संवेदनशीलता भी है। यदि कोई व्यक्ति अदालत में अत्यधिक तनावग्रस्त दिखाई देता है, तो उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार करते हुए उसकी मानसिक स्थिति को भी समझना चाहिए। न्याय केवल आदेश सुनाने से पूरा नहीं होता, बल्कि यह विश्वास भी पैदा करता है कि अदालत ने व्यक्ति की बात पूरी गंभीरता से सुनी और समझी। यही विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है। यह भी सच है कि न्याय में विलंब, लंबी कानूनी प्रक्रिया और बढ़ते मुकदमों का बोझ कई लोगों में निराशा पैदा करता है। ऐसे में न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में लगातार प्रयास आवश्यक हैं। जब लोगों को समय पर न्याय मिलेगा, तो निराशा और असंतोष की स्थितियां भी कम होंगी। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों का निपटारा नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और संतुलन बनाए रखना भी है। इस घटना ने एक और संदेश दिया है कि न्यायालय की गरिमा बनाए रखने में सभी की समान जिम्मेदारी है। यदि अदालत में अनुशासन समाप्त हो जाए, तो न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी और इसका नुकसान अंतत: आम नागरिक को ही होगा। इसलिए चाहे वह वरिष्ठ अधिवक्ता हों, नए वकील हों या स्वयं पक्षकार, सभी को यह समझना होगा कि अदालत में शब्दों का चयन, व्यवहार की मर्यादा और कानून के प्रति सम्मान सर्वोपरि है। दूसरी ओर न्यायपालिका की उदारता भी सराहनीय है। यदि अदालत चाहती तो अवमानना की कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उसने संयम दिखाया और कठोर दंड देने के बजाय मामले को वहीं समाप्त करना उचित समझा। यह निर्णय बताता है कि न्याय केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और करुणा का संतुलित स्वरूप है।

नशा मुक्त भारत ञ्च 2029 -औषधीय (अदरक, इलायची और पुदीने के टिंचर) की आड़ में छिपतें नशे पर कानून का डंडा

वैश्विक स्तरपर दवा और मादक पदार्थों के बीच की धुंधली होती लकीर वर्तमान समय में वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती बन चुकी है। पारंपरिक रूप से समाज जिन रसायनों को चिकित्सा,शारीरिक रिकवरी और उपचार का माध्यम मानता आया है,आज वही रसायन एक छिपे हुए वैश्विक महामारी के रूप में युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। इस गंभीर संकट को भांपते हुए,भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक युगांतकारी कदम उठाते हुए औषधि नियम,1945 में ऐतिहासिक संशोधन किया है।भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक गज़ट नोटिफिकेशन 8 जुलाई 2026 (डी.एस.आर.607(ई) को जारी किया गया,आधिकारिक गज़ट में प्रकाशित होने के बाद, इन नए सख्त नियमों को देश भर में पूरी तरह प्रभावी होने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। इस प्रकार, दवा निर्माताओं और फार्मेसियों के लिए यह संशोधन जनवरी 2027 से अनिवार्य रूप से लागू माना जाएगा ताकि तब तक उद्योग जगत पैकेजिंग और फॉर्मूलेशन में आवश्यक बदलाव कर सके इस नए कानून के तहत अब ऐसी सभी ओरल लिक्विड (तरल) दवाएं, जिनमें एथिल अल्कोहल की मात्रा 12 प्रतिशत वी /वी से अधिक है और जिनकी पैकिंग 30 मिलीलीटर से बड़ी है,उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए शेड्यूल एच1 के दायरे में ला दिया गया है। इस कठोर विनियामक हस्तक्षेप का प्राथमिक और मूल उद्देश्य देश में कफ सिरप, टॉनिक, पाचक द्रव्यों और अन्य सुगंधित औषधीय मिश्रणों के रूप में धड़ल्ले से किए जा रहे गैर-चिकित्सीय नशे और फार्मास्युटिकल दुरुपयोग की जड़ों पर प्रहार करना है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र अधिवक्ता होने के नाते बता दूं कि नशे के आदी लोगों और विशेषकर किशोरों द्वारा कानून की कमियों का फायदा उठाकर किया जाने वाला यह दुरुपयोग केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक विनियामक चिंता का विषय रहा है। लंबे समय से कुछ विशिष्ट औषधीय फॉर्मूलेशन,जैसे कि अदरक, इलायची और पुदीने के टिंचर तथा कई पारंपरिक स्वास्थ्य टॉनिक, औषधि नियम,1945 के शेड्यूल के, के तहत लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से पूरी तरह मुक्त थे।इस छूट कापरिणाम यह हुआ कि जिन दवाओं में अल्कोहल की सांद्रता 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक थी,वे भी बाजार में बिना किसी सख्त निगरानी के ओवर-द- काउंटर यानी बिना पर्ची के आसानी से उपलब्ध थीं। कई राज्य सरकारों द्वारा इस पर गहरी चिंता जताए जाने के बाद केंद्र सरकार ने शेड्यूल से इस छूट को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है, जिससे अब इन दवाओं के निर्माण, भंडारण और वितरण के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। यह संशोधन सीधे तौर पर उस छिपे हुए और सामाजिक रूप से स्वीकृत नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ता है, जो बिना किसी रोक-टोक के समाज में सटीकता से जहर घोल रही थी। साथियों बात अगर हम विशिष्ट विनियामक कानूनीधाराएं और दंडात्मक प्रावधानइस कानून को जमीन पर सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने इसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ,1940 के दंडात्मक प्रावधानों से जोड़ा है। अधिनियम की धारा 18(सी) के तहत बिना वैध निर्माण या बिक्री लाइसेंस के इन दवाओं का भंडारण या वितरण करना एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा। नए संशोधनों के तहत-शेड्यूल एच1 नियमों के प्रथम उल्लंघन पर- यदि कोई केमिस्ट या फार्मासिस्ट पहली बार बिना डॉक्टर के पर्चे के 12 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल वाली दवा बेचते या बिक्री का 3 वर्ष का रिकॉर्ड न मेंटेन करते हुए पकड़ा जाता है, तो राज्य दवा नियामक प्राधिकरण द्वारा उसका लाइसेंस 15 से 30 दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है।बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर- यदि कोई रिटेलर जानबूझकर नियमों की अवहेलना जारी रखता है, तो अधिनियम की धारा 27(डी) के तहत उसका दुकान लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ही उसे न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर अधिकतम 5 वर्ष तक की जेल की सजा और कम से कम 1 लाख रुपये का भारी वित्तीय जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है।सिंडिकेट या थोक डायवर्जन के मामले में- यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर ने जानबूझकर नशे के सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने के लिए थोक स्तर पर इन दवाओं की काला बाजारी की है, तो अपराध की गंभीरता को देखते हुए धारा 27(ए) के तहत आजीवन कारावास तक की कड़ी सजा का प्रावधान सटीकता से लागू हो सकता है। साथियों, समकालीन विश्व में मादक पदार्थों के सेवन के तरीकों में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट या संरचनात्मक बदलाव देखा गया है। अब पारंपरिक अवैध ड्रग्स जैसे हेरोइन, चरस या कोकीन के बजाय, युवा वर्ग कानूनी रूप से उपलब्ध फार्मास्युटिकल दवाओं के दुरुपयोग की ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण इन दवाओं का अत्यंत सस्ता होना, आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाना, गंधहीन होना और पारंपरिक नशीले पदार्थों की तरह पकड़े जाने का सामाजिक कलंक या कानूनी डर न होना है। कफ सिरप (जैसे कोडीन आधारित या उच्च अल्कोहल युक्त सिरप) और रिस्टोरेटिव टॉनिक का अत्यधिक मात्रा में सेवन कर तत्काल हाई प्राप्त करना एक वैश्विक फैशन बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रवृत्ति को फार्मा-विंडिंग या औषधीय नशे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां लोग मानसिक तनाव,अकेलेपन या तात्कालिक आनंद के लिए दवाओं की पूरी की पूरी बोतलें एक बार में पी जाते हैं। साथियो,नशे के इस नए चलन ने चिकित्सा विज्ञान, समाज शास्त्रियों और नीति निर्माताओं को समान रूप से गहराई से चिंतित किया है। उच्च अल्कोहल सांद्रता वाली ये दवाएं, जब बिना किसी चिकित्सीय आवश्यकता के अत्यधिक मात्रा में शरीर में जाती हैं, तो यह सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं और व्यक्ति की निर्णय क्षमता को शून्य कर देती हैं। लंबे समय तक इस तरह का सेवन करने से लीवर सिरोसिस, किडनी का फेल होना, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, हृदय संबंधी विसंगतियां और गंभीर मानसिक विकार जैसे अपरिवर्तनीय स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं। कई मामलों में, किशोर इन कफ सिरप और टॉनिकों को अन्य सिंथेटिक दवाओं, अवसादरोधी गोलियों या नशीली गोलियों के साथ मिलाकर एक जानलेवा कॉकटेल तैयार करते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल किसी एक देश की सीमा तक सीमित है, बल्कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीपों में भी इसी तरह के फार्मास्युटिकल उत्पादों के डायवर्जन (गलत इस्तेमाल के लिए वितरण) की गंभीर घटनाएं लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सटीकता से रिपोर्ट की गई हैं। साथियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकार का यह संशोधन एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। चिकित्सा जगत में दवाओं का उपयोग हमेशा तर्कसंगत,नियंत्रित और साक्ष्य- आधारित होना चाहिए, न कि उपभोक्ता की सनक पर आधारित।जब सामान्य नागरिक सर्दी-खांसी, सामान्य थकान या मामूली कमजोरी के लिए खुद ही मेडिकल स्टोर से जाकर उच्च अल्कोहल युक्त हैवी टॉनिक खरीदकर पीने लगते हैं, तो वे अनजाने में ही अपनी शारीरिक प्रणालियों को गंभीर खतरे में डाल रहे होते हैं। स्व- दव की इस घातक आदत के कारण वास्तविक बीमारी के लक्षण तो कुछ समय के लिए छिप जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को अल्कोहल और अन्य रसायनों की गंभीर लत लग जाती है।इस संशोधन के माध्यम से सरकार ने एक बेहद स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा किसी भी व्यावसायिक लाभ या औद्योगिक सुगमता से बहुत ऊपर है, इन दवाओं को शेड्यूल एच 1 में स्थानांतरित करने से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति केवल और केवल डॉक्टर की लिखित सलाह पर ही इनका उपभोग कर सकेगा।

यह कदम अंतत: समाज में दवाओं के प्रति एक जिम्मेदार और सचेत व्यवहार विकसित करेगा। जब दवाओं की उपलब्धता को वैज्ञानिक आधार पर तर्कसंगत बनाया जाता है, तो इसके दीर्घकालिक परिणाम देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले वित्तीय, सामाजिक और प्रशासनिक बोझ को कम करने के रूप में सटीकता से सामने आते हैं। साथियों संशोधन के विनियामक प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं को समझना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह देश की पूरी दवा वितरण प्रणाली को एक पारदर्शी और जवाबदेह ढांचे में ढालता है। औषधि नियम, 1945 के तहत शेड्यूल एच1 को विशेष रूप से उन दवाओं की सख्त निगरानी के लिए पेश किया गया था, जिनके दुरुपयोग या एंटीबायोटिक प्रतिरोध पैदा करने की संभावना सबसे अधिक होती है। उच्च अल्कोहल वाली ओरल दवाओं को इस श्रेणी में शामिल करने के बाद अब देश के प्रत्येक फार्मासिस्ट या केमिस्ट को एक अलग, विशेष रजिस्टर बनाए रखना होगा। इस रजिस्टर में दवा खरीदने वाले मरीज का नाम, उसका पूरा पता, संपर्क सूत्र, प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले डॉक्टर का नाम, उनकी डिग्री तथा बेची गई दवा की सटीक तारीख व मात्रा दर्ज करनी होगी। इस पूरे भौतिक और डिजिटल रिकॉर्ड को न्यूनतम तीन वर्षों तक ड्रग इंस्पेक्टर्स की औचक जांच के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य है। साथियों, यह व्यापक डेटा ट्रेल आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी प्रकार के लीकेज,ब्लैक मार्केटिंग या थोक डायवर्जन को पूरी तरह से असंभव बना देता है। यदि कोई मेडिकल स्टोर अवैध रूप से इन दवाओं की बड़ी खेप किसी नशे के सिंडिकेट या अवैध वितरकों को बेचता है, तो रिकॉर्ड में विसंगति आते ही वह कानून के शिकंजे में आ जाएगा। इस प्रकार, विनियामक ढांचे में किया गया यह बदलाव केवल कागजी न होकर जमीन पर एक ठोस प्रशासनिक पकड़ सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही, इस कानून का उल्लंघन करने वाले फार्मेसियों के खिलाफ भारी जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और आपराधिक मुकदमे तक का प्रावधान किया गया है, जो वितरकों के मन में एक विनियामक भय पैदा करेगा।दवाओं के जरिए होने वाले नशे का सबसे दर्दनाक पहलू इसका सामाजिक ताने- बाने और पारिवारिक स्थिरता पर पड़ने वाला विनाशकारी प्रभाव है। पारंपरिक मादक पदार्थों जैसे शराब, गांजा या अफीम के सेवन पर समाज में एक गहरी सामाजिक बंदिश और शर्मिंदगी होती है, जिसके कारण कई लोग इसकी शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। इसके विपरीत, चूंकि कफ सिरप या हेल्थ टॉनिक आकर्षक पैकिंग में दवा की बोतलों में आते हैं, इसलिए कई बार परिवारों को बहुत देर से पता चलता है कि उनका बच्चा किसी गंभीर नशे की गिरफ्त में आ चुका है। यह साइलेंट एडिक्शन मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह तबाह कर देता है, जिससे घरेलू हिंसा और अपराधों में भी वृद्धि होती है।

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

इंदौर बाजार भाव

इंदौर। एजेंसी। ताजा पूछपरख से सोमवार को अनाज मंडी में चने में बाजार उछाल पर रहे। मूंग व उड़द में मजबूती रही। खाद्य तेलों में व्यापार ठंडा-ठंडा ही रहा। तिलहनों में सोयाबीन सुर्ख रहा। किराना जिंसों में शक्कर व खोपरा गोला मजबूती बनाये रहे। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार चने में ताजा लेवाली के बीच भावों में जोरदार तेजी रही। चना बढ़िया मालों में 6200-6300 रू. प्रति क्विंटल पर आ गया। उड़द व मूंग में बाजार मजबूत रहे। खाद्य तेलों में व्यापार ठंडा-ठंडा ही रहा। तिलहनों में सोयाबीन बाजार 7000 रू. प्रति क्विटल पर बने रहे। उधर, किराना जिंसों में शक्कर व खोपरा गोला सुर्ख बने रहे। भाव इस प्रकार रहे-

किराना- शक्कर 4450-4520, खोपरा गोला 370-420, खोपरा बूरा 3200-6800 (15 कि.ग्रा.), जीरा राजस्थान 280-285, ऊंझा हल्का 290-295, बेस्ट 315-325, हल्दी निजामाबाद 210-230, सांगली 275-280, साबूदाना हल्का 5200-5350, मीडियम 5450-5600, बेस्ट 6000-6100, सच्चा मोती 5700, मोरधन 7200-8200, सौंफ मोटी 275-350, बेस्ट 350-400, सौंफ बारिक 180-300, एक्स्ट्रा बोल्ड 350-400, राई दाल 90-95, सरसो दाल 85-95, कालीमिर्च एटम 750-755, मीनी मटरदाना 770-800, मटरदाना 825-850, खसखस अनक्लीन 1150-1250, क्लीन 1300-1350, दालचीनी 250-260, जायफल 725-750, वाद्यान फूल 405-600, शाहजीरा 350-400, तेजपान 90-100, पत्थर फूल 235-425, जावत्री 1675-1750, केसर 200-250, नाग केसर 925-975, सौंठ 325-500, धोली मूसली 1400-1600, लौंग 700-720, बेस्ट 760-790, हींग (वनदेवी 751) 3450, पाउच 10 ग्राम 3550, सिंघाडा छोटा 100-120, बड़ा 120-130, सिंदूर (25 कि.ग्रा. पैकिंग) 7300, देशी कपूर 850-860, बेस्ट 875-900, पूजा बादाम 115-125, बेस्ट 220-230, पूजा सुपारी 425-450, अरीठा 180-200, हरी इलायची एवरेज 2700-2800, मीडि?यम 2900-3050, बेस्ट 3150-3250, एक्ट्रा बेस्ट 3300-3500, पानबार 2450, बड़ी इलायची 1800-2100, तरबूज मगज 525-550, काजू (240) 880-925, काजू (210) 950-1000, काजू डब्ल्यू (340) 840-870, काजू एस.डब्ल्यू (300) 800-825, काजू जे.एच. 840-870, टुकड़ी 780-820, बादाम मगज 840-870, सिंगापुरी 850-860, बादाम टांच 700-725, अखरोट 590-850, अखरोट गिरी 1250-1550, जर्दालु 375-500, बेस्ट 550-650, किशमिश कंधारी 450-600, इंडियन 400-450, चारौली 1450-1750, मुनक्का 350-550, अंजीर 850-950, मखाना 850-1200, बेस्ट 1350-1400, खारक एवरेज 75-80, मीडि?यम 90-130, बेस्ट 140-260, पिस्ता पिशोरी 2900-3100, कंधारी 2500-2700, नमकीन पिस्ता 1000-1150, बेस्ट 1200-1250, गेहूँ आटा 1820, मैदा कट्टा 1850, रवा कट्टा 1880, बेसन 4675 (50 कि.ग्रा.), नारियल (120) 2500, (160) 2900, (200) 3100, (250) 3600,

तेल- सींगदाना 1610-1630, मुम्बई 1630-1635, राजकोट तेलिया 2550, सोया साल्वेंट 1395-1400, सोया रिफाइंड 1455-1460, कपास्या 1535, धूलिया 1540, कड़ी 1540,

रात की धारणा- गुजरात लुज 1645, मुम्बई पाम 1470, मुम्बई सोया 1470,

खली- कपस्या खली (60 कि.ग्रा.) इन्दौर 2600, देवास-उज्जैन 2600, खंडवा-बुरहानपुर 2575, अकोला 3925 (प्रति क्विंटल)

तिलहन- सरसो 7600-7800, रायडा 6800, सोयाबीन 7000, टोली (महुआ बीज) 5000-5100, करंज 4400-4500, अलसी 8500-9000, अरंडी 4500-4700, तिल्ली पुरानी 6500-7000, तिल्ली नई 7200-7500,

दलहन- चना कांटेवाला बेस्ट 6200-6300, एवरेज 5900-6000, विशाल 6000-6100, महाराष्ट्र विशाल 5900-5950, काबूली चना डॉलर 7000-8300, काबूली चना रशियन 5600-5800, बिटकी 5200-5300, मसूर बेस्ट 5900-5950, एवरेज 5700-5800, मूंग गर्मी बेस्ट नया 7100-7250, मूंग पुराना बोल्ड 7500-7700, मीडियम 7400-7700, मोगर 5500-6500, तुअर निमाड़ी बेस्ट 7200-7400, एवरेज 6500-6600, हल्की 6400-6500, महाराष्ट्र सफेद 7400-7500, महाराष्ट्र लाल 7700-7900, उड़द बेस्ट 9300-9600, उड़द गर्मी 8600-9300, ग्रेविटी क्लीन 9600-9800, हल्की 4000-6000,

दाल- चना दाल एवरेज 7400-7500, मीडियम 7600-7700, बोल्ड 7900-8100, तुअर दाल सवा नं. 8200-8400, तुअर दाल 7300-7600, तुअर दाल मीडियम 8500-8800, बेस्ट 9900-10200, मसूर दाल 6800-7100, मूंग दाल 8700-8900, मूंग मोगर 10100-10600, उड़द दाल 9900-10300, मोगर 10800-11000,

अनाज- गेहूं मिल क्वालिटी 2500-2550, लोकवन एवरेज 2550-2650, बेस्ट 2750-2800, मालवराज 2600-2650, गेहूँ पूर्णा एवरेज 2400-2550, बेस्ट 2650-2750, मक्का पीली 1975-2000,

चावल- चावल हंसा सफेद 2900-3100, सेला 3500-3700, परमल 3400-3500, दुबराज 4500-5500, राजभोग 7500, काली मुंछ डिनर किंग 9000, बासमती दुबार 9500-10000, मीनी दुबार 8000-8500, मोगरा 5000-7000, तिबार 10500-11500, बासमती (921) 12000-13000, बासमती सेला 7500-9500, पोहा 4500-5100,

मावा- इन्दौर 340, उज्जैन 280, रतलाम 275 रू. प्रति किलो।

इंदौर सर्राफा बाज़ार

इन्दौर। एजेंसी। सोमवार को स्थानीय सराफा बाजार में व्यापार सामान्य ही रहा। दोनों ही मूल्यवान धातुओं में बाजार सुस्ती पर रहे। भाव इस प्रकार रहे-

चॉंदी (9999) 222500, चॉंदी (99) 222400, टंच 221900, सिक्का 2600, सोना 10 ग्राम 141500,

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई। एजेंसी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार को रुपये में गिरवट रही और ये 26 पैसे टूटकर 95.64 पर बंद हुआ। सोमवार सुबह कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 39 पैसे टूटकर 95.77 प्रति डॉलर पर आ गया। वहीं विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 79 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ा। उन्होंने कहा कि घरेलू मुद्रा के कमजोर शुरुआत के साथ 95.53 प्रति डॉलर के स्तर पर खुलने की उम्मीद थी। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.72 प्रति डॉलर पर खुला और बाद में 95.77 प्रति डॉलर के स्तर तक गिर गया।

शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद

सेंसेक्स 47अंक , निफ्टी 4 अंक उछला

मुंबई। एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार सोमवार को हल्की बढ़त पर बंद हुआ। आज दुनिया भर के बाजारों से मिले नकारात्मक वैश्विक संकेतों के साथ ही उतार-चढ़ाव जारी रहने से बाजार में उत्साह नहीं था। । सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन आईटी शेयरों में तेजी से बाजार अंत में बढ़त पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 47.01 अंक उछलकर 77,616.40 पर जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 4.10 अंक बढ़कर 24,211 पर बंद हुआ। वहीं व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप भी हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। आज सेक्टरवार देखें तो निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा गिरावट रही जबकि निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा तेजी आई । इसके बाद निफ्टी मीडिया और निफ्टी

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी बढ़त रही। निफ्टी ऑटो में और निफ्टी प्राइवेट बैंक व निफ्टी पीएसयू बैंक में भी तेजी रही।वहीं इसके विपरीत, निफ्टी एफएमसीजी में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा निफ्टी मेटल , निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी रियल्टी में गिरावट आई। निफ्टी फार्मा और निफ्टी एनर्जी भी नीचे आये। निफ्टी में टीसीएस और एचसीएलटेक में बढ़त दर्ज की गई और ये दिन के सबसे अधिक लाभ वाले शेयर रहे। टेक महिंद्रा, इंफोसिस, बजाज ऑटो और एनटीपीसी के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। जबकि, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, नेस्ले इंडिया के शेयर रहे ।जानकारों के अनुसार अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले बढ़ाने के बाद से ही ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 3 तेजी आई है जिससे बाजार पर दबाव आया है। । वहीं इससे पहले आज सुबह शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों में तेज गिरावट दर्ज की गई। सुबह शुरुआत के बाद निफ्टी 50 178 अंक की गिरावट के साथ 24,029.75 पर कारोबार कर रहा था।

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली। एजेंसी। श्रम मंत्रालय ने सांविधिक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (फ्लोर वेज) तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारों के मुताबिक वेतन संहिता के अंतर्गत न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। अधिकारियों का समूह गणना के तरीके और खपत बास्केट पर काम कर रहा है और केंद्र सरकार 'केंद्रीय सलाहकार बोर्ड' (सीएबी) बनाएगी। सीएबी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की सिफारिश करने से पहले बातचीत करेगा। यह एक बार अधिसूचित होने के बाद न्यूनतम सीमा के लिए कानूनी बाध्यता होगी और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इस निर्धारित सीमा से कम वेतन तय नहीं कर पाएंगे। लोगों ने बताया कि यह तकनीकी प्रक्रिया एस. पी. विशेषज्ञ समूह के तैयार अनुमानों पर आधारित होगी। इस क्रम में खपत बास्केट को नए सिरे से बनाने के बजाए महंगाई के हिसाब से संशोधित किए जाने की संभावना है। अधिकारियों का समूह तरीके की जांच कर रहा है और खपत बास्केट को अपडेट कर रहा है, जबकि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड केंद्र को अपनी सिफारिश देने से पहले प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेगा। मामले की जानकारी रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके साथ ही राज्यों के साथ भी बातचीत चल रही है। इसका कारण यह है कि न्यूनतम वेतन राशि तय करने में बड़ी चुनौती राज्यों के बीच न्यूनतम वेतन में अंतर है।' खबर लिखे जाने तक श्रम मंत्रालय को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला था।

सेवानिवृत्ति की तैयारी-ईपीएफ, पीपीएफ या एनपीएस कौन है बेहतर विकल्प?

बढ़ती महंगाई और लंबी जीवन प्रत्याशा के बीच वित्तीय सुरक्षा के लिए तीनों योजनाओं को समझना जरूरी

नई दिल्ली। एजेंसी। बढ़ती महंगाई और लंबी जीवन प्रत्याशा को देखते हुए, सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। केवल बचत पर्याप्त नहीं, बल्कि नियमित आय देने वाली निवेश योजनाएं आवश्यक हैं। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) तीन प्रमुख विकल्प हैं, जिनके नियम, जोखिम, रिटर्न और कर लाभ भिन्न हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ एक मजबूत आधार है, जहां नियोक्ता-कर्मचारी योगदान से बड़ा फंड बनता है। सरकारी ब्याज दर के साथ यह नौकरीपेशा लोगों के लिए सुरक्षित बचत है। वहीं पीपीएफ किसी भी भारतीय नागरिक के लिए सुरक्षित और सरकारी गारंटी वाली योजना है। 7.1 फीसदी ब्याज दे रही यह योजना, निवेश, ब्याज और परिपक्वता राशि पर कर छूट (ईईई) के कारण दीर्घकालिक निवेश का लोकप्रिय विकल्प है। एनपीएस अधिक रिटर्न चाहने वाले और सीमित बाजार जोखिम उठाने को तैयार निवेशकों के लिए बेहतर है। यह शेयर, बॉन्ड आदि में निवेश करती है, बाजार-आधारित प्रतिफल के साथ अतिरिक्त कर लाभ देती है। वित्तीय विशेषज्ञ तीनों योजनाओं के संतुलित संयोजन की सलाह देते हैं ताकि सुरक्षा, कर बचत और बेहतर रिटर्न का लाभ मिल सके। नियमित निवेश और योजना की समीक्षा भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

मेष- आज किस्मत आपके कदमों के साथ चलती नजर आएगी। भाग्य का साथ मिलने से कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपका मिलनसार स्वभाव नए लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा और दोस्ती का दायरा बढ़ेगा। हालांकि बातचीत में कटु शब्दों से बचना जरूरी होगा।

वृषभ- आज का दिन व्यस्तता से भरा रह सकता है। काम का दबाव बढ़ने से भागदौड़ भी अधिक रहेगी। पेट से जुड़ी किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें और खर्चों पर भी नियंत्रण बनाए रखें। एक साथ कई जिम्मेदारियां आने से मन थोड़ा तनाव महसूस कर सकता है। पड़ोसियों और आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, क्योंकि मुश्किल समय में वही सबसे पहले साथ खड़े हो सकते हैं।

मिथुन- आज सफलता का रास्ता अच्छी योजना और धैर्य से होकर गुजरेगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला परेशानी बढ़ा सकता है। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। पुरानी गलती से मिली सीख भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। मेहनत से पीछे न हटें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यदि प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो बजट का पूरा ध्यान रखें।

कर्क- आज खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। परिवार में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, इसलिए जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सोच-समझकर ही अपनी राय दें। किसी रिश्तेदार के आने से घर का माहौल बदल सकता है।

सिंह- आज का दिन सुखद और संतोष देने वाला रहेगा। लंबे समय से अटका हुआ कोई आर्थिक मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है। आय के नए स्रोत बनने से भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ेगा। यदि किसी को उधार दिया हुआ पैसा अटका था, तो उसके वापस मिलने की संभावना है। जीवनसाथी की सलाह व्यापार में लाभ दिला सकती है। किसी जरूरी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है।

कन्या- आज आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। बोलने से पहले सोचें और किसी सामाजिक कार्यक्रम में पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनें। विरोधी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी उन पर भारी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और खर्चों को लेकर ज्यादा चिंता नहीं होगी।

तुला- आज धन और खुशहाली में बढ़ोतरी के अच्छे संकेत हैं। प्रेम जीवन में साथी के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा। हालांकि पुराने स्वास्थ्य संबंधी समस्या दोबारा परेशान कर सकती है, इसलिए खान-पान में लापरवाही न करें। भाई-बहनों का सहयोग हर कदम पर मिलेगा। व्यापार की किसी बड़ी डील को अंतिम रूप देने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें, इससे रिश्ते और मजबूत होंगे।

वृश्चिक- आज खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। दिखावे में किया गया खर्च बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों से बचें, जो जीवनसाथी को ठेस पहुंचा सकते हैं। संतान के भविष्य को लेकर आप थोड़ा सख्त रवैया अपना सकते हैं, लेकिन आपकी मंशा उनके भले की ही होगी। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद बढ़ने की आशंका है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें।

धनु- आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। यात्रा की योजना बन सकती है और माता-पिता की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। धन का सही उपयोग करना आज बेहद जरूरी रहेगा। पारिवारिक मामलों में गुस्से पर काबू रखें, वरना रिश्तों में दूरी आ सकती है। माता-पिता के आशीर्वाद से कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ने की भी संभावना है।

मकर- आज चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहेगा। दूसरों की मदद करने का अवसर मिलेगा और इससे आपको भी आत्मसंतोष मिलेगा। हालांकि जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत पर लगाम लगाना जरूरी होगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। यदि यात्रा पर निकलें, तो वाहन सावधानी से चलाएं।

कुंभ- आज थोड़ा सतर्क रहकर आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ लोग आपके कामों में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए किसी अजनबी पर भरोसा न करें। कानूनी मामलों में भागदौड़ बढ़ सकती है। व्यापार में साझेदारी से जुड़ी किसी बड़ी डील करने से पहले हर पहलू पर गंभीरता से विचार करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।

मीन- आज का दिन सामान्य लेकिन कई छोटे-छोटे सुखद अनुभवों से भरा रहेगा। घर के लिए कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का योग बन सकता है। पिताजी की सलाह आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगी, इसलिए उसे नजरअंदाज न करें। संतान किसी खास चीज की इच्छा जता सकती है। लंबे समय बाद किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपका दिन यादगार बना देगी।

शब्दजाल - 8319

उ	जा	ला	ह	दा	प	उ	ड़ी	सा	झ	आ
ज	अ	ल	म	आ	मो	ल	ब्ब	तें	शा	अ
अं	इ	नु	दि	ल	दा	ज	ढा	र	ला	व
ज	कु	उ	ल	बे	ला	लू	उ	त	रा	ना
स	ति	श	द	व	दा	ल	उ	ग	वी	ट
री	रं	ल	चु	बि	लि	र्त	क्ष	दा	प	च
जो	उ	ल	के	गा	ला	म	उ	कौ	र	ले
श	ता	जीं	स	त	क	व	क	ग	श	ता
म	व	मि	न	व	न	ज	सा	शा	जू	द
द	ला	ल	म	ह	उ	ठ	ना	स	प	ना
थो	औ	र	प्या	र	उ	ल	झ	न	क	

शब्दजाल में 'उ' से शुरु होने वाले दस शब्द ढूंढिए. दिये गए शब्द उपर से नीचे व तिरछे हो सकते हैं.

उकसाना, उतावला, उलझन, उठना, उजाला, उड़ीसा, उलजलूल, उतराना, उदबिलाव, उदारता

शब्दजाल - 8318 का हल

फिल्म वर्ग पहेली- 7263

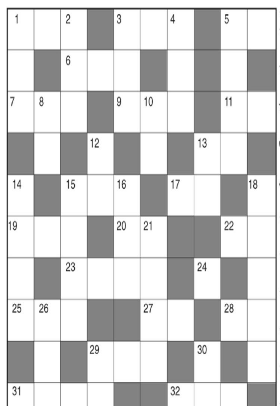

ऊपर से नीचे:-

१. राहुल राय, शीबा की फिल्म-३
२. आमिर खान, ग्रेसी सिंह की 'मधुबन में जो कन्हैया' गीत वाली फिल्म-३
३. 'जिन्हें हम भूलना चाहें वो' गीत वाली दीपक कुमार, रेहाना की फिल्म-३
४. शशिकपूर, राखी की 'आज मदहोश हुआ जाये रे' गीत वाली फिल्म-३
५. 'नाले नाले मैं चली' गीत वाली मिथुन, कबीर बेदी, संगीता की फिल्म-४
८. बॉबी, काजोल, मनीषा कोइराला की 'मेरे ख्वाबों में तू' गीत वाली फिल्म-२
१०. 'अब चाहे सर फूटे या' गीत वाली राजेश खन्ना, राखी, शर्मिला टैगोर की फिल्म-२
१२. कुमार गौरव, माधुरी की 'पहली बारिश मैं और तू' गीत वाली फिल्म-२
१३. 'सजना साथ निभाना' गीत वाली राजेश खन्ना, बबीता की फिल्म-२
१४. सुनीलदत्त, माला की 'आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार' गीत वाली फिल्म-४
१५. 'जान तन से' गीत वाली जैकी श्रॉफ, फरहा की फिल्म-४
१६. प्रशांत, संध्या की 'तुम तो प्यार हो सजना' गीत वाली फिल्म-३
१८. 'खुशी से खुदकुशी' गीत वाली फिल्म-५
२१. सनी, जीतेंन्द्र, फरहा, जयाप्रदा की फिल्म-४
२६. 'आँखों आँखों में हो गए' गीत वाली फिल्म-३
२९. नसीर, अतुल, पूजा भट्ट की फिल्म-२
३०. 'रंग [illegible]' गीत वाली फिल्म-२

बायें से दायें:-

१. अमिताभ, सलमान, जॉन, हेमा, रानी की फिल्म-३
३. 'हैलो हैलो बोल के' गीत वाली सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी की फिल्म-३
५. जैकी, अनिल, शत्रुघ्न, हेमा, टीना मुनीम की फिल्म-२
६. 'मैं लव तुम से' गीत वाली फिल्म-३
७. कंवलजीत, वहीदा की फिल्म-३
९. 'झूठी मूठी मितवा सांवन' गीत वाली फिल्म-३
११. नवीन निश्चल, प्राण, रेखा की 'ना सतरा से ऊपर' गीत वाली फिल्म-२
१३. 'हर इक लब पर है' गीत वाली श्रेयस तलुदे, आयशा टकिया की फिल्म-२
१५. शाहरूख, मनीषा, प्रीति, शिल्पा की फिल्म-२,१
१७. अमिताभ, जया भादुड़ी की फिल्म-२
१९. 'मुझे तुम याद' गीत वाली फिल्म-३
२०. अमिताभ, गोविंदा, रजनीकांत, किमी की फिल्म-२
२२. 'दिल में जिगर' गीतवाली फिल्म-२
२३. हिंदी फिल्मोंका पहला 'ही-मैन' किसे कहा गया है-४
२४. जीतेंन्द्र, जयप्रदा की एक पारिवारीक फिल्म-१
२५. 'सौ सवालों का' गीत वाली धर्मेन्द्र, अनिलकपूर, मीनाक्षी की फिल्म-३
२७. अमिताभ, जैकी, जावेद, कैटरीना, मधु, सीमा, जीनत की फिल्म-२
२८. 'जुड़वाँ' में सलमान के साथ करिशमा के अलावा दूसरी नायिका कौन थी-२
२९. राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर की फिल्म-३
३१. फिरोज, संजय, मनीषा की 'आखिर तुम्हें आना है' गीत वाली फिल्म-४
३२. 'मेरा दिल जिस दिल' गीत वाली अनिल, अक्षय, करीना की फिल्म-३

फिल्म वर्ग पहेली- 7262

दैनिक पंचांग

14 जुलाई को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति	लग्नारंभ समय	
सूर्य	मिथुन में	कर्क	05.39 बजे से
चंद्र	मिथुन में	सिंह	07.55 बजे से
मंगल	वृष में	कन्या	10.07 बजे से
बुध	मिथुन में	तुला	12.17 बजे से
गुरु	कर्क में	वृश्चिक	14.32 ब.से
शुक्र	सिंह में	धनु	16.48 बजे से
शनि	मीन में	मकर	18.53 बजे से
राहु	कुंभ में	कुंभ	20.40 बजे से
केतु	सिंह में	मीन	22.12 बजे से
राहुकाल		मेष	23.43 बजे से
3.00 से 4.30		वृष	01.23 बजे से
बजे तक		मिथुन	03.21 बजे से

मंगलवार 2026 वर्ष का 195 वा दिन **दिशाशूल** उत्तर **ऋतु** वर्षा। **विक्रम संवत्** 2083 **शक संवत्** 1948 **मास** आषाढ़ (दक्षिण भारत में ज्येष्ठ) **पक्ष** कृष्ण **तिथि** अमावस्या 15.14 बजे को समाप्त। **नक्षत्र** पुनर्वसु 00.10 बजे रात्र को समाप्त। **योग** व्याघात 11.57 बजे को समाप्त। **करण** नाग 15.14 बजे तदनन्तर किंस्तुघ्न 01.30 बजे रात्र को समाप्त। **चन्द्रायु** 24.9 घण्टे **रवि क्रान्ति** उत्तर 21° 42' **सूर्य** उत्तरायन **कलि अहर्गण** 1872770 **जूलियन दिन** 2461235.5 **कलियुग संवत्** 5128 **कल्पारंभ संवत्** 1972949128 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885128 **वीरनिर्वाण संवत्** 2552 **हिजरी सन्** 1448 **महीना** मोहर्रम **तारीख** 28 **विशेष** स्नानदान श्राद्ध अमावस्या।

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
रोग	05.53 से	07.22 बजे तक	काल	05.42 से	07.13 बजे तक
उद्वेग	07.22 से	08.15 बजे तक	लाभ	07.13 से	08.45 बजे तक
चर	08.15 से	10.19 बजे तक	उद्वेग	08.45 से	10.16 बजे तक
लाभ	10.19 से	11.48 बजे तक	शुभ	10.16 से	11.48 बजे तक
अमृत	11.48 से	01.16 बजे तक	अमृत	11.48 से	01.19 बजे तक
काल	01.16 से	02.45 बजे तक	चर	01.19 से	02.51 बजे तक
शुभ	02.45 से	04.13 बजे तक	रोग	02.51 से	04.22 बजे तक
रोग	04.13 से	05.42 बजे तक	काल	04.22 से	05.54 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

प्रसंगतः प्रार्थना का अर्थ

यहूदी गुरु रब्बी बार्डिक्टेव हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करते और उन्हें सुख-शांति के उपाय बताया करते थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया और हाथ जोड़कर बोला, 'महाराज, मैं एक गरीब गाड़ीवान हूं। गाड़ी चलाकर अपना व परिवार का भरण-पोषण करता हूं। मेरा सारा दिन काम करने में ही बीत जाता है और प्रभु का स्मरण करने का जरा भी वक्त नहीं मिलता। कुछ दिनों से यही सोच-सोचकर मैं परेशान हूं। ऐसे में मेरा कल्याण कैसे हो पाएगा? कृपया आप मुझे कोई रास्ता बताएं।' उस गरीब गाड़ीवान की बात सुनकर बार्डिक्टेव बोले, 'क्या तुम अपनी गाड़ी से ऐसे लोगों को भी गंतव्य तक पहुंचाते हो जो अक्षम व विकलांग हैं और जो तुम्हारा किराया देने में असमर्थ हैं?' गाड़ीवान ने कहा, 'हां, मैं विकलांगों व गरीब लोगों से किराया नहीं लेता और उन्हें सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाता हूं। इसके अतिरिक्त मैं अपनी कमाई के कुछ हिस्से से बेजुबान पशु-पक्षियों को भी खिलाता हूं।' गाड़ीवान की बातें ध्यान से सुनकर गुरु बार्डिक्टेव बोले, 'भइया, तुम्हारे मन में विकलांगों, असहायों, गरीबों व बेजुबान पशु-पक्षियों के लिए दया भावना है और यह भावना किसी प्रार्थना से कम नहीं है। प्रार्थना का उद्देश्य भी अपने जीवन को सार्थक करना है और यह सार्थकता दूसरे रास्तों से भी पाई जा सकती है। ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दुराचारी हैं, वे चाहे दिन भर प्रभु का स्मरण करते रहें किंतु प्रभु ऐसे दुराचारी लोगों की प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करते। वे ऐसे लोगों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं जो मन, वचन व कर्म से नेक होते हैं और मानवीय गुणों की रक्षा करते हैं। तुम भी प्रभु के ऐसे ही बंदों में से एक हो। इसलिए तुम चिंतामुक्त होकर ऐसे ही अपने कार्य में लगे रहो जैसे अभी लगे हुए हो। तुम्हारा कल्याण स्वतः हो जाएगा।' गुरु बार्डिक्टेव की बातें सुनकर गाड़ीवान संतुष्ट हुआ और अपने काम पर निकल गया ।

सूडोकु नवताल- 7572

★☆☆☆☆ सरल

2		8	5	1	9	6		7
					8			1
		7	4	6		8		9
3	2				7			8
1		9		4		7		5
4			2				9	3
6		3		5	1	9		
8			3					
7		1	9	2	6	3		4

सूडोकु नवताल -7571 का हल

7	1	9	8	5	3	2	6	4
4	5	3	6	2	9	7	1	8
6	2	8	4	7	1	9	5	3
9	8	2	7	3	5	1	4	6
1	3	6	9	4	8	5	7	2
5	7	4	1	6	2	8	3	9
8	4	7	5	9	6	3	2	1
3	6	1	2	8	7	4	9	5
2	9	5	3	1	4	6	8	7

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

शब्द पहेली - 8787

बाएँ से दाएँ

1. जी,इच्छा,चित्त-2
2. तन,बदन,देह-3
4. अग्निदग्ध-2
6. रनिवास (उर्दू-3)
7. स्नान करना-3
8. विश्राम-3
9. राजा,सम्राट-3
10. वचन,प्रतिज्ञा-3
11. तरंग,हिलोर-3
13. दौड़ना (अंग्रेजी-2)
14. सही का विलोम-3
15. सदुपुरुष-2
16. पाठ,शिक्षा-3
17. कर्ता,कार्य करने वाला-3
18. इज्जत,मान,सम्मान-3
19. सब कुछ छीन लेना-2
20. भवन,प्रासाद-3
21. वजह-3
23. खेल दिखाने वाला-2
24. पेन,लेखनी-3
25. ठाठ-बाट-2

ऊपर से नीचे

1. राय,वोट,अभिप्राय-2
2. लाज.लज्जा-2
3. 500 कागजों की गड्डी -2
4. दुनिया,जगत-3
5. लेकर आना-2
6. अवैध,नाजायज-3
7. निगाह,दृष्टि-3
8. बैठने की जगह-3
9. आराम,मदद-3
10. कर्म,भाग्य-3
11. लगन,जिद,उत्साह-3
12. दांपत्य संबंध विच्छेद-3
14. जवान,तरुण-3
15. रिक्त जगह पूर्ण करना-3
16. दुर्बल का विलोम-3
17. वजह-3
18. पदचाप, किसी के आने की आवाज-3
19. रनिवास (उर्दू-3)
20. जी,इच्छा,चित्त-2
21. समयगति-2
22. देह,बदन-2

शब्द पहेली -8786 का हल

सा	ध		प	ना	ह		शा	न
त	र	ह		क	ब	च		शा
	ती	र	थ		स	प	ना	
घ		म	का	न		ल	च	क
रा	ख		न	ज	र		ना	म
ना	र	द		ला	क	र		र
	ल	ह	र		म	वा	ली	
रा		न	क	ल		ना	प	ना
ज	रा		म	त	ली		ना	ना

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

मनरेगा कर्मचारियों को 8 महीने से नहीं मिला वेतन, परिवार आर्थिक संकट में

कर्मचारी वेतन नहीं मिलने तक सामूहिक अवकाश पर

पद्मेश न्यूज। लांजी। जनपद पंचायत लांजी में मनरेगा योजना के तहत कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। विगत 8 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ हो गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने और आर्थिक संकट की मार झेल रहे कर्मचारियों ने आखिरकार 13 जुलाई 2026 से सामूहिक अवकाश पर चले गए।

एकमात्र ब्लॉक जहां 3 महीने का वेतन भी नहीं पहुंचा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में स्न्न पोर्टल के माध्यम से वेतन वितरण होता है। मनरेगा परिषद ने हाल ही में मात्र 3 महीने का आवंटन जारी किया, जिससे प्रदेश भर के ज्यादातर मनरेगा कर्मचारियों को वेतन मिल गया। लेकिन जनपद पंचायत लांजी पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा ब्लॉक बन गया है, जहां इस 3 महीने के वेतन का भी भुगतान नहीं हो सका। कर्मचारियों का आरोप है कि विगत 15 दिनों से स्न्न पोर्टल के माध्यम से सेंट्रल ट्रेजरी को वेतन बिल ट्रांसफर कर दिए गए थे, फिर भी आज तक किसी भी कर्मचारी के बैंक खाते में राशि जमा नहीं हुई है।

बार-बार शिकायत, कोई समाधान नहीं

कर्मचारियों और अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों के पास कई बार लिखित निवेदन दिए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उपयंत्री, अधिकारी, कर्मचारी और ग्राम रोजगार सहायक सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं। एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 8 महीने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, बीमारी — सब ठप्प हो गया है। मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है। हम लोग सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही।

विधायक को भी दी सूचना

इस गंभीर समस्या से अवगत कराते हुए स्थानीय विधायक राजकुमार कर्राहे को भी पत्र भेजा गया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक वेतन भुगतान नहीं होता, वे सामूहिक अवकाश पर ही रहेंगे।

प्रशासनिक लापरवाही या सिस्टम की खामी?

यह मामला सिर्फ लांजी ब्लॉक तक सीमित नहीं लग रहा। मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना में कर्मचारियों की इस हालत से ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर स्न्न पोर्टल पर बिल ट्रांसफर होने के बावजूद पैसे खाते में क्यों नहीं पहुंच रहे? क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है या बड़े स्तर पर कोई तकनीकी/वित्तीय गड़बड़ी?

जनपद पंचायत लांजी के मनरेगा कर्मचारियों की यह लड़ाई अब पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण बनती जा रही है। प्रशासन और सरकार से अपील है कि इस समस्या का तुरंत समाधान निकाला जाए, ताकि कर्मचारी अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जी सकें और योजना का काम भी सुचारू रूप से चल सके।

लांजी का साप्ताहिक मछली बाजार बना स्वास्थ्य के लिए ख़तरा!

मछलियों के अपशिष्ट और बदबू से परेशान रहवासी

पद्मेश न्यूज। लांजी। रविवार को लगने वाला लांजी का साप्ताहिक बाजार आसपास निवासरत लोगों के लिए अब सिरदर्द बन गया है। मछली व मुर्गी बाजार के अंतिम छोर पर बसे रहवासी लोग बदबू की चपेट में हैं। मछली विक्रेता मछली को साफ करके काटने के बाद अपशिष्ट पदार्थ वहीं छोड़ देते हैं। साथ ही, जिंदा मछली रखने के लिए पिकअप वाहनों में लाया गया गंदा पानी भी वहीं बाजार में बहा दिया जाता है। जिसके चलते बाजार समाप्त होने के बाद सफाई न होने से पूरा इलाका बदबू से भर जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाजार उठने के तुरंत बाद सफाई हो जानी चाहिए, लेकिन यहां दो-तीन दिन बाद या फिर शिकायत करने के बाद ही सफाई कर्मचारी नजर आते हैं। इससे अगले दिन गंध और भी तेज हो जाती है। एक स्थानीय निवासी ने गुस्से के साथ कहा कि हर रविवार के बाद पूरा इलाका गंदगी से बजबजा जाता है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं। कभी भी कोई गंभीर बीमारी फैल सकती है। हमने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। मछली बाजार के अपशिष्ट पदार्थ, मरी मछलियां और बहाए गए पानी से न सिर्फ बदबू फैल रही है, बल्कि मक्खियां, मच्छर और अन्य कीटाणु भी बढ़ रहे हैं। आसपास के लोग दावा कर रहे हैं कि यह लापरवाही उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।

नगर परिषद उठाए सख्त कदम

लोगों की मांग है कि नगर परिषद लांजी तुरंत कदम उठाए, मछली विक्रेताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट को बाजार समाप्त होते ही तुरंत हटाया जाए और किसी सुरक्षित जगह पर डिस्पोज किया जाए। बाजार के बाद नियमित एवं तत्काल सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी

ऐसे इलाकों में जलजनित और वायरल बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार, बाजार में पड़े मछली के अपशिष्ट और गंदे पानी से हैजा,

डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। स्वास्थ्य विभाग भी इसे संज्ञान में लेते हुए लोगों को जागरूक करें।

छोटू पटेल की सोलहवीं पुण्यतिथि पर सिविल अस्पताल में मरीजों को फल व नवजात शिशुओं को वस्त्र किया वितरित

पद्मेश न्यूज। लांजी। लांजी नगर के भिलाई रोड पर स्थित पटेल परिवार के होनहार एवं मिलनसार व्यक्तित्व के धनी आशीष छोटू पटेल

16 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना पर असामयिक स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गीय छोटू पटेल का व्यवहार आज भी लोगों के स्मृति पटल पर है इनकी 16 वीं पुण्यतिथि पर 13 जुलाई 2026 को परिजनों द्वारा शांति पाठ करा कर सिविल अस्पताल लांजी पंहुचकर अस्पताल में

भर्ती मरीजो को फल वितरण किया गया साथ ही नवजात शिशुओ को वस्त्र वितरण किया गया। बतादे कि प्रतिवर्ष छोटू महिमेहरो का परिवार जिसमें पिताजी युवराज महिमेहरो, माता श्रीमती विद्या महिमेहरो, बडे भाई राजा पटेल महिमेहरो, बहन श्रीमती अंजू कर्राहे, ओम चिया समस्त पटेल परिवार, सहित मित्र मण्डल सौरभ मोनू पशीने, अमित आसटकर, शालू अली, जीवन किरनापुरे, सुभाष सहारे, उपकेन वराड़े, शरद सोनवाने, इकराम शेख, आदित्य रामटेककर, नितिन बड़गैया, मोनू वराड़े, नावेद खान एवं समस्त मित्र मंडल तथा सिविल अस्पताल लांजी से बीएमओ डॉ अक्षय उपराड़े, सचिन रावल, आशीष भरने, अंकित खरोले, इन्द्रजीत सहित अन्य स्टॉफ उपस्थित रहे। जिनके द्वारा फल, बिस्कुट और चाय बांटी एवं नवजात शिशुओं को वस्त्र वितरण कार्य किया गया तथा आशीष छोटू पटेल को भावपूर्ण श्रृद्धांजलि अर्पित की गई।

ग्रामीणों के दबाव पर प्रशासन की कार्रवाई

देवलगांव में करीब दो एकड़ शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त, मवेशियों की चराई प्रभावित होने पर ग्रामीणों ने छेड़ी मुहिम, अब पूरे गांव की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी; एसडीएम को सौंपेंगे ज्ञापन

पद्मेश न्यूज। लांजी। जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत देवलगांव में शासकीय चरनोई भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों की पहल रंग लाई। सोमवार 13 जुलाई को राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में खसरा-नक्शे के आधार पर सीमांकन कर करीब दो एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।ग्रामीणों का कहना है कि यह अभियान अब पूरे गांव की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तक जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार हल्का क्रमांक-36 में भूमिस्वामी तेजलाल टेंभरे एवं भूमेश्वर टेंभरे की पैतृक भूमि के सामने स्थित शासकीय भूमि पर विनोद टेंभरे एवं सोहन बागड़े द्वारा कथित रूप से अतिक्रमण कर लिया गया था। अतिक्रमण के कारण बारिश के मौसम में चरवाहों ने मवेशी चराना बंद कर दिया था। ग्रामीणों के अनुसार गांव में दो से तीन हजार मवेशी हैं, जिनके लिए यह चरनोई भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण है। चराई प्रभावित होने से किसानों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती पुष्पा कमलकिशोर ठाकरे को लिखित आवेदन देकर मांग की थी कि जब तक शासकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, तब तक मवेशियों को चराने नहीं ले जाया जाएगा।

हरे भरे पेड़ों की चढ़ गई बलि

ग्रामीणों के विरोध के बाद सोमवार को ग्राम सरपंच, पंच-प्रतिनिधि, पटवारी, कोटवार तथा गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संबंधित स्थल पर पहुंचकर राजस्व अमले ने खसरा एवं नक्शे के अनुसार भूमि की नाप-जोख की। सीमांकन के दौरान शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर जेसीबी से हटाकर करीब दो एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण के दौरान शासकीय भूमि पर लगे पलाश के हरे-भरे पेड़ों की भी कटाई कर दी गई थी। कार्रवाई के दौरान उक्त भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय भूमि गांव की सार्वजनिक संपत्ति है और इसका उपयोग पूरे गांव के हित में होना चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।

अब पूरे गांव से अतिक्रमण हटाने की तैयारी

ग्रामीणों का कहना है कि देवलगांव में 10 से 15 अन्य लोगों ने भी शासकीय भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामीणों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ने लगभग दो से तीन एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है तथा कई स्थानों पर हरे-भरे पेड़ों की भी कटाई की गई है। इसे लेकर ग्रामीणों ने पूरे गांव की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि 14 जुलाई को अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) लांजी को ज्ञापन सौंपकर गांव की समस्त शासकीय भूमि का सीमांकन कराने, सभी अतिक्रमण हटाने तथा शासकीय भूमि पर पेड़ों की कटाई के मामलों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की जाएगी।

अब अपील का इंतजार नहीं, 16वें दिन स्वत होगी कार्रवाई

लोक सेवा गारंटी में बड़ा बदलाव, लापरवाह अधिकारियों पर लगेगी पेनाल्टी

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब तय समय-सीमा में नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदक की अपील का इंतजार नहीं किया जाएगा। यदि निर्धारित समय में सेवा नहीं दी जाती है तो समय-सीमा समाप्त होने के 16वें दिन प्रथम और द्वितीय अपील प्राधिकारी स्वत- (सुओ मोटू) संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे।

राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 में संशोधन कर इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। संशोधित नियमों का 9 जुलाई से गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही प्रभावी हो गया है। सरकार जल्द ही लोक सेवा गारंटी पोर्टल में भी इसके लिए तकनीकी प्रावधान करेगी, जिससे लंबित मामलों की स्वत- निगरानी और कार्रवाई संभव हो सके।

अब नहीं टलेगी कार्रवाई

अब तक यदि किसी अधिकारी ने समय-सीमा में सेवा नहीं दी, तो कार्रवाई के लिए नागरिक को स्वयं प्रथम और फिर द्वितीय अपील करनी पड़ती थी। कई मामलों में लोग अपील नहीं करते थे, जिससे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। नई व्यवस्था के तहत यदि सेवा तय समय में नहीं मिलती है तो 16वें दिन अपीलीय अधिकारी बिना किसी आवेदन के स्वत- रिकॉर्ड मंगाकर मामले की सुनवाई करेंगे और आवश्यक आदेश जारी करेंगे। इसके लिए नागरिक को अलग से दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

लापरवाही पर 500 से 5,000 रुपये तक जुर्माना

संशोधित नियमों के अनुसार यदि द्वितीय अपील प्राधिकारी यह पाता है कि संबंधित अधिकारी ने बिना उचित कारण के सेवा उपलब्ध नहीं कराई, तो उस पर 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना लगाया जा सकेगा। यदि अधिकारी ने बिना पर्याप्त कारण के सेवा देने में देरी की है, तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी। हालांकि, किसी भी प्रकार की पेनाल्टी लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा।

अपील की व्यवस्था बनी रहेगी

संशोधन के बावजूद नागरिकों का अपील का अधिकार यथावत रहेगा। सेवा नहीं मिलने या आवेदन निरस्त होने पर 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील की जा सकेगी। प्रथम अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने पर 60 दिनों के भीतर द्वितीय अपील का अधिकार रहेगा। दोनों अपीलीय अधिकारियों को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त हैं, जिससे वे प्रभावी निर्णय ले सकें।

32 विभागों की 665 सेवाएं दायरे में

मध्यप्रदेश ने वर्ष 2010 में देश का पहला राइट टू सर्विस (लोक सेवा गारंटी) कानून लागू किया था। वर्तमान में इस कानून के तहत 32 सरकारी विभागों की 665 सेवाएं शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन, राशन कार्ड, पेयजल कनेक्शन, भूमि अभिलेखों की प्रतियां और अन्य नागरिक सेवाएं जैसी सुविधाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाती हैं।

एआई से होगी सेवाओं की निगरानी

सरकार लोक सेवा गारंटी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा तेज बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। इससे लंबित मामलों की पहचान, समय-सीमा की निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही स्वत- सुनिश्चित की जा सकेगी।

107 मंडी निरीक्षक बने मंडी सचिव

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज मंडी बोर्ड ने विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति की दूसरी सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार 107 मंडी निरीक्षकों को पदोन्नत कर मंडी सचिव बनाया गया है। वहीं 15 मंडी सचिव-'स' को मंडी सचिव-'ब' के पद पर प्रमोशन दिया गया है। भोपाल में आरपी गुना को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडी बोर्ड का कहना है कि पदोन्नति से लंबे समय से रिक्त या प्रभार के भरोसे चल रही कृषि उपज मंडियों में नियमित अधिकारियों की नियुक्ति होगी। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान संभव होगा। इसके अलावा 20 सहायक वर्ग-2 कर्मचारियों तथा 12 सहायक यंत्रियों को भी पदोन्नत कर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

लांजी में ''पद्मेश''

इंटरनेट (ब्राडबेंड) कनेक्शन के लिये संपर्क करें

Mo. 8319969927

एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा

भोपाल-इंदौर में बनेंगे बड़े आईटी पार्क

मध्य प्रदेश में 40 हजार करोड़ के निवेश की तैयारी

भोपाल। मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। भोपाल में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश अब केवल कृषि और खनिज तक सीमित नहीं है, बल्कि डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, एआई और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे भविष्य के उद्योगों का नया केंद्र बन रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया और गूगल प्ले व एमपीएसईडीसी के बीच अहम एमओयू भी हुआ। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि इस कॉन्क्लेव के जरिए 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव आने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने तीन बड़े ऐलान भी किए। भोपाल में 4 लाख वर्गफीट का अत्याधुनिक आईटी पार्क, इंदौर आईटी कॉरिडोर में 3 लाख वर्गफीट का नया आईटी पार्क और सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा टेक कंपनियों के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। सीएम ने कहा कि पिछले दो वर्षों में टेक सेक्टर में किए गए वादों को सरकार ने पूरा किया है और अब तक 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जमीन पर उतर चुका है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बने सेमीकंडक्टर और हाई-टेक उत्पाद दुनिया के कई देशों तक पहुंचेंगे।

भारी निवेश करने जा रहीं कंपनियां

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि जीआईएस में प्रदेश को अभूतपूर्व निवेश मिला। इसमें 10 लाख करोड़ निवेश धरातल पर उतर चुका है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 इसी औद्योगिक निवेश यात्रा का एक पड़ाव है। आज मध्यप्रदेश में जीसीसी, डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के विकास के लिए निवेश और भविष्य की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अब तक 12 हजार करोड़ से अधिक निवेश धरातल पर आ चुका है और आगे भी इस पर काम हो रहा है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में अलग-अलग दिग्गज टेक कंपनियां 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रही हैं।

सीएम के सहयोग से मजबूत हुआ विश्वास

प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम. सेल्वेंद्रन ने कहा कि एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन महत्वपूर्ण है। इस आयोजन में जीसीसी, डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के विकास पर चर्चा होगी और पॉलिसी में आवश्यक बदलाव भी करेंगे। सबमर बार्सिलोना के सीईओ पैट्रिक स्मिथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में सबमर ग्रुप का निवेश भारत के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए संभावनाएं तलाश रही थी और मध्यप्रदेश इसके लिए सबसे बेहतर है। इस महत्वपूर्ण साझेदारी से डेटा सेंटर और एआई टेक्नोलॉजी के विकास पर काम करेंगे। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एआई न केवल अर्थव्यवस्था के लिए अहम है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी सेक्टर में भविष्य का लीडर बनेगा। मध्यप्रदेश सरकार और यहां के मुख्यमंत्री के सहयोग से हमारा विश्वास मजबूत हुआ है।

एमपी में बने प्रोडक्ट दुनियाभर में जाएंगे

सिद्धार्थ रेड्डी ने कहा कि पहली एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में डेटा सेंटर, दूसरी में सेमीकंडक्टर पॉलिसी और तीसरी में जीसीसी, डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में डिजिट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। पारस सेमीकंडक्टर के सीईओ संतोष कुमार ने कहा कि सेमीकंडक्टर डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ है। डिजिटल सेक्टर में सेमीकंडक्टर न्यू ऑयल के समान है। पारस सेमीकंडक्टर मध्यप्रदेश में 6000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हम यहां केवल निवेश ही नहीं करेंगे, बल्कि एक डिजिटल इंडस्ट्री के निर्माण के लिए इकोसिस्टम विकसित करने में भी सहयोग करेंगे। मध्यप्रदेश में बने सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में सप्लाई होंगे। शिवानंद कोटेश्वर ने कहा कि देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों में टेक इंडस्ट्री के विकास के लिए मध्यप्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। टेक कंपनियों के लिए पर्याप्त मात्रा में कुशल कामगार उपलब्ध हैं।

सीएम ने की ये प्रमुख घोषणाएं

- इंदौर आईटी कॉरीडोर में 3 लाख वर्ग फीट क्षेत्र के अत्याधुनिक आईटी पार्क का विकास किया जाएगा। इससे जीसीसी, डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सेक्टर की कंपनियों को वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी उपलब्ध कराएगा।
- सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस- इस क्षेत्र में कौशल विकास एवं उद्योग क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करेगा।
- भोपाल में 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र का बड़ा आईटी पार्क बनेगा। यहां टेक कंपनियों को प्लग एंड प्ले के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्री पार्क में भी 5 एकड़ क्षेत्र में प्लग एंड प्ले फैसिलिटी तैयार की जाएगी।

कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने दिग्गजों की मौजूदगी में दाखिल किया नामांकन

- मीनाक्षी नटराजन प्रकरण' से सबक ले उतारे 2 डमी उम्मीदवार

भोपाल। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने न्यू कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना चुनावी नामांकन पत्र जमा कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी एकजुटता दिखाई, बल्कि 'मीनाक्षी नटराजन मामले' से सबक लेते हुए बेहद सतर्कता बरती और मुख्य प्रत्याशी के साथ-साथ दो डमी उम्मीदवारों के भी फॉर्म दाखिल करवाए हैं, ताकि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी या सियासी उलटफेर की गुंजाइश न रहे।

घनश्याम सिंह के नामांकन के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। उनके साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया, पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, अशोक सिंह और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा, नामांकन प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जो इस उपचुनाव में कांग्रेस को अपना खुला समर्थन देते नजर आए। एक्ज़िक्यूटिवब्रांच

नरोत्तम मिश्रा का दर्द मुख्यमंत्री नहीं बांट रहे

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव को मजबूती से जीतेगी। भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा का दर्द वर्तमान मुख्यमंत्री भी नहीं बांट रहे हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने 'थंब्स-अप' (जीत का इशारा) दिखाते हुए दावा किया कि जिस तरह 2023 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, उसी तरह 2026 के इस उपचुनाव में भी कांग्रेस ही परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से जनता और कांग्रेस दोनों खुश हैं।

25 हजार वोटों से जीतेंगे

कांग्रेस प्रत्याशी कुंअर घनश्याम सिंह ने कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज नामांकन दाखिल कर दिया गया है। अब कांग्रेस पूरी ताकत (पूरे डैम) के साथ मैदान में उतरेगी। दतिया में पिछले कुछ समय में जो डर और खराब वातावरण बना था, अब उसे सही करने का समय आ गया है। हम यह चुनाव 25,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीतेंगे।

कुख्यात वन्यजीव शिकारी अजीत पारधी की जमानत निरस्त, मध्यप्रदेश लाने की तैयारी

भोपाल। मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) को वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2013 में पेंच टाइगर रिजर्व में दर्ज बाघ शिकार प्रकरण के कुख्यात आरोपी अजीत पारधी की जमानत विशेष न्यायालय, जबलपुर ने निरस्त कर दी है। न्यायालय अब आरोपी की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करेगा, जिसके बाद उसे महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश लाकर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अजीत पारधी को एसटीएसएफ ने 11 वर्षों की फरारी के बाद 18 जुलाई 2024 को बालाघाट जिले से गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने के बावजूद उसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान 25 जनवरी 2025 को उसे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ शिकार के एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में वह जिला जेल चंद्रपुर में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है। एसटीएसएफ ने वर्ष 2025 में उसकी जमानत निरस्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। लोक अभियोजन अधिकारी के तर्कों और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर विशेष न्यायालय ने माना कि आरोपी जमानत पर रहने योग्य नहीं है। इसके बाद उसकी जमानत और बंधपत्र निरस्त कर दिए गए। यह प्रदेश का उन विरले मामलों में शामिल है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 480 के तहत जांच एजेंसी के आवेदन पर पहले से जमानत प्राप्त आरोपी की जमानत रद्द की गई है।

दतिया उपचुनाव: भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भरा नामांकन, मुख्यमंत्री ने विकास के नाम पर मांगा जनसमर्थन

दतिया/भोपाल(ईएमएस)। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खण्डेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह और वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में दतिया कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद किला चौक पर आयोजित विशाल जनसभा में भाजपा नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसमर्थन की अपील की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दतिया का उपचुनाव केवल एक विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि विकास और जनसेवा की दिशा तय करने वाला चुनाव है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक सामान्य कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है और जनता के आशीर्वाद से दतिया के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश सरकार रोजगार सृजन के लिए आईटी, सेमीकंडक्टर और डिफेंस पार्क जैसे क्षेत्रों में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश ला रही है तथा गुना, शिवपुरी और दतिया सहित पूरे क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि दतिया की जनता विकास, सुशासन और भाजपा की जनकल्याणकारी नीतियों के साथ खड़ी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय होकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाने तथा पार्टी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सेवा, समर्पण और संघर्ष की परंपरा के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने दतिया में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए आशुतोष तिवारी को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने का संकल्प दोहराया।

भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने स्वयं को दतिया की जनता का बेटा बताते हुए कहा कि वे जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के कई मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

107 मंडी निरीक्षक बने मंडी सचिव

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज मंडी बोर्ड ने विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति की दूसरी सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार 107 मंडी निरीक्षकों को पदोन्नत कर मंडी सचिव बनाया गया है। वहीं 15 मंडी सचिव-'स' को मंडी सचिव-'ब' के पद पर प्रमोशन दिया गया है। भोपाल में आरपी गुना को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडी बोर्ड का कहना है कि पदोन्नति से लंबे समय से रिक्त या प्रभार के भरोसे चल रही कृषि उपज मंडियों में नियमित अधिकारियों की नियुक्ति होगी। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान संभव होगा। इसके अलावा 20 सहायक वर्ग-2 कर्मचारियों तथा 12 सहायक यंत्रियों को भी पदोन्नत कर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

भोपाल में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग का अजब कारनामा

भोपाल । राजधानी भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले पुल और दीवार के अंदर बने सार्वजनिक शौचालय के बाद अब लोक निर्माण विभाग की इंजीनियरिंग का एक और कारनामा सामने आया है। भोपाल के वार्ड-64 स्थित भेल नगर कॉलोनी में बनाई जा रही 80 फीट चौड़ी सीमेंट-कांक्रीट सडक् के बीच एक बड़ा आम का पेड़ खड़ा छोड़ दिया गया है। पेड़ को हटाने या सुरक्षित स्थानांतरित करने के बजाय उसके दोनों ओर सडक् बना दी गई, जिससे वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा पैदा हो गया है। रहवासियों का कहना है कि सडक् के बीच पेड़ होने से वाहन चालकों को अचानक रास्ता बदलना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। रात में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट, रिफ्लेक्टर और चेतावनी संकेत नहीं होने से अनजान दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के पेड़ से टकराने की आशंका बनी रहती है। संभावित हादसे को लेकर भेल नगर के रहवासियों ने तेज सिंह ठाकुर की अगुवाई में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों, ठेकेदार, क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम आयुक्त से शिकायत कर समाधान की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खतरे की जानकारी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन काम नहीं रोका गया और पेड़ के दोनों ओर सडक् बना दी गई। रहवासी पेड़ काटने के नही, बल्कि तकनीकी प्रक्रिया के तहत उसे सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे है ताकि पेड़ भी बचे और हादसों का खतरा भी टले। मकान नंबर 43/ए के सामने सडक् के ठीक बीच एक बड़ा आम का पेड़ है। रहवासी सवाल उठा रहे है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं।

10 महीने वेतन-भत्ता नहीं लेंगे विधायक डोडियार

एलएलएम की पढ़ाई के लिए विधायक कमलेश्वर ने छोड़ा वेतन-भत्ता

भोपाल। मध्य प्रदेश के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने 10 महीने तक वेतन और भत्ता नहीं लेने का ऐलान किया हैं। इसे लेकर उन्होंने एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है। जिसमें लिखा है कि 20 जुलाई 2026 से 15 मई 2027 तक देय विधायक वेतन और भत्तों का भुगतान स्थगित करने की बात कहीं है। रतलाम जिले की सैलाना से भारत आदिवासी पार्टी विधायक कमलेश्वर डोडियार ने 10 महीने का वेतन और भत्ता नहीं लेने की घोषणा की हैं। दरअसल, कमलेश्वर ने एलएलएम में एडमिशन लिया है, पढ़ाई के चलते उन्होंने यह निर्णय लिया है। इसे लेकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र भी लिखा हैं।

डोडियार ने कहा कि नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल में एक वर्षीय एलएलएम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स में अध्ययन एवं शैक्षणिक कार्यों में दिनांक 20 जुलाई 2026 से संलग्न रहूंगा। इस कारण मैं अपनी स्वेच्छा से विधायक के रूप में देय वेतन एवं भत्ते ग्रहण नहीं करना चाहता हूं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मेरे इस स्वैच्छिक निर्णय को स्वीकार करते हुए, दिनांक 20 जुलाई 2026 से 15 मई 2027 तक नियमित कक्षाओं और परीक्षाओं के चलते मुझे देय विधायक वेतन एवं भत्तों का भुगतान स्थगित करने का कष्ट करें। विधायक कमलेश्वर ने पत्र में यह भी लिखा कि करीब 10 महीने का वेतन भत्ता छोड़ने के बाद जरूरी समय पर मैं स्वयं के खर्चे से विधानसभा क्षेत्र में दौरे कार्यक्रम और जन सुनवाई जैसे कार्यक्रमों में उपस्थिति आदि सुनिश्चित करूंगा। यह भी कि अध्ययन के दौरान विधानसभा सदस्य के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन प्राथमिकता से करूंगा। कृपया मेरे आवेदन पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए की गई कार्रवाई से मुझे जन हित में अवगत कराने का कष्ट करें।'

विधानसभा सत्र और क्षेत्रीय दौरे जारी रहेंगे

विधायक ने स्पष्ट किया है कि पढ़ाई के बावजूद वे अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करते हुए वे विधानसभा सत्रों में प्राथमिकता से शामिल होंगे। साथ ही अपने निजी खर्च पर सैलाना विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, जनसुनवाई करेंगे और शासकीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे।

28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगी सेना भर्ती रैली

भोपाल। मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए 28 जुलाई से 8 अगस्त 2026 तक भोपाल के अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार, यह रैली प्रदेश के 15 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए होगी। इसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी, तकनीकी, ट्रेड्समैन सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए धर्म गुरु और एजुकेशन हवलदार पदों की भर्ती भी होगी। सामान्य प्रवेश परीक्षा में सफल शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की गई है।

मध्यप्रदेश में गायब हुए लोगों की होगी एफआईआर

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अलर्ट पर सभी पुलिस अधीक्षक

भोपाल। मध्य प्रदेश से गायब 1 लाख 26 हजार लोगों के परिवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एमपी पुलिस द्वारा दिए गए आदेश से थोड़ी राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश पुलिस में नई व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश में अब किसी वयस्क युवक-युवती अचानक गायब होने पर पुलिस को अब उसकी एफआईआर दर्ज करना होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

अभी तक ऐसे मामलों में पुलिस सिर्फ शिकायती आवेदन लेती थी, इक्का-दुक्का मामलों को छोड़ बाकी में कार्रवाई भी न के बराबर होती थी। मिसिंग पर्सन के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। प्रदेश में 1 लाख 26 हजार 163 लोग लापता हैं। इनमें 89352 महिलाएं जबकि 36811 पुरुष हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बदला नियम

वयस्कों की गुमशुदगी के मामले में एफआईआर का नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू हुआ है। दरअसल, जी गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। तमिलनाडु के जी गणेश की नाबालिग बेटी साल 2011 में लापता हो गई थी। कई जांच के बाद भी बच्ची का पता नहीं चला और पुलिस ने मामले को अनडिटेक्टेबल मानकर केस को बंद कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी गुमशुदा व्यक्तियों चाहे वह महिला हो या पुरुष पर भी लागू कर दी है।

अब क्या होगा

गुमशुदगी के मामले में अब तक अधिकांश मामलों में पुलिस सिर्फ शिकायती आवेदन लेती थी। एफआईआर और गंभीरता आमतौर पर महिलाओं के उन्हीं मामलों में दिखाई देती थी, जिसमें अपहरण या किसी दूसरे अपराध होने का संदेह होता था, लेकिन अब गुमशुदगी के हर मामले में पुलिस को एफआरआई करनी होगी। पीड़ित परिजन के शिकायत लेकर पहुंचने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 (3) के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। हालांकि स्पेशल डीजी महिला अपराध अनिल कुमार के मुताबिक अब वयस्कों की गुमशुदगी के मामलों में अपहरण, मानव दुर्व्यापार और दूसरे अपराध के तथ्य मिलने पर इससे जुड़ी धाराओं को भी जोड़ा जाएगा। यानी गुमशुदगी के मामले में एफआईआर तो दर्ज होगी, लेकिन इसके बाद पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि जांच में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपहरण या कोई दूसरे गंभीर अपराध के तथ्य नहीं मिले तो धाराएं नहीं बढ़ेंगी।

मध्य प्रदेश से गायब होने वालों के आंकड़े चौंकाने वाले

मध्य प्रदेश से बच्चों के गायब होने के अलावा वयस्कों के गायब होने के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक मिसिंग पर्सन के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। साल 2024 में मध्य प्रदेश में 65 हजार 338 लोग गुमशुदा हुए, इसमें युवतियों की संख्या सबसे ज्यादा है। गायब हुई महिलाओं की संख्या 46732 और पुरुषों की संख्या 18 हजार 606 है। मध्य प्रदेश में पिछले सालों से गुम 60 हजार 825 लोगों को अभी तक नहीं खोजा जा सका है।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने का विरोध तेज

विधायक आरिफ मसूद ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन; 38 साल पुरानी पहचान बरकरार रखने की मांग

भोपाल । भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय किए जाने के प्रस्ताव का विरोध अब राजनीतिक स्तर पर भी तेज हो गया है। भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद ने सोमवार को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय का नाम यथावत रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि 38 वर्ष पुरानी शैक्षणिक संस्था की पहचान समाप्त करना उचित नहीं है। यदि सरकार वाग्देवी भोजपाल के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है तो नए विश्वविद्यालय की स्थापना कर उसका नाम रखा जाए।

ज्ञापन में मसूद ने कहा कि 3 जून 2026 को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्ताव में महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना बरकतउल्ला भोपाली के योगदान को कमतर आंकते हुए यह लिखा गया कि उनका जीवन विदेश में बीता और भोपाल के निवासी होने के अलावा उनका कोई विशेष योगदान नजर नहीं आता। मसूद ने इसे एक महान देशभक्त का अपमान बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की।

राज्यपाल को दिए ज्ञापन में आरिफ मसूद ने मौलाना बरकतउल्ला भोपाली के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि वे जापान में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार से जुड़े रहे। वर्ष 1913 में उन्होंने लाला हरदयाल के साथ गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में काम किया और उसके समाचार पत्र में देशभक्ति से जुड़े लेख लिखे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान के काबुल में गठित स्वतंत्र भारत की पहली निर्वासित अंतरिम सरकार में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रपति और मौलाना बरकतउल्ला भोपाली प्रधानमंत्री बनाए गए थे। इसके अलावा उन्होंने रूस में लेनिन से मुलाकात कर भारत की आजादी के लिए समर्थन भी मांगा था।

लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा

भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को 270 रन से रौंदा

लॉर्ड्स। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान पर पहली बार महिला टीमों के बीच खेले गये टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है। भारतीय महिला टीम को जीत के लिए चौथे दिन चार विकेट की जरूरत थी जो उसने आसानी से हासिल कर लिए। 457 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम इंग्लैंड तीसरे दिन के 6 विकेट पर 130 रनों से आगे खेलते हुए अपनी दूसरी पारी में 186 रनों पर ही सिमट गयी। मैच में शानदार गेंदबाजी के लिए भारतीय टीम की गेंदबाज क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने आज सुबह केवल 5 रन बनाकर ही एक विकेट खेल और 1 विकेट खो दिया। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। वहीं इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट पर 151 से आगे खेलते हुए सात विकेट पर 341 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 115 रनों की बढ़त मिली थी, जिसके कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसकी आधी टीम 150 रनों पर ही आउट

हो गयी थी। तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने इंग्लैंड की पहली पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। इसके साथ ही वह लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर पांच विकेट लेकर नाम दर्ज कराने वाली इतिहास की पहली महिला क्रिकेटर बन गईं। विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने भारत की दूसरी पारी में दबाव की परिस्थितियों में 113 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। इस शतक के बल पर उन्होंने भी पहली बार बतौर महिला बल्लेबाज लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया।

पहली बार महिला टीमों के बीच यहां हुए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली। मंधाना ने पहली पारी में 83 बनाए, कप्तान कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने भी 57 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 3, लॉरेन फिलर, इस्सी वोंग और मैडी विलियर्स ने 2-2 विकेट लिए। लॉरेन बेल को एक सफलता मिली।

भारत के पहली पारी में 285 रन के जवाब इंग्लैंड की पहली पारी सिर्फ 170 रनों पर सिमट गई। विकेटकीपर बल्लेबाज एमी जोंस ने 52, कप्तान नेट साइवर ब्रंट ने 44 रन बनाए। मैया बूचियर ने 23 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से क्रांति गौड ने 17 ओवर में 37 रन देकर पांच विकेट लिए। लॉर्ड के लीडरबोर्ड पर अपना नाम लिखाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनीं। सयाली सतघरे और स्नेह राणा को दो- दो विकेट मिले। दीप्ति शर्मा ने एक विकेट लिय। भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 115 रनों की बढ़त मिली।

इस मैच में जीत के साथ ह 149 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारतीय महिला टीम इस मैदान पर टेस्ट मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन गयी। इस ऐतिहासिक मैच में कई व्यक्तिगत उपलब्धियां भी दर्ज की गई हैं। भारत की क्रांति गौड़ और यस्तिका भाटिया ने सबसे पहले इस बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया। क्रांति गौड़ ने इंग्लैंड की पहली पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए जबकि यस्तिका यहां शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। वहीं मेजबान इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने भी इस विकेट पर भारतीय टीम के खिलाफ 5 विकेट लेकर एक रिकार्ड अपने नाम किया। इस मैच में पूरे समय भारतीय टीम हावी रही। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा की अर्धशतकीय पारियों की सहायता से पहली पारी में 285 रन बनाये। वहीं इसके बाद मेजबान टीम अपनी पहली पारी में केवल 170 रन ही बना पायी। भारतीय टीम की ओर से क्रांति गौड़ ने से 5 विकेट हॉल लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इंग्लैंड की तरफ से केवल एमी जोन्स ने अर्धशतक और कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने भी 44 रन बनाये। पहली पारी में 115 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने के बाद भारतीय टीम ने दूसरी पारी में यस्तिका भाटिया के शानदार शतक 113 रनों और स्मृति मंधाना व ऋचा घोष के अर्धशतकों की मदद से 7 विकेट पर 341 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इससे मेजबानों को जीत के लिए 456 रनों का एक विशाल लक्ष्य मिला। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय इंग्लैंड की टीम ने अपने 6 विकेट केवल 130 रनों पर ही खो दिये। इस प्रकार मेजबानों को जीत के लिए अभी भी 327 रनों की जरूरत थी पर उसके बचे हुए बल्लेबाज रन बनाने में असफल रहे।

फीफा 2026 सेमीफाइनल

मेसी पहली बार इंग्लैंड का मुकाबला करेंगे

अटलांटा। फीफा विश्वकप फुटबॉल के सेमीफाइनल में गुरुवार 15 जुलाई को फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला फ्रांस से होगा। इस मैच में सभी की नजरें अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी पर रहेंगी। इसका कारण है कि कि मेसी पहली बार इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे, इस मैच में जीत के साथ ही दोनो ही टीमें फाइनल में पहुंचना चाहेंगी। अपने दो दशक से अधिक लंबे शानदार करियर में मेसी ने फुटबॉल जगत की लगभग हर दिग्गज टीम के खिलाफ खेला है पर इंग्लैंड के खिलाफ वह कभी नहीं उतर हैं। स्विट्जरलैंड पर जीत के बाद ही मेसी ने इस मुकाबले को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा, सच कहूं तो यह बहुत खास है। मैंने इंग्लैंड के अलावा लगभग हर बड़ी टीम के खिलाफ खेला है। इंग्लैंड एक मजबूत और बड़ी टीम है। ऐसे मुकाबले, खासकर विश्व कप सेमीफाइनल में खेलना हमेशा ही एक अलग और रोमांचक होता है। मेसी ने अब तक ब्राजील, उरुग्वे, जर्मनी, इटली, स्पेन और फ्रांस जैसी विश्व चैंपियन टीमों के खिलाफ कई यादगार मैच खेलकर अपनी टीम को जीत दिलायी है पर इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसी बड़ी फुटबॉल शक्ति रही जिसके खिलाफ वह कभी नहीं उतरे। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सेमीफाइनल तक का सफर भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहा है। क्वार्टरफाइनल में उन्होंने स्विट्जरलैंड को अतिरिक्त समय में 3-1 से मात देकर अंतिम चार में अपनी जगह पक्की की। इस मैच में मेसी ने एलेक्सिस मैक एलिस्टर के गोल में शानदार असिस्ट दिया, जबकि जूलियन अल्वारेज़ और लाउतारो मार्टिनेज ने भी गोल दागे। मेसी ने स्वीकार किया, हम लगातार दबाव में खेल रहे हैं और इसका असर खिलाड़ियों पर पड़ा है। लेकिन टीम पूरी तरह तैयार है और अब तक जिस तरह खेली है, उसी अंदाज में आगे भी मुकाबला करेगी। वहीं इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच इससे पहले 2002 फीफा विश्व कप में टक्कर हुई थी तब इंग्लैंड ने 1-0 से जीत दर्ज की थी।

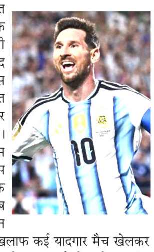

दक्षिण कोरिया के किम ने स्कॉटिश ओपन के साथ ही रोलेक्स सीरीज जीती

नॉर्थ बेरविक। दक्षिण कोरिया के स्टार गोल्फर टॉम किम ने स्कॉटिश ओपन 2026 खिताब जीतने के साथ ही रोलेक्स सीरीज अपने नाम की है। टॉम किम ने अंतिम और निर्णायक राउंड में बिना एक भी बोगी गंवाये 6-अंडर 64 का स्कोर बनाकर दो शॉट की निर्णायक बढ़त के साथ ही मुकाबला अपने नाम किया। इसके साथ ही किन ने पहली बार प्रतिष्ठित रोलेक्स सीरीज का खिताब जीता है। किम ने पूरे फाइनल राउंड में धैर्य से खेलते हुए शानदार खेल दिखाया। उनकी जीत का सबसे अहम पल 16वें होल पर आया, जहां उन्होंने 203 यार्ड की दूरी से एक अच्छा शॉट खेलकर गेंद को छह फीट के अंदर पहुंचाया। इस शानदार शॉट के बाद उन्होंने बर्डी लगाई और दो शॉट की निर्णायक बढ़त भी प्राप्त की। ली। इस बढ़त को अंत तक बनाये रखकर खिताब जीता। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मिन वू ली ने 67 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। दूसरी ओर स्कॉटलैंड के रॉबर्ट मैकइंटायर, इंग्लैंड के मैट फिट्ज़पैट्रिक, जापान के कीता नाकाजिमा और अमेरिका के जॉनी कीफर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे।

फीफा विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भिड़ेंगे फ्रांस और स्पेन

डलास। फीफा विश्व कप 2026 अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और अब दुनिया की दो दिग्गज फुटबॉल टीमें फ्रांस और स्पेन पहले सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला बुधवार, 15 जुलाई को रात 12:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमों का लक्ष्य जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाना होगा, ऐसे में फुटबॉल प्रेमियों को रोमांचक और कांटे की टक्कर देखने की उम्मीद है।

फ्रांस ने पूरे टूर्नामेंट में संतुलित खेल का प्रदर्शन किया है। मजबूत रक्षा पंक्ति, तेज आक्रमण और मिडफील्ड पर नियंत्रण के दम पर टीम ने नॉकआउट चरण में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया। टीम के खिलाड़ी बेहतरीन लय में हैं और बड़े मुकाबलों का अनुभव भी उसके पक्ष में माना जा रहा है।

दूसरी ओर स्पेन ने अपनी पारंपरिक पासिंग फुटबॉल और आक्रामक रणनीति से विरोधी टीमों को लगातार चुनौती दी है। क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के संतुलित संयोजन ने स्पेन को इस विश्व कप की सबसे मजबूत टीमों में शामिल कर दिया है। टीम गेंद पर नियंत्रण बनाए रखने और अवसरों को गोल में बदलने की क्षमता के कारण किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुकाबला केवल दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि दो अलग-अलग फुटबॉल शैलियों की टक्कर भी होगा। फ्रांस जहां तेज काउंटर अटैक और शारीरिक मजबूती के लिए जाना जाता है, वहीं स्पेन छोटे-छोटे पास, गेंद पर कब्जा और सामूहिक खेल के दम पर मैच का रुख बदलने में माहिर है। ऐसे में मैच का परिणाम खिलाड़ियों के संयम, रणनीति और मौके भुनाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे विश्व कप 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम तीसरे स्थान के लिए होने वाले मुकाबले में उतरेगी। दुनियाभर के करोड़ों फुटबॉल प्रशंसकों की निगाहें इस हाई-वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हैं। दोनों टीमों के पास विश्व फुटबॉल में गौरवशाली इतिहास है और वे एक बार फिर विश्व चैंपियन बनने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। ऐसे में यह सेमीफाइनल विश्व कप के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक साबित हो सकता है।

सीएसके ने फ्लेमिंग को मुख्य कोच पद से हटाया

चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने पिछले 17 साल से टीम के मुख्य कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग को मुख्य कोच पद से हटा दिया है। पिछले कुछ आईपीएल सत्र से टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और वह अंतिम दो स्थानों तक सिमट गयी है। जिसके बाद से ही कोचिंग में बदलाव की मांग की जा रही थी। माना जा रहा है कि अब किसी भारतीय को कोच पद की जिम्मेदारी मिल सकती है।

फ्लेमिंग ने आईपीएल के शुरुआती सत्र में एक खिलाड़ी के तौर पर शुरुआत की थी और 2009 से ही टीम के मुख्य कोच का पद संभाला था। फ्रेंचाइजी के वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान में डलास में हैं, जहां वे पिछले कुछ सीजन की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं। चेन्नई सुपर

किंग्स क्रिकेट लिमिटेड की पूर्णकालिक निदेशक रूपा गुरुनाथ इन महत्वपूर्ण फैसलों की निगरानी कर रही हैं, जिसमें खिलाड़ियों के आदान-प्रदान के साथ-साथ पूरे कोचिंग स्टाफ में संभावित बड़े बदलाव भी शामिल हैं।

एक प्रेस रिलीज में, गुरुनाथ ने फ्लेमिंग के योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, फ्लेमिंग इस फ्रेंचाइजी के लगभग पूरे सफर में हमारी कोचिंग यूनिट का मुख्य आधार रहे हैं। लगभग दो दशकों तक, उन्होंने हमारी पहचान, विजन और बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश को आकार देने में मदद की है। उन्होंने आगे कहा, सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी की ओर से, हम उनकी अटूट प्रतिबद्धता, जुनून और लीडरशिप के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। भले ही मैदान पर हमारा साथ अब समाप्त हो रहा है पर वह हमेशा टीम की विरासत का अहम हिस्सा बने रहेंगे।

पूर्व क्रिकेटर हेमांग बदानी को सीएसके कोचिंग सेटअप में अहम भूमिका दी जा सकती है। बदानी ने पिछले दो सत्र में दिल्ली कैपिटल्स में मुख्य कोच के रूप में कार्य किया था, जहां उनकी टीम क्रमश: पांचवें और छठे स्थान पर रही थी; अपने पहले सीजन में टीम बहुत कम अंतर से प्लेऑफ में जगह बनाने से रह थी।

शुभमन की कप्तानी में एकदिवसीय सीरीज में जीत के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम रोहित, विराट करेंगे वापसी

लंदन। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम मंगलवार से मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेलने उतरेगी। इस सीरीज से अनुभवी बल्लेबाजी रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में वापसी करेंगे। इसके अलावा आईपीएल के बाद आराम कर रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी खेलते दिखेंगे। ये सीरीज भारतीय प्रशंसकों के लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसमें उन्हें एक बार फिर विराट और रोहित को बल्लेबाजी करते देखने का अवसर मिलेगा। सीरीज का पहला मैच 14 जुलाई, मंगलवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। वहीं सीरीज का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई, गुरुवार को कार्डिफ के सोफिया गार्डस में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 19 जुलाई, रविवार को लंदन

के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा। इस अंतिम मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर होगी।

विराट और रोहित की वापसी से भारतीय शीर्ष क्रम को जबरदस्त मजबूती मिलेगी, जबकि बुमराह एक बार फिर तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे। उन्हें अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा से उन्हें साथ मिलेगा। स्पिन की कमान कुलदीप यादव संभालेंगे। वहीं अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर के तौर पर उतरेंगे। विकेटकीपिंग के विकल्प के तौर पर केएल राहुल और ईशान किशन रहेंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर शिवम दुबे और तेज गेंदबाज प्रिंस यादव से भी टीम के पास अच्छे विकल्प रहेंगे। शुभमन के लिए ये दौरा बेहद अहम रहेगा। हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम टी20 में जीत के बाद से ही उत्साह से भरी हुई है। टीम में जोस बटलर, जो रूट, जोफ्रा आर्चर और सैम कुर्रन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो घरेलू हालातों में मैच का रुख कभी भी मोड़ सकते हैं।

एकदिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव।

इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में रोहित और विराट बना सकते हैं नये रिकार्ड

लंदन। आक्रामक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली यहां इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार से शुरु हो रही एकदिवसीय सीरीज में बड़े रिकार्ड बना सकते हैं। ऐसे में प्रशंसकों की नजरें इन दो दिग्गजों पर रहेंगी। एकदिवसीय क्रिकेट में अभी सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित आठवें स्थान पर हैं। 285 मैचों की 277 पारियों में 48.83 की औसत से उन्होंने 11720 रन बनाए हैं, जिसमें 62 अर्धशतक और 33 शतक शामिल हैं। अब वह इस सीरीज में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक का रिकार्ड तोड़ सकते हैं। इंजमाम ने एकदिवसीय में 11739 रन बनाए हैं। इंग्लैंड सीरीज में केवल 20 रन बनाते ही हिटमैन इंजमाम को पीछे छोड़कर

सातवें स्थान पर आ जाएंगे। इसके बाद उनका अगला लक्ष्य श्रीलंका के महेला जयवर्धने होंगे, जिनके नाम 12650 रन दर्ज हैं। वहीं दूसरी ओर विराट एकदिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर कायम हैं। 311 मैचों की 299 पारियों में 58.71 की शानदार औसत से उन्होंने अब तक 14797 रन बनाए हैं। ऐसे में विराट की नजरें 15,000 एकदिवसीय रन का रिकार्ड बनाने पर रहेंगी। इसके लिए उन्हें केवल 203 रन की जरूरत है। अगर विराट यह मुकाम इस सीरीज में हासिल कर लेते हैं, तो वह एकदिवसीय इतिहास में 15,000 रन पूरे करने वाले सचिन तेंदुलकर (18426 रन) के बाद दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे।

यास्तिका ने लॉर्ड्स में बनाया रिकार्ड

लंदन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शतक लगाने के साथ ही एक नया रिकार्ड अपने नाम किया है। इसी के साथ ही यास्तिका लॉर्ड्स में शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गईं हैं। इससे उनका नाम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर बोर्ड पर लिखा गया। यास्तिका के शतक से भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में सात विकेट पर 341 रनों का अच्छा खासा स्कोर बनाने में सफल रही। यास्तिका ने 158 गेंदों में 14 चौके लगाकर 113 रन बनाये। इस बल्लेबाजी ने वोंग की गेंद पर एक रन लेकर अपना शतक पूरा किया। जड़ा। वहीं इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने भी 118 रन देकर पांच विकेट लिए।

साल के अंत में नेपाल दौरे पर जाएगी भारत ए टीम

मुम्बई। भारत ए क्रिकेट टीम इस साल के अंत में नेपाल का दौरा करेगी। इस दौरे में भारत एक नेपाल टीम से तीन मैचों की सीरीज खेलेगी इससे नेपाल टीम को काफी लाभ होगा। दोनो ही देशों के क्रिकेट बोर्ड इस दौर को लेकर सहमत हैं। इस दौरे में सभी मुकाबले नेपाल के कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेले जाएंगे।

इस महत्वपूर्ण दौरे को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग हुए आईसीसी के सालान सम्मेलन के दौरान तय किया गया था।

द्रविड़ बन सकते हैं इंग्लैंड की टेस्ट टीम के मुख्य कोच

लंदन। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व कोच रहे राहुल द्रविड़ अब इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के नये मुख्य कोच बन सकते हैं। ब्रैंडन मैकुलम को टेस्ट टीम के मुख्य कोच पद से हटाए जाने के बाद से ही नये कोच के लिए अटकलें लगायी जाने लगी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में 1-2 की करारी हार के बाद से ही इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने ब्रैंडन मैकुलम को पद से हटाने का फैसला किया है हालांकि वह सीमित ओवरों के लिए मुख्य कोच बने रहेंगे। उनकी आक्रामक क्रिकेट की बैजबॉल रणनीति टेस्ट में असफल रही है। इसी को देखते हुए बोर्ड ने उन्हें हटाने का फैसला किया है। ईसीबी का मानना है कि अगले साल होने वाली प्रतिष्ठित एशेज सीरीज से पहले टीम में बदलाव के लिए यह जरुरी है। गौरतलब है कि मैकुलम

के चार साल के कार्यकाल के दौरान इंग्लैंड ने कुल 49 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से टीम को 27 में जीत और 20 में हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान इंग्लैंड का प्रदर्शन घरेलू मैदानों पर तो शानदार रहा, लेकिन विदेशी पिचों पर टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, जहां भारत (2023-24) और पाकिस्तान (2024-25) के दौरों पर मिली शर्मनाक सीरीज हार ने उनके बैजबॉल रणनीति को फेल कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार, ईसीबी ने मैकुलम के संभावित विकल्पों की एक सूची तैयार की है, जिसमें द्रविड़ का मुख्य दावेदार के तौर पर शामिल किया गया है। द्रविड़ के अलावा जिम्बाब्वे के पूर्व कोच एंडी फ्लावर और इंग्लैंड के पूर्व इंग्लिश स्पिनर रिचर्ड डॉसन, श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा, इंग्लैंड लायंस के कोच एंड्रयू फ्लिंटॉफ भी दावेदार हैं। वहीं कोच के लिए प्रमुख दावेदार द्रविड़ की गिनती दुनिया के सबसे समझदार और रणनीतिक रूप से मजबूत कोचों में होती है। उनके मार्गदर्शन में भारतीय टीम ने 2024 टी20 विश्व कप का खिताब जीता और 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल तक वह पहुंची थी। द्रविड़ की बारीक कोचिंग शैली, अनुशासन और रेड-बॉल (टेस्ट) क्रिकेट की गहरी समझ के कारण ही इंग्लैंड बोर्ड उन्हें इस पद के लिए सबसे बेहतर मान रहा है। हालांकि, रिपोर्ट यह भी बताती है कि राहुल द्रविड़ की पूर्णकालिक कोचिंग में वापसी की खास इच्छा नहीं रही है, लेकिन इंग्लैंड के टेस्ट कोच का पद उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें उन्हें घर पर बिताने के लिए लंबा समय मिलेगा और साथ ही अपने पसंदीदा प्रारूप (टेस्ट क्रिकेट) को जिंदा रखने में योगदान देने का मौका भी मिलेगा।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति लालबर्रा जिला-बालाघाट (म.प्र.)

क्रमांक/मंडी/तौलकांटा/2026-27/ लालबर्रा दिनांक

निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मंडी समिति लालबर्रा ब श्रेणी मंडी द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी0ओ0टी) के तहत संरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक 2026_MPSAM_520573_1 के अंतर्गत ऑनलाईन निविदायें दिनांक 22.07.2026 को शाम 03.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म0प्र0 शासन के ई-निविदा के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल **www.mpmandiboard.com.in** पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट:- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,लालबर्रा
जिला-बालाघाट(म.प्र.)

जून महीने में 4.38 प्रतिशत पर पहुंची खुदरा महंगाई

- 17 महीने में पहली बार टूटा आरबीआई का टारगेट

-खाने-पीने की चीजों और पेट्रोल-डीजल के महंगे होने से आम आदमी का बजट बिगड़ा

नई दिल्ली। जून महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38 फीसदी पर पहुंच गई है। सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से जारी इन आंकड़ों ने चिंता इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि पिछले 17 महीनों में यह पहला मौका है जब महंगाई ने रिजर्व बैंक के 4 फीसदी के सुरक्षित लक्ष्य को पार किया है। इससे पहले मई में यह आंकड़ा 3.93 फीसदी था।

महंगाई में इस ताजा उछाल की मुख्य वजह खाने-पीने के सामान और ईंधन की बढ़ती कीमतें हैं। इसके अलावा, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और मानसून की चाल को लेकर उठ रही चिंताओं ने भी कीमतों को ऊपर धकेलने का काम किया है। बाजार को भी कुछ ऐसे ही आंकड़ों की उम्मीद थी। अर्थशास्त्रियों ने इसके 4.3 फीसदी रहने का अनुमान जताया था। खास बात यह है कि जब से सीपीआई के लिए नया बेस ईयर और अपडेटेड बास्केट लागू हुआ है, तब से यह महंगाई का सबसे ऊंचा स्तर है।

खाने-पीने की चीजों ने बिगाड़ा बजट

महंगाई के इस आंकड़े में सबसे ज्यादा असर खाने-पीने के सामान पर दिखा है। जून में खाद्य महंगाई दर 5.32 फीसदी पर पहुंच गई, जो मई में 4.78 फीसदी थी। अगर इसे और बारीकी से देखें, तो ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई 5.45 फीसदी और शहरों में 5.09 फीसदी रही। हालांकि, कुछ सब्जियों ने थोड़ी राहत जरूर दी है। आलू की कीमतों में जून में 20.34 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई (मई में यह 23.71 फीसदी गिरी थी)। वहीं, टमाटर जो पिछले साल मई में 48 फीसदी से ज्यादा महंगा हो गया था, उसके दाम में भी इस बार 31.92 फीसदी की गिरावट आई है। लेकिन बाकी खाद्य पदार्थों की कीमतों ने इस राहत को बेअसर कर दिया।

पेट्रोल-डीजल ने बिगाडा खेल

सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि अब सफर करना और सामान की ढुलाई भी महंगी हो गई है। जून में ट्रांसपोर्ट महंगाई दर 4.31 फीसदी हो गई। इसकी बड़ी वजह यह रही कि सरकारी तेल कंपनियों ने मई के दौरान पेट्रोल-डीजल की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की थी। इसका सीधा असर माल ढुलाई (गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस) पर पड़ा है, जिसकी महंगाई दर उछलकर 7.70 फीसदी पर पहुंच गई है। ढुलाई महंगी होने का मतलब है कि बाजार तक पहुंचने वाला हर सामान अपने आप महंगा हो जाएगा।

कच्चे तेल से और बढ़ सकती है टेंशन

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आगे का रास्ता भी आसान नहीं है। 'अल नीनो' के चलते अगर इस साल मानसून कमजोर रहता है, तो फसलों की पैदावार बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। भारत में खेती काफी हद तक दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर है, क्योंकि देश के आधे से ज्यादा खेतों में सिंचाई की पक्की सुविधा नहीं है। दूसरी तरफ, दुनिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में ऊर्जा महंगी होने से देश का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है, रुपया कमजोर हो सकता है और आयातित महंगाई का खतरा पैदा हो सकता है।

कमजोर पड़ा मानसून, 372 जिले बारिश की कमी से प्रभावित; खरीफ फसलों पर बढ़ा संकट

नई दिल्ली । देश में मानसून की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ गई है, जिससे कृषि क्षेत्र की चिंता बढ़ गई है। ताजा स्थिति के अनुसार देश के 372 जिले सामान्य से कम वर्षा की मार झेल रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्षा की कमी बढ़कर 19 प्रतिशत तक पहुंच गई है। कमजोर बारिश का सबसे अधिक असर खरीफ फसलों की बुआई पर पड़ रहा है और किसानों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थिति को गंभीर मानते हुए 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करने का फैसला किया है। बैठक में वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों की स्थिति, फसलों पर पड़ रहे प्रभाव और किसानों को राहत देने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्यों को वैकल्पिक फसलें अपनाने और कृषि सलाह को गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। बारिश में कमी के कारण धान, सोयाबीन, कपास, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय लगातार राज्यों से जानकारी जुटा रहा है और हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है, लेकिन इससे पूरे देश में वर्षा की कमी की भरपाई होने की उम्मीद कम है। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वर्षा की स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कमजोर मानसून का असर खेती और खाद्य उत्पादन पर न्यूनतम रहे।

बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में पहली गिरफ्तारी

चमोली। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर मचे बवाल के बीच पहली गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस नौटियाल से पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड पुलिस ने बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे और दान के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया।

चमोली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि चमोली पुलिस ने रविवार रात प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया और उन्हें बद्रीनाथ ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।

राम मंदिर चंदा चोरी . सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को भेजा नोटिस, एसआईटी से मांगी रिपोर्ट

मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान की कथित चोरी की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने यूपी स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) को दान चोरी मामले में अपनी जांच की प्रगति पर सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और राज्य की ओर से यह जानकारी दी। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी, जब सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर विचार करेगा। तीन याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने सीबीआई जांच और ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की कैग ऑडिट की मांग की है। अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने भी ऐसी ही याचिका दायर की है। राजद सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर तीसरी याचिका में मंदिर ट्रस्ट के पूरे वित्तीय कामकाज की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है।

राम मंदिर में दान के कथित दुरुपयोग का मामला जून के पहले हफ्ते में चढ़ावे की गिनती के दौरान सामने आया था। ट्रस्ट की सिफ़ारिश पर, यूपी सरकार ने जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया, जिसमें लखनऊ डिविज़नल कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और स्पेशल सेक्रेटरी (फ़ाइनेंस) नील रतन शामिल हैं। एसआईटी को प्रारंभिक गबन के सबूत मिले, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और 8 लोगों की गिरफ़्तारी हुई। एसआईटी के अनुसार, 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज में दान-गिनती के नियमों का लगभग 70 बार उल्लंघन देखा गया, जिससे चोरी की आशंका पुख्ता हुई। जांचकर्ताओं का आरोप है कि आरोपियों ने गिनती हॉल के अंदर कमजोर निगरानी का फायदा उठाया। जांच से पहले कुछ कर्मचारियों से 78.94 लाख और गिनती वाले कमरे से जुड़े बाथरूम से 2.25 लाख बरामद होने की भी सूचना है।

कोलकाता एयरपोर्ट मस्जिद विवाद : शुभेंदु अधिकारी का बयान, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर

कोलकाता,। कोलकाता एयरपोर्ट के भीतर स्थित पुरानी मस्जिद में सामूहिक नमाज़ पर रोक लगाने और उसके प्रस्तावित स्थानांतरण को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान तेज हुआ है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि बताकर अपना रुख साफ किया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धार्मिक स्वतंत्रता का बचाव किया है। सीएम अधिकारी ने विवाद पर टिप्पणी कर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि चीन और बांग्लादेश जैसे संवेदनशील पड़ोसी देशों के करीब स्थित भू-रणनीतिक महत्व के इंस्टॉलेशन (एयरपोर्ट) के गेट बाहरी लोगों के लिए खुले नहीं रखे जा सकते। सीएम अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और एयरपोर्ट की सुरक्षा को अन्य सभी चीजों से ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। वहीं, सीएम सुवेंदु ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया कि उनकी सरकार धार्मिक रीति-रिवाजों में बाधा डालती है। उन्होंने कहा, हमने किसी को भी अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोका है, जैसा कि विपक्ष ने हमारे बारे में कहा था। मुख्यमंत्री सुवेंदु ने उदाहरण देकर बताया कि बकरीद (ईद-उल-अज़्हा) जानवरों की बलि से जुड़े कानूनों का पालन कर मनाई गई और मुहर्रम बिना हथियार लहराए शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिससे कोई समस्या नहीं हुई। मुख्यमंत्री सुवेंदु ने नागरिकों से कानून का पालन करने और धर्म को एक निजी मामले के रूप में देखने का आग्रह किया, ताकि सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहे।

इस बीच, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मस्जिद को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तार और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए कदम ज़रूरी है। मजूमदार ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जबकि उनकी मौजूदा सरकार ऐसी राजनीति में विश्वास नहीं रखती और मस्जिद को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा।

दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद सौगत रॉय ने बांकरा मस्जिद में प्रवेश पर अनिश्चितकालीन रोक और उसके स्थानांतरण के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। ममता के नेता रॉय ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की सहमति के बिना मस्जिद के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं होना चाहिए।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने शनिवार को सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बांकरा मस्जिद (जिसे गौरीपुर जामा मस्जिद भी कहा जाता है) को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद मस्जिद में मरम्मत कार्य के चलते तीन दिनों के लिए नमाज़ रोक दी गई है। माना जाता है कि 130 साल से भी ज़्यादा पुरानी यह मस्जिद एयरपोर्ट के निर्माण से भी पहले से मौजूद है और यह एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से करीब 165 मीटर की दूरी पर स्थित है।

चुनावी हलफनामे में प्रशांत किशोर ने घोषित की 198 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति, जन सुराज को 85 करोड़ का चंदा

नई दिल्ली। बिहार की राजनीति में सक्रिय जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनावी नामांकन के साथ दाखिल किए गए अपने हलफनामे में पहली बार अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक किया है। हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी जाह्नवी दास की कुल संपत्ति 198 करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें प्रशांत किशोर के पास लगभग 96 करोड़ रुपये, जबकि उनकी पत्नी जाह्नवी दास के पास करीब 112 करोड़ रुपये की संपत्ति है। हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर के पास करीब 22.19 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और लगभग 73 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। वहीं जाह्नवी दास के पास लगभग 89 करोड़ रुपये की चल और करीब 12 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज की गई है। उन्होंने बैंक से 5.77 करोड़ रुपये का ऋण भी लिया हुआ है। संपत्तियों में गुवाहाटी, नोएडा, गाजियाबाद, पटना, दिल्ली और बक्सर सहित कई स्थानों पर फ्लैट, प्लॉट और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं। हलफनामे में यह भी बताया गया है कि प्रशांत किशोर की कंपनी वेधा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 में जन सुराज को 85 करोड़ रुपये का चंदा दिया। इसके अलावा जन सुराज फाउंडेशन को 50 लाख रुपये और जॉय ऑफ गिविंग संस्था को 2.75 करोड़ रुपये का योगदान भी दिया गया। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि यह केवल उनका नामांकन नहीं, बल्कि बिहार के बेहतर भविष्य और राजनीतिक बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है।

अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, 7 लोगों की मौत

लगातार बारिश से 97 हजार से अधिक लोग प्रभावित, कई जिले देश के बाकी हिस्सों से कटे

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और उसके कारण आई बाढ़ तथा भूस्खलन ने व्यापक तबाही मचाई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, आपदा में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राज्य के सभी 26 जिलों में 97 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कई स्थानों पर सड़कें, पुल, स्कूल और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे अनेक क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है।

सबसे अधिक प्रभावित कुरुंग कुमे जिला रहा, जहां कुमे नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के बाद अचानक आई बाढ़ ने पारसी-पारलो सर्कल और दामिन उपखंड में भारी तबाही मचाई। बाढ़ के तेज बहाव में हुरी और दामिन को जोड़ने वाला पुल बह गया, जिससे पूरे क्षेत्र का सड़क संपर्क बाधित हो गया। पारसी-पारलो क्षेत्र में निरीक्षण भवन में पानी भर गया, दो मकानों और एक चर्च को आंशिक नुकसान पहुंचा तथा पागम गांव को जोड़ने वाला पुल भी बह गया।

बाढ़ का असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है। क्षेत्र के प्रमुख शिक्षण संस्थान सेंट थॉमस स्कूल का पूरा परिसर जलमग्न हो गया, जिससे कक्षाओं, भवनों, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों के आवासों को भारी क्षति पहुंची है। प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित कर दी हैं।

राज्य के अन्य जिलों में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। पक्के केसांग जिले के पाकड़ो गांव के पास बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-13 बंद हो गया है। अधिकारियों के अनुसार, सड़क को दोबारा चालू करने में दो से तीन दिन लग सकते हैं। पश्चिम कामेंग जिले में सेला टनल की ओर जाने वाली सड़क का एक हिस्सा बह गया है, जबकि पापुम पारे जिले में शिव मंदिर के पास भूस्खलन से पोटिन-किमिन मार्ग भी बंद हो गया है।

जिला प्रशासन, पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और अन्य एजेंसियां राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आवश्यक मरम्मत कार्य की योजना बनाई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा मौसम और यातायात संबंधी आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की है।

सुप्रीम कोर्ट में छलका सहारा निवेशक का दर्द, महिला बोली- पति की मौत हो गई, अब तो हमारी जमा पूंजी दिला दीजिए

नई दिल्ली। सहारा समूह में वर्षों पहले निवेश करने वाले लाखों लोगों की उम्मीदें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में लगी रहीं। सुनवाई के दौरान एक महिला निवेशक भावुक हो गई और अदालत से हाथ जोड़कर अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने की गुहार लगाई। महिला ने कहा कि उसके पति का निधन हो चुका है और परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसने अदालत से कहा कि जीवनभर की बचत सहारा में फंसी हुई है, अब न्याय दिलाया जाए। महिला की भावुक अपील सुनकर अदालत ने उसकी बात सुनी और कहा कि ऐसे मामलों में निवेशकों की परेशानी को समझा जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सहारा से जुड़े मामलों और निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया पर पहले से सुनवाई चल रही है तथा इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सहारा प्रकरण लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में है। वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दो कंपनियों को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था। इसके बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा राशि से पात्र निवेशकों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन बड़ी संख्या में निवेशक अब भी अपनी रकम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा सुनवाई के दौरान अदालत के सामने निवेशकों की परेशानियां फिर प्रमुखता से सामने आईं। अदालत ने संकेत दिया कि लंबित मामलों के साथ निवेशकों के हितों पर भी विचार किया जाएगा।

डायलिसिस के बहाने 50 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप

वाराणसी। वाराणसी में एक सेवानिवृत्त शिक्षक की करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन कथित रूप से धोखाधड़ी कर हड़पने के मामले में अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। न्यायालय के निर्देश पर भाजपा के एक जिला पदाधिकारी, उप निबंधक, कार्यालय कर्मी सहित 10 लोगों के खिलाफ रोहनिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में आरोप है कि डायलिसिस और आयुष्मान कार्ड बनवाने का झांसा देकर पूरी साजिश को अंजाम दिया गया।

दरअसल रोहनिया थाना क्षेत्र निवासी प्रमिला मिश्र ने अदालत में दायर प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उनके पति, सेवानिवृत्त शिक्षक ओम प्रकाश मिश्र, जो लंबे समय से डायलिसिस पर हैं, उनकी बीमारी का फायदा उठाकर आरोपियों ने राजातालाब मुख्य मार्ग स्थित लगभग 60 बिस्वा भूमि का फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया। अदालत ने प्रस्तुत दस्तावेजों और आरोपों को प्रथम दृष्टया संज्ञान योग्य मानते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश के बाद भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, उप निबंधक अनिल कुमार, कार्यालय के लिपिक, शिकायतकर्ता के भतीजे विशाल मिश्रा, चालक रवि उपाध्याय सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने पहले इलाज में होने वाले खर्च का हवाला देकर आयुष्मान कार्ड बनवाने का प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ओम प्रकाश मिश्र के नाम से नया मोबाइल नंबर और बैंक खाता खुलवाया गया तथा उस नंबर को उनके पेंशन खाते से जोड़ दिया गया। आरोप है कि इसके बाद खाते का उपयोग उनकी जानकारी के बिना किया जाने लगा। परिजनों का आरोप है कि 30 मार्च को मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 7 अप्रैल को डायलिसिस के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डायलिसिस के बाद जब उनकी स्थिति सामान्य नहीं थी, तब उन्हें सीधे उप निबंधक कार्यालय ले जाकर कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए और जमीन का बैनामा कर दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ दिनों बाद ओम प्रकाश मिश्र ने आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी मांगी।

चढ़ावा चोरी पर संतोष दुबे ने एसआईटी को सौंपे दस्तावेज

अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच एसआईटी कर रही है। चढ़ावा चोरी मामले में श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव समेत आठ आरोपी जेल में हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी मनी ट्रेल खंगाल रही है, वहीं अब पूर्व कारसेवक संतोष दुबे ने भी सोमवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कुछ नए साक्ष्य सौंपे हैं। संतोष दुबे सोमवार को अयोध्या के सीओ कार्यालय पहुंचे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सबूत सौंपे। संतोष दुबे ने कहा कि इन सबूतों के बाद चंदा चोरों की मुसीबतें बढने़ वाली हैं। संतोष दुबे ने कहा कि एक दिन पहले एसआईटी ने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चंदा चोरी को लेकर पूछताछ की थी। उन्होंने कहा कि एसआईटी उनके बयानों और सबूतों को भी जांच में शामिल कर रही है। पूर्व कारसेवक संतोष दुबे ने एक कागज दिखाते हुए दावा किया है कि एसआईटी ने उनसे सभी सबूत सीओ कार्यालय पहुंचकर सौंपने को कहा था। इसलिए ही वह सबूत सौंपने सीओ कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सीओ कार्यालय से यह सबूत एसआईटी तक पहुंचाए जाएंगे। संतोष दुबे ने कहा कि मुझे अभी तक भरोसा नहीं था, लेकिन एसआईटी के अधिकारियों से एक दिन पहले हुई बातचीत में समझ आया कि जांच सही दिशा में है। उन्होंने दावा किया कि कई बड़े नाम भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। कोई नहीं बचेगा। संतोष दुबे ने सीएम योगी को बधाई भी दी। गौरतलब है कि इस मामले में टिन्नू यादव के साथ ही अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा समेत अन्य आरोपियों से अयोध्या पुलिस लगाता पूछताछ कर रही है।

नोएडा भूमि मुआवजा घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी भंग कर जांच विजिलेंस को सौंपी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के बहुचर्चित भूमि मुआवजा घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को हटाकर मामला उत्तरप्रदेश राज्य विजिलेंस ब्यूरो को सौंपा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने यूपी सरकार की दलीलों को स्वीकार कर विजिलेंस ब्यूरो को अधिकतम तीन महीने में पूरी जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। निर्णय जांच में तेजी लाने और भ्रष्टाचार निवारण मामलों में विशेषज्ञता वाली एजेंसी को कार्यभार सौंपने के उद्देश्य से लिया गया है।

यह घोटाला नोएडा प्राधिकरण द्वारा जमीन अधिग्रहण के दौरान नियमों की अनदेखी कर कुछ चुनिंदा जमीन मालिकों और किसानों को अधिकारियों के साथ मिलीभगत से करोड़ों रुपये का अतिरिक्त व गैरकानूनी मुआवजा जारी करने से जुड़ा है। आरोप है कि खेल में एक संगठित नेटवर्क के जरिए करीब 10 प्रतिशत तक नकद कमीशन लिया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसके आधार पर अब तक छह एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं।

उत्तरप्रदेश सरकार ने अदालत को बताया कि इन छह एफआईआर में से तीन अधिकारियों और जमीन मालिकों की कथित सांठगागांठ से संबंधित हैं, जबकि बाकी तीन आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं। राज्य की मांग पर, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भंग कर सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज तत्काल विजिलेंस विभाग को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने जांच में तेजी लाने और विजिलेंस ब्यूरो को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान उन किसानों और जमीन मालिकों को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा को बरकरार रखा है, जिन्हें पहले यह राहत मिली थी। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने इस चरण में मामले के मूल गुण-दोषों (मेरिट्स) पर कोई निश्चित टिप्पणी नहीं की है, और निचली अदालतों को कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से फैसले लेने की आजादी बनी रहेगी। इस आदेश के बाद, भ्रष्टाचार निवारण मामलों में विशेषज्ञ, राज्य विजिलेंस ब्यूरो अब इस महत्वपूर्ण घोटाले की जांच का जिम्मा संभालेगा।

दक्षिण सतपुड़ा
राजनीति | समाज | देशकाल
और गांव कनेक्शन की ख़बरें

पद्मेश न्यूज़
शहर | समाज | गांव

बालाघाट एक्सप्रेस

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

न्यूज गैलेरी

सरकारी जमीन पर खेती रोकने से नाराज़ सास-बहू ने सरपंच को दी जान से मारने की धमकी

सास बहू के खिलाफ अपराध दर्ज

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। बिरसा थाना क्षेत्र के ग्राम अचानकपुर में शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे को लेकर विवाद सामने आया है। कब्जे वाली जमीन पर खेती करने से रोकने पर सास बहू ने ग्राम पंचायत के सरपंच को कथित रूप से अश्लील गालियां दीं, महिला संबंधी झूठे मामले में फंसाने और जान से मारने की धमकी दे डाली। शिकायत पर बिरसा पुलिस ने दसोदा बाई गिरी और उसकी बहू सरस्वती गिरी दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अचानकपुर निवासी विमल तिलासी (45) ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। गांव के शैलगिरी गोस्वामी द्वारा शासकीय भूमि पर कथित रूप से कब्जा कर खेती की जा रही है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में उक्त भूमि को साप्ताहिक बाजार एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया है। साथ ही उस भूमि पर न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त है।बताया गया कि 11 जुलाई की शाम 7 बजे सरपंच विमल तिलासी गांव की एक मेडिकल दुकान में बैठे थे। इसी दौरान शैलगिरी गोस्वामी की पत्नी दसोदा बाई गिरी गोस्वामी और उसकी बहू सरस्वती गिरी गोस्वामी मेडिकल दुकान के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने मेडिकल दुकान सरपंच विमल को अच्छी और वहां पहुंचीं। दोनों सास बहू ने ने सरपंच से पूछा कि उन्होंने पुलिस क्यों बुलवाई थी और उन्हें कब्जे वाली जमीन पर खेती क्यों नहीं करने दी जा रही है। सरपंच द्वारा स्थगन आदेश का हवाला देते हुए कहे आप लोग उस जमीन पर खेती नही कर सकते। खेती नहीं करने की बात कहने पर दोनों महिलाएं आक्रोशित हो गईं और अश्लील गालियां देने लगीं। सरपंच विमल द्वारा गाली देने मना करने पर दोनों सास बहू ने सरपंच को जान से मारने, रास्ते में अकेला मिलने पर निपटा देने तथा झूठे महिला संबंधी प्रकरण में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। घटना के बाद दोनों वहां से चली गईं। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने भी घटनाक्रम देखा।12 जुलाई को सरपंच विमल तिलासी ने बिरसा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दसोदा बाई गिरी गोस्वामी और उसकी बहु सरस्वती गिरी गोस्वामी के विरुद्ध अश्लील गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

12 साल बाद फिर लौटेगा बालाघाट का गौरव, सितंबर से फिर गूंजेगा रेंजर कॉलेज परिसर

सांसद भारती पारधी ने तैयारियों का लिया जायजा, सितंबर से शुरू होगी नई बैच, वर्षों बाद फिर मिलेगा वन अधिकारियों को प्रशिक्षण

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

लगभग 12 वर्षों से बंद पड़ा बालाघाट का ऐतिहासिक रेंजर कॉलेज एक बार फिर अपनी पुरानी पहचान हासिल करने जा रहा है। सितंबर 2026 से यहां पुनः रेंजर प्रशिक्षण की शुरुआत होगी और देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रशिक्षु एक बार फिर बालाघाट में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। लंबे समय से निष्क्रिय पड़े इस प्रतिष्ठित संस्थान के दोबारा शुरू होने से न केवल जिले को उसकी पुरानी पहचान वापस मिलेगी, बल्कि वन प्रशिक्षण के क्षेत्र में बालाघाट का महत्व भी फिर बढ़ेगा। रेंजर कॉलेज के पुनः संचालन से पहले सोमवार को सांसद भारती पारधी ने कॉलेज परिसर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कॉलेज की अधोसंरचना, प्रशिक्षण व्यवस्था, छात्रावास, कक्षाओं, मेस और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक सुधार कार्यों की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान क्लास रूम सभागार में विभागीय अधिकारियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से सांसद को कॉलेज की रूपरेखा, चल रहे मरम्मत कार्य और आगामी प्रशिक्षण सत्र की तैयारियों से अवगत कराया। इसके बाद सांसद ने कॉलेज परिसर का भ्रमण कर विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान सामने आया कि कई स्थानों पर मरम्मत और सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। वहीं मेस भवन का एक हिस्सा पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी मरम्मत भी कराई जा रही है ताकि नई बैच के आने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हो सकें। गौरतलब है कि करीब दो वर्ष पहले रेंजर कॉलेज को जबलपुर स्थानांतरित किए जाने की चर्चाओं ने जिले में चिंता बढ़ा दी थी। बालाघाट की पहचान माने जाने वाले इस संस्थान के स्थानांतरण की खबर सामने आने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने इसका विरोध किया था। उस समय इस मुद्दे पर सांसद भारती पारधी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे, जिसके बाद उन्होंने भोपाल से लेकर दिल्ली तक विभागीय स्तर पर लगातार प्रयास किए। इन्हीं प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है कि रेंजर कॉलेज का स्थानांतरण रुक गया और अब इसे पुनः बालाघाट से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। लंबे अंतराल के बाद सितंबर 2026 से यहां नई बैच का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, जिसके लिए कॉलेज परिसर को फिर से व्यवस्थित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सांसद भारती पारधी ने कहा कि रेंजर कॉलेज केवल एक प्रशिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि बालाघाट की ऐतिहासिक पहचान और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जिले की इस महत्वपूर्ण धरोहर को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए वरिष्ठ नेतृत्व और वन विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिले के विकास और उसकी पहचान को संरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता है। सांसद ने कहा कि रेंजर कॉलेज के पुनः शुरू होने से स्थानीय स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देशभर से आने वाले प्रशिक्षुओं के कारण जिले की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और बालाघाट को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से एक महत्वपूर्ण वन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में पहचान मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण शुरू होने से पहले सभी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह तैयार कर ली जाएं, ताकि प्रशिक्षुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्य वन संरक्षक गौरव ने बताया कि वर्ष 2014 से रेंजर महाविद्यालय की गतिविधियां पूरी तरह बंद थीं। अब शासन के निर्णय के बाद इसे पुनः शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कॉलेज की अधोसंरचना को तेजी से तैयार किया जा रहा है और 30 जुलाई तक नई बैच को बालाघाट भेजने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेज दिया जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि सितंबर से प्रशिक्षण कार्य नियमित रूप से प्रारंभ हो जाए। करीब डेढ़ दशक बाद रेंजर कॉलेज में फिर से प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में जिले के लोगों को उम्मीद है कि बालाघाट एक बार फिर देश के प्रमुख वन प्रशिक्षण केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा और वर्षों से वीरान पड़े इस परिसर में फिर से प्रशिक्षण, अध्ययन और अनुशासन का माहौल दिखाई देगा।

खरपड़िया में 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या- माता-पिता की इकलौती बेटी थी पायल

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम खरपड़िया में सोमवार की सुबह एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका पायल पिता सुरेंद्र देशमुख कक्षा 11वीं की छात्रा थी। और वह माता-पिता की इकलौती बेटी थी जिसका एक बड़ा भाई है। तिरोड़ी पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजनों को सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार घटना 13 जुलाई की सुबह पायल की मां सुशीला बाई खेत में खार खोदने गई थीं। बड़ा भाई रक्षक देशमुख फटाका फैक्ट्री में काम पर चला गया था। पिता सुरेंद्र देशमुख घर के सामने चौपाल पर बैठे थे।सुबह 9:45 बजे पायल अपनी मां के लिए टिफिन लेकर खेत गई और वापस घर लौट आई। करीब 10:30 बजे जब पिता घर के अंदर गए तो उन्होंने बेटी को घर की छपरी में फंदे पर लटका देखा। पिता के चिल्लाने पर पड़ोसी दौड़े और पायल को नीचे उतारे लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।खबर मिलते ही मां और भाई भी घर पहुंच गए।सुशीला बाई की सूचना पर तिरोड़ी थाने से सहायक उप निरीक्षक उमेश दियेवार अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।फिलहाल पायल ने आत्महत्या क्यों की। इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। तिरोड़ी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।

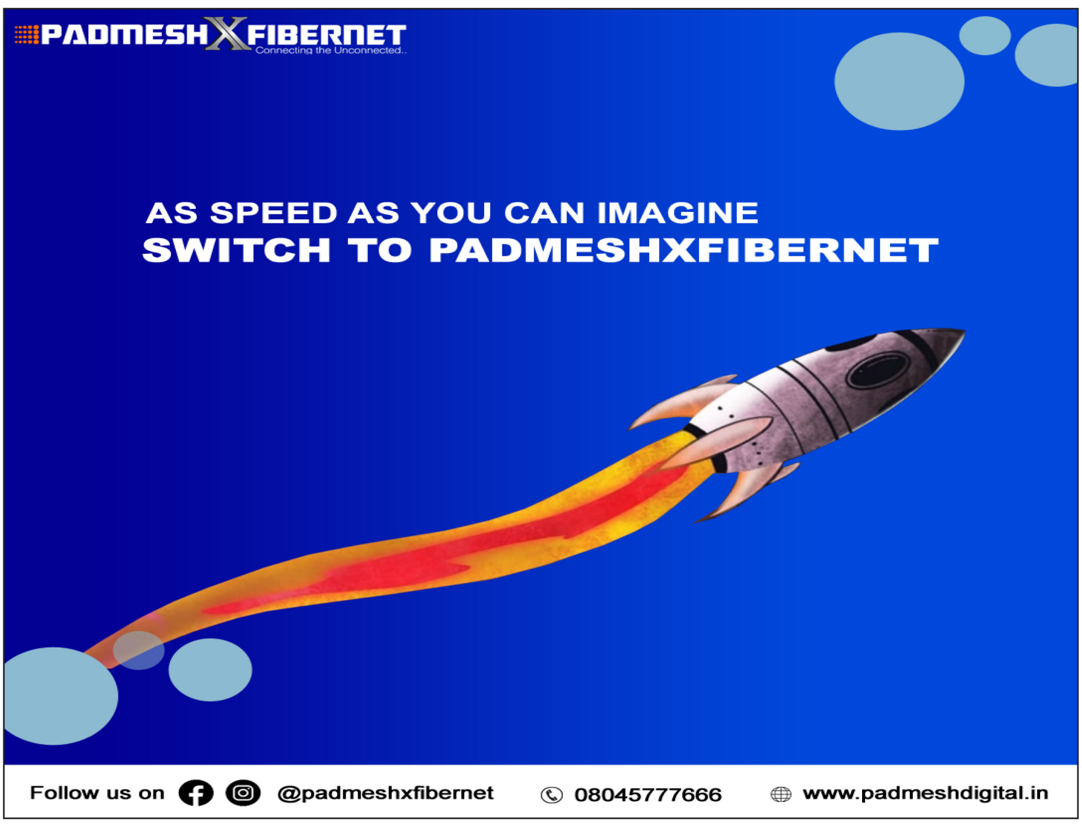

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :**9425138710**, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट